गैर गोपनीय

केस नंबर: एडी (ओआई)- 05/2025

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथी मंजिल, जीवन तारा भवन, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

प्रकटीकरण विवरण

विषय: जनवादी गणराज्य चीन ("चीन पीआर"), यूरोपीय संघ, सऊदी अरब साम्राज्य तथा ताइवान से उत्पन्न या वहाँ से निर्यातित "एथिलीन डायमीन" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी (एंटी-डंपिंग) जांच।

गैर गोपनीय

विषय-सूची

क. मामले की पृष्ठभूमि...4
ख. प्रक्रिया...5
3.1 प्रारंभ...5
3.2 आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण का प्रसारण 6
3.3 संबंधित देशों के निर्यातकों तथा भारत के आयातकों/उपयोगकर्ताओं द्‌वारा भागीदारी 6
3.4 आगे की प्रक्रिया 8
ग. *उत्पाद जिसके संबंध में जांच की जा रही है एवं समान वस्तु*...9
ग.1. अन्य हितबद्‌ध पक्षों (निर्यातकों, आयातकों एवं उपयोगकर्ताओं) द्‌वारा प्रस्तुतियाँ 9
ग.2. आवेदक द्‌वारा प्रस्तुति 10
ग.3. प्राधिकरण द्‌वारा जांच...11
घ. घरेलू उद्‌योग का दायरा और स्टैंडिंग...14
घ.1. विरोधी हितबद्‌ध पक्षों द्‌वारा प्रस्तुतियाँ 14
घ.2. आवेदक द्‌वारा प्रस्तुति 14
घ.3. प्राधिकरण द्‌वारा परीक्षण 15
ङ. गोपनीयता एवं विविध अभ्यावेदन...16
ङ.1. विरोधी हितबद्‌ध पक्षों द्‌वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन...16
ङ.2. आवेदक द्‌वारा प्रस्तुति 17
ङ.3. प्राधिकरण द्‌वारा जांच...18
च. डंपिंग का आकलन तथा सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य एवं डंपिंग मार्जिन का निर्धारण..............19
च.1. अन्य हितबद्‌ध पक्षों द्‌वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन...19
च.2. आवेदक द्‌वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन...20
च.3. प्राधिकरण द्‌वारा जांच...22
च.4. सामान्य मूल्य एवं निर्यात मूल्य का निर्धारण 23
छ. क्षति का आकलन और कारणात्मक संबंध...31
छ.1. अन्य हितबद्‌ध पक्षों द्‌वारा प्रस्तुतियाँ 31
छ.2. आवेदक द्‌वारा प्रस्तुति 35
छ.3. प्राधिकरण द्‌वारा परीक्षण 38
छ.3.1. मांग/प्रत्यक्ष उपभोग का आकलन 41
छ.3.2. डंप किए गए आयात का मात्रात्मक प्रभाव...42
छ.3.3. डंप किए गए आयात का कीमत पर असर...43
छ.3.4. घरेलू उद्‌योग के आर्थिक पैरामीटर...46
छ.3.5. चोट के संबंध में अवलोकन...52
ज. *श्रेय* न देना और कारण-संबंध...53
झ. चोट की गंभीरता का स्तर...54

गैर गोपनीय

ञ. भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे.....56
ञ.1 विरोधी हितधारक पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन.....56
ञ.2 आवेदक द्वारा प्रस्तुति.....57
ञ.3 प्राधिकरण द्वारा जांच.....58
ट. प्रकटीकरण-पश्चात् टिप्पणियाँ.....61
ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुतियाँ.....61
ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ.....65
ट.3 प्राधिकरण द्वारा परीक्षण.....67
ठ. निष्कर्ष.....72
ड. सिफारिशें.....74
ढ. आगे की प्रक्रिया.....77

गैर गोपनीय

फा. सं. 6/05/2025-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथी मंजिल, जीवन तारा भवन, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: .06.2026

<u>प्रकटीकरण विवरण</u>
<u>केस नंबर: एडी (ओआई)- 05/2025</u>

विषय: जनवादी गणराज्य चीन ("चीन पीआर"), यूरोपीय संघ, सऊदी अरब साम्राज्य तथा ताइवान से उत्पन्न या वहाँ से निर्यातित "एथिलीन डायमीन" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी (एंटी-डंपिंग) जांच।

<u>सामान्य प्रकटीकरण</u>

फा. सं. 6/05/2025-डीजीटीआर - समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (डंपित वस्तुओं पर प्रतिप्रतिषेध शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे आगे "प्रतिप्रतिषेध नियम" अथवा "नियम" कहा गया है) को दृष्टिगत रखते हुए, ...।

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

1. बालाजी स्पेशियलिटी केमिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" कहा गया है) ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा प्रतिप्रतिषेध नियमों के अनुसार, एथिलीन डायमाइन (जिसे आगे "विचारणाधीन उत्पाद", "संबंधित वस्तु" अथवा "ईडीए" कहा गया है) के चीन जनवादी गणराज्य (चीन पीआर), यूरोपीय संघ, सऊदी अरब साम्राज्य तथा ताइवान (जिन्हें आगे "संबंधित देश" कहा गया है) से होने वाले आयातों के संबंध में प्रतिप्रतिषेध जांच प्रारंभ किए जाने हेतु नामित प्राधिकरण (जिसे आगे "प्राधिकरण" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया।

2. और जबकि, आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत् प्रमाणित आवेदन के आधार पर, प्राधिकरण ने अधिसूचना फा. सं. 6/05/2025-डीजीटीआर दिनांक 25 मार्च, 2025 के माध्यम से, जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, प्रतिप्रतिषेध नियमों के नियम 5 के अनुसार चीन पीआर, यूरोपीय संघ, सऊदी अरब तथा ताइवान से विचारणाधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में प्रतिप्रतिषेध जांच प्रारंभ की। इसका उद्देश्य विचारणाधीन उत्पाद के कथित डंपिंग के अस्तित्व, मात्रा एवं प्रभाव का निर्धारण करना तथा ऐसे प्रतिप्रतिषेध शुल्क की मात्रा की सिफारिश करना था, जिसे यदि अधिरोपित किया जाए, तो वह घरेलू उद्योग को हुई कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हो।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

3. जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

3.1 प्रारंभ

i. नियम 5(5) के अनुसार, प्राधिकरण ने जांच प्रारंभ करने की कार्यवाही से पूर्व वर्तमान प्रतिप्रतिषेध आवेदन की प्राप्ति के संबंध में भारत स्थित संबंधित देशों के दूतावासों को सूचित किया।

ii. आवेदन की जांच करने पर प्राधिकरण को डंपिंग तथा उससे उत्पन्न क्षति के प्रथमदृष्टया साक्ष्य प्राप्त हुए। अतः, नियम 5 एवं 6 के अनुसार, अधिसूचना फा. सं. 6/05/2025-डीजीटीआर दिनांक 25 मार्च, 2025 के माध्यम से प्राधिकरण ने वर्तमान जांच कार्यवाही प्रारंभ की।

iii. जांच अवधि (जांच की अवधि- पी ओ आई) को 1 अक्टूबर, 2023 से 30 सितंबर, 2024 (12 माह) तक माना गया। क्षति अवधि (Injury Period) के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022, 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023, 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तथा जांच अवधि को शामिल किया गया।

iv. प्राधिकरण ने क्षति अवधि के लिए विचारणाधीन उत्पाद के लेन-देन-वार आयात आंकड़े प्राप्त करने हेतु प्रणाली एवं डेटा प्रबंधन महानिदेशालय (डीजी सिस्टम्स) से अनुरोध किया। प्राधिकरण को उक्त आंकड़े प्राप्त हुए तथा लेन-देन का विधिवत परीक्षण करने के पश्चात आवश्यक विश्लेषण के लिए इन आंकड़ों पर भरोसा किया गया।

3.2 आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण का प्रसारण

v. नियम 6(2) के अनुसार, प्राधिकरण ने आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर भारत में संबंधित देशों के दूतावासों, संबंधित देशों में विचारणाधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादकों एवं निर्यातकों, भारत में संबंधित वस्तु के ज्ञात आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षों को जांच प्रारंभ करने संबंधी अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराकर उन्हें जांच प्रारंभ होने की सूचना दी।

vi. नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकरण ने भारत में स्थित संबंधित देशों के दूतावासों के माध्यम से उन देशों की सरकारों, संबंधित आयातों के ज्ञात निर्यातकों तथा आवेदन की प्रति लिखित रूप में मांगने वाले अन्य हितबद्ध पक्षों को आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण की एक प्रति उपलब्ध कराई।

vii. प्राधिकरण ने भारत में स्थित संबंधित देशों के दूतावासों के माध्यम से उन देशों की सरकारों को प्रश्नावली प्रेषित की। संबंधित देशों की सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे अपने देश में विचारणाधीन उत्पाद के उत्पादकों को जांच प्रारंभ करने संबंधी अधिसूचना तथा प्रश्नावली अग्रेषित करें और उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने की सलाह दें।

viii. प्राधिकरण ने नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी प्राप्त करने हेतु संबंधित वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली प्रेषित की।

ix. प्राधिकरण ने नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी प्राप्त करने हेतु भारत में संबंधित वस्तु के ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्ताओं को आयातक प्रश्नावली प्रेषित की।

3.3 संबंधित देशों के निर्यातकों तथा भारत के आयातकों/उपयोगकर्ताओं द्वारा भागीदारी

x. निम्नलिखित उत्पादकों एवं निर्यातकों ने वर्तमान जांच में स्वयं को हितबद्ध पक्ष के रूप में पंजीकृत कराया है :

क्र. सं.	**हितबद्ध पक्ष का नाम**
क.	मेसर्स बीएएसएफ एंटवर्पेन एनवी, बेल्जियम
ख.	मेसर्स बीएएसएफ ईओओडी, बुल्गारिया
ग.	मेसर्स बीएएसएफ एस्पानोला एसएलयू, स्पेन
घ.	मेसर्स बीएएसएफ फ्रांस एस.ए.एस., फ्रांस
ङ.	मेसर्स बीएएसएफ हांगकांग लिमिटेड., हांगकांग
च.	मेसर्स बीएएसएफ हंगारिया केएफटी., हंगरी
छ.	मेसर्स बीएएसएफ-वाईपीसी कंपनी लिमिटेड, चीन पीआर
ज.	मेसर्स बीएएसएफ आयरलैंड डीएसी, आयरलैंड
झ.	मेसर्स बीएएसएफ इटालिया एस.पी.ए., इटली
ञ.	मेसर्स बीएएसएफ नेदरलैंड बी.वी.., नीदरलैंड
ट.	मेसर्स बीएएसएफ एसई, जर्मनी
ठ.	मेसर्स बीएएसएफ स्पोल एस.आर.ओ.., चेक गणराज्य
ड.	मेसर्स बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड

ढ.	मेसर्स डॉव केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड, दुबई शाखा, यूएई
ण.	मेसर्स डॉव सऊदी अरब प्रोडक्ट मार्केटिंग अरेबिया बी.वी., दुबई शाखा, यूएई
त.	मेसर्स डॉव केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड., दुबई शाखा, यूएई
थ.	मेसर्स सदारा केमिकल कंपनी, सऊदी अरब साम्राज्य
द.	बीएएसएफ बेल्जियम कोऑर्डिनेशन सेंटर, बेल्जियम
ध.	बीएएसएफ ओय, फिनलैंड
न.	बीएएसएफ एसआरएल, रोमानिया

xi. विषय जांच की प्रारंभिक सूचना के प्रत्युत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/उपयोगकर्ताओं ने स्वयं को इस जांच में हितबद्ध पक्ष के रूप में पंजीकृत कराया है।

क्र. सं.	**हितबद्ध पक्ष का नाम**
क.	मेसर्स कार्डोलाइट स्पेशल्टी केमिकल्स इंडिया एलएलपी
ख.	मेसर्स कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड (सी आई एल)
ग.	मेसर्स डॉव केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (डीसीआईपीएल)
घ.	मेसर्स इंडोरामा इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
ङ.	मेसर्स ह्योसंग इंडिया प्रा. लि.
च.	मेसर्स इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

xii. प्राधिकरण ने व्यापक अर्थव्यवस्था पर शुल्कों के प्रभाव एवं जनहित का आकलन करने के लिए एक आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। ईआईक्यू की एक प्रति संबंधित देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों एवं उपयोगकर्ताओं तथा आवेदक को भेजी गई। ईआईक्यू को प्रशासनिक लाइन मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया। निम्नलिखित हितबद्ध पक्षों ने अपने अभ्यावेदन/प्रस्तुतियाँ दाखिल की हैं:

क्र. सं.	**हितबद्ध पक्ष का नाम**
क.	बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड
ख.	कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड
ग.	कार्डोलाइट स्पेशल्टी केमिकल्स इंडिया एलएलपी

xiii. निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्वयं को पंजीकृत कराने वाले सभी हितबद्ध पक्षों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी। सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षों को यह निर्देश दिया गया कि वे वर्तमान कार्यवाही में अपने द्वारा दायर सभी अभ्यावेदनों के गैर-गोपनीय संस्करण को अन्य सभी हितबद्ध पक्षों के साथ परस्पर रूप से साझा (प्रसारित) करें।

3.4 आगे की प्रक्रियाएँ

xiv. नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकरण ने हितबद्ध पक्षों को 7 अक्टूबर 2025 को आयोजित एक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। तत्पश्चात, नामित प्राधिकरण में परिवर्तन के कारण 18 दिसंबर 2025 को एक अन्य मौखिक सुनवाई आयोजित की गई। दोनों मौखिक सुनवाइयों में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षों को निर्देश दिया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करें तथा उसके पश्चात प्रत्युत्तर (rejoinder) प्रस्तुत करें। प्राधिकरण की स्वीकृत प्रथा के अनुसार, पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तरों के गैर-गोपनीय संस्करणों का परस्पर वितरण (प्रसार) नहीं किया गया।

xv. नियम 6(8) के अनुसार, जहाँ किसी हितबद्ध पक्ष ने वर्तमान कार्यवाही के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुँच से इनकार किया है या समय पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा उत्पन्न की है, ऐसे पक्षों को प्राधिकरण द्वारा असहयोगी (असहयोगी) माना गया है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष अभिलिखित किए गए हैं।

xvi. नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना का प्राधिकरण द्वारा गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में परीक्षण किया गया। संतुष्ट होने पर, प्राधिकरण ने जहाँ आवश्यक समझा, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया और ऐसी जानकारी को गोपनीय मानते हुए अन्य हितबद्ध पक्षों को प्रकट नहीं किया गया। जहाँ संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षों को यह निर्देश दिया गया कि वे प्रस्तुत की गई गोपनीय सूचना का एक गैर-गोपनीय सारांश भी उपलब्ध कराएँ।

xvii. नियम 8 के अनुसार, प्राधिकरण ने वर्तमान कार्यवाही के लिए आवश्यक समझे जाने तक आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का सत्यापन (सत्यापन) किया। प्राधिकरण ने इस मामले में अपने विश्लेषण हेतु हितबद्ध पक्षों के सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया है।

xviii. प्राधिकरण ने यह निर्धारित करने के लिए कि क्या डंपिंग मार्जिन से कम शुल्क भी आवेदक को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त होगा, संबंधित उत्पाद के लिए गैर-हानिकारक मूल्य (गैर-हानिकारक मूल्य) की गणना की। एन आई पी की गणना भारत में घरेलू समान वस्तु के उत्पादन एवं बिक्री की इष्टतम लागत तथा उत्पादन लागत के आधार पर, आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) को ध्यान में रखते हुए की गई है।

xix. प्राधिकरण ने अंतिम निष्कर्ष निकालते समय कार्यवाही के दौरान हितबद्ध पक्षों द्वारा उठाए गए मुद्दों, प्रस्तुत की गई सूचनाओं तथा दिए गए अभ्यावेदनों का, जहाँ तक वे साक्ष्य द्वारा समर्थित थे और वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक थे, परीक्षण किया।

गैर गोपनीय

xx. '***' उन सूचनाओं को दर्शाता है जो किसी पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई हैं और जिन्हें प्राधिकरण द्वारा नियमों के अंतर्गत गोपनीय माना गया है।

xxi. प्राधिकरण द्वारा विषय जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 84.27 है।

ग. <u>उत्पाद जिसके संबंध में जांच की जा रही है एवं समान वस्तु</u>

ग.1 अन्य <u>इच्छुक पक्षों (निर्यातकों, आयातकों और उपयोगकर्ताओं) द्वारा प्रस्तुतियाँ</u>

4. अन्य हितबद्ध पक्षों ने उत्पाद जिसके संबंध में जांच की जा रही है तथा समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं।

i. इंडोरामा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने यह प्रस्तुत किया है कि आवेदक स्पैन्डेक्स यार्न के उत्पादन में प्रयुक्त एथिलीन डायमीन का उत्पादन नहीं करता है, और इसलिए उस सीमा तक उत्पाद जिसके संबंध में जांच की जा रही है, के दायरे से उपयोगकर्ता-आधारित छूट (उपयोगकर्ता-आधारित छूट) प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

ii. इंडोरामा को स्पैन्डेक्स यार्न के उत्पादन के लिए उच्च शुद्धता वाले एथिलीन डायएमीन की आवश्यकता होती है, जहाँ थोड़ी सी भी अशुद्धियाँ उत्पाद के प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं। एथिलीन डायएमीन को शुद्धता और जल सामग्री के सटीक विनिर्देशों को पूरा करना आवश्यक है।

iii. कई बार बातचीत और टेस्टिंग के बावजूद, आवेदक इन स्पेसिफिकेशन्स को पूरा करने वाला ईडीए सप्लाई नहीं कर पाया है। बालाजी ने अपनी जमा की गई टेस्ट रिपोर्ट्स में माना कि वे दूसरे पैरामीटर्स को तो पूरा कर सकते थे, लेकिन उनके ईडीए में पानी की मात्रा 0.28% थी, जो इंडोरामा की ज़रूरी सीमा से ज़्यादा थी।

iv. ह्योसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न के निर्माण के लिए विचाराधीन उत्पाद को दायरे से बाहर रखने का अनुरोध किया है। उनका तर्क है कि इससे इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न बनाने वालों की निर्यात मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होगी।

v. थॉरिटी ने पहले चीन पीआर और तुर्की से आने वाले डाइमिथाइलएसीटामाइड (डीएमएसी) की मिड-टर्म समीक्षा (14.10.2020) में स्पैन्डेक्स बनाने वालों के लिए इसी तरह की खास कच्चे माल की ज़रूरतों को माना था, जहाँ असल इस्तेमाल करने वालों की ज़रूरतों के आधार पर कुछ उत्पादों को छूट दी गई थी।

vi. डीजीटीआर ने असली यूज़र्स के लिए छूट देने की अनुमति भी नियमित रूप से दी है, जैसे कि "स्टेनलेस स्टील 300 और 400 सीरीज़ के कोल्ड रोल्ड फ़्लैट प्रोडक्ट्स" के

मामले में 29.09.2025 की शुरुआत की सूचना में, जहाँ कुछ खास कामों के लिए कुछ चौड़ाई वाले प्रोडक्ट्स को छूट दी गई थी।

vii. अगर आवेदक इस छूट को न मानने का अनुरोध करता है, तो अथॉरिटी उनसे एक अंडरटेकिंग (लिखित वचन) मांग सकती है जिसमें वे यह पुष्टि करें कि वे ज़रूरी स्पेसिफिकेशन वाला एथिलीन डाई-अमाइन सप्लाई कर सकते हैं। अगर वे ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं, तो अथॉरिटी को संबंधित ट्रेड नोटिस के तहत एक साल की 'कूलिंग-ऑफ अवधि' को हटा देना चाहिए ताकि बिना किसी रोक-टोक के इंपोर्ट किया जा सके।

ग.2 <u>आवेदक द्वारा प्रस्तुति</u>

5. आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित बातें कही हैं:

i. विचाराधीन उत्पाद 'एथिलीन डायमाइन' है और इसे 'ईडीए' के नाम से भी जाना जाता है।

ii. जिस प्रोडक्ट की बात हो रही है, वह एक ऐसा केमिकल है जिसमें दो रिएक्टिव अमीन ग्रुप होते हैं, जो इसे कई तरह की इंडस्ट्रियल प्रक्रियाओं में एक ज़रूरी इंग्रीडिएंट बनाते हैं। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से स्पेशलिटी कंपाउंड, फंगीसाइड, एग्रोकेमिकल, कोटिंग और पॉलीमर जैसे केमिकल बनाने में किया जाता है। इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल एग्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल जैसे उद्योगों में बड़े पैमाने पर किया जाता है।

iii. आवेदक द्वारा बनाए गए समान उत्पाद और आयातित उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है।

iv. चीन पी आर और तुर्की से डाइमिथाइलएसीटामाइड (डीएमएसी) और स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर एंटी-डंपिंग जांच के संबंध में अन्य इच्छुक पार्टियों का भरोसा गलत है। दोनों मामलों में, प्रोडक्ट को बाहर रखने की छूट केवल तभी दी गई थी जब यूज़र्स ने टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के साथ, फंक्शनल रूप से एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल न हो पाने (कार्यात्मक रूप से प्रतिस्थापन-अक्षमता) का स्पष्ट, वेरिफ़ाई करने योग्य और साबित करने योग्य सबूत दिया हो। मौजूदा मामले में ऐसा कोई सबूत नहीं है।

v. स बात पर कि आवेदक तय स्पेसिफिकेशन के आधार पर प्रोडक्ट सप्लाई नहीं कर पा रहा है, घरेलू इंडस्ट्री ने कहा है कि यूज़र्स जिन स्पेसिफिकेशन शीट का हवाला दे रहे हैं, वे पुरानी हो चुकी हैं। घरेलू इंडस्ट्री ने 2020-21 के बाद टेक्निकल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए काफी रिसर्च और डेवलपमेंट का काम किया है, और अब स्पैन्डेक्स बनाने वाली दूसरी कंपनियों को हाई प्योरिटी वाला एथिलीन डाई-अमाइन सप्लाई किया जा रहा है। एचपीएलसी (हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी) टेस्ट रिपोर्ट पर भरोसा करने के मामले में, घरेलू इंडस्ट्री ने कहा है कि यूज़र्स जिन

एचपीएलसी टेस्ट रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, उन्हें कभी भी घरेलू इंडस्ट्री के साथ शेयर नहीं किया गया, जबकि इसकी मांग की गई थी।

vi. यूज़र-बेस्ड एक्सक्लूज़न (उपयोगकर्ता-आधारित छूट) के अनुरोध पर यह कहा गया है कि ऐसा अनुरोध उचित नहीं है, क्योंकि अगर इंडोरामा ऑर्डर दे, तो घरेलू उद्योग ज़रूरतों को पूरा करने वाला ईडीए बनाने और सप्लाई करने में सक्षम है। घरेलू उद्योग अन्य स्पैन्डेक्स यूज़र्स को भी यह प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है।

vii. स्पेसिफिकेशन्स की तुलना से पता चलेगा कि घरेलू इंडस्ट्री का प्रोडक्ट सभी ज़रूरी पैरामीटर्स को पूरा करता है। इसके अलावा, उसी प्लांट का इस्तेमाल करके और बिना किसी अतिरिक्त मशीनरी के, कस्टमर की ज़रूरतों के हिसाब से स्पेसिफिकेशन्स में बदलाव किया जा सकता है। अगर ज़रूरत पड़ी, तो घरेलू इंडस्ट्री अथॉरिटी को अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार है।

ग.3 <u>प्राधिकरण द्वारा जांच</u>

6. शुरुआत के चरण में, विचाराधीन उत्पाद को इस प्रकार परिभाषित किया गया था:

"3. इस जांच में जिस प्रोडक्ट (पीयूसी) पर विचार किया जा रहा है, वह 'एथिलीन डायमाइन' है, जिसे शॉर्ट में "ईडीए" कहा जाता है। यह प्रोडक्ट एक साफ़, रंगहीन लिक्विड है। इसका फ्रीज़िंग पॉइंट 11°C और बॉइलिंग पॉइंट 117°C है।"

ईडीए एक ऐसा केमिकल है जिसमें दो रिएक्टिव अमीन ग्रुप होते हैं, जो इसे कई तरह की इंडस्ट्रियल प्रक्रियाओं में एक ज़रूरी चीज़ बनाते हैं। ईडीए का इस्तेमाल मुख्य रूप से स्पेशल कंपाउंड, फंगीसाइड, एग्रोकेमिकल, कोटिंग और पॉलीमर जैसे केमिकल बनाने में किया जाता है। इसके अलावा, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल एग्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल जैसे उद्योगों में बड़े पैमाने पर किया जाता है।

ईडीए को कस्टम्स टैरिफ एक्ट, 1975 के तहत चैप्टर 29, यानी "ऑर्गेनिक केमिकल्स" में, टैरिफ क्लासिफिकेशन के सब-हेडिंग 2921 21 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। आवेदक ने बताया है कि ईडीए को एच एस कोड 2921 21 00 के तहत आयात किया जाता है। कस्टम्स क्लासिफिकेशन केवल संकेत देने वाला है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

7. स्पैन्डेक्स यार्न के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले एथिलीन डायमाइन को बाहर रखने के मामले में, घरेलू इंडस्ट्री ने कहा है कि उसने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए काफी रिसर्च और डेवलपमेंट किया है। घरेलू इंडस्ट्री ने माना है कि भले ही वह पहले

स्पेसिफिकेशन पूरे नहीं कर पाती थी, लेकिन अब वह डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट सप्लाई कर सकती है। घरेलू इंडस्ट्री ने यह भी बताया है कि उसने दूसरे स्पैन्डेक्स प्रोड्यूसर्स को *ईडीए* सप्लाई किया है, और प्रोडक्ट यूज़र इंडस्ट्री की सभी टेक्निकल ज़रूरतों को पूरा करता है। कस्टमर की ज़रूरतों के आधार पर प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन में बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए किसी नई मशीन की ज़रूरत नहीं है, और पूरी प्रोसेस उसी प्लांट में की जा सकती है। घरेलू इंडस्ट्री ने टेक्निकल एनालिसिस सर्टिफिकेट भी दिया है, जिससे पता चलता है कि वह ज़रूरी स्पेसिफिकेशन वाला घरेलू प्रोडक्ट दे सकती है। सिर्फ़ एक टेक्निकल पैरामीटर में अंतर होने से यह साबित नहीं होता कि दोनों प्रोडक्ट एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, खासकर तब जब घरेलू इंडस्ट्री ने खुद स्पैन्डेक्स के दूसरे प्रोड्यूसर्स को यह प्रोडक्ट बेचा हो। इच्छुक पार्टियों का इसे बाहर रखने का दावा पूरी तरह से पानी सोखने की क्षमता पानी सोखना) पर आधारित है। हालाँकि, अथॉरिटी का मानना है कि घरेलू इंडस्ट्री ने इस बात के पर्याप्त सबूत दिए हैं कि वह ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जिसका इस्तेमाल स्पैन्डेक्स यार्न बनाने में किया जा सकता है और घरेलू इंडस्ट्री द्वारा सप्लाई किया गया प्रोडक्ट इम्पोर्ट किए गए प्रोडक्ट जैसा ही है। इसे देखते हुए, एंड-यूज़र के आधार पर कोई छूट देना भी सही नहीं लगता।

8. ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, अथॉरिटी जांच शुरू होने के समय तय किए गए प्रोडक्ट के दायरे को ही पक्का रखती है, जिसे नीचे दिया गया है।
इस जांच में जिस प्रोडक्ट पर विचार किया जा रहा है, वह 'एथिलीन डायमाइन' है, जिसे *'ईडीए'* के नाम से भी जाना जाता है।

9. जिस प्रोडक्ट की बात हो रही है, उसे बनाने की प्रक्रिया में मोनो इथेनॉलमाइन और अमोनिया की प्रतिक्रिया (रिएक्शन) शामिल है। यह प्रतिक्रिया हाइड्रोजन के माहौल में, एक कैटलिस्ट की मौजूदगी में, लगभग 150 से 200 किग्रा/सेमी^{2} के दबाव और 150 से 225 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होती है। इससे एथिलीन डायमाइन, डायथिलीन ट्रायमाइन, पाइपरज़ीन, अमीनो एथिल पाइपरज़ीन, हाइड्रॉक्सिल एथिल पाइपरज़ीन और अमीनो एथिल इथेनॉलमाइन का मिश्रण बनता है। यह प्रतिक्रिया एक कंटीन्यूअस फ्लो रिएक्टर में होती है। रिएक्टर से मिलने वाले रिएक्शन मिक्सचर को फिर प्रोडक्ट्स को अलग करने के लिए कई बार डिस्टिलेशन (आसवन) प्रक्रिया से गुज़ारा जाता है। बचे हुए कच्चे माल को वापस रिएक्शन स्टेज में भेज दिया जाता है ताकि उनसे ज़रूरी प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें।

10. जिस प्रोडक्ट की बात हो रही है, उसे कस्टम टैरिफ के चैप्टर 29 में "ऑर्गेनिक केमिकल्स" (कार्बनिक रसायन) के तहत रखा गया है। यह कस्टम टैरिफ एक्ट, 1975 के चैप्टर 29 और एच एस कोड 2921 21 00 के अंतर्गत आता है। अथॉरिटी ने कस्टम क्लासिफिकेशन को

केवल संकेत के तौर पर माना है और इस जांच के दायरे के लिए इसे बाध्यकारी नहीं माना है। भारत में इस प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर कोई रोक नहीं है क्योंकि यह 'ओपन जनरल लाइसेंस' के तहत आता है। इस प्रोडक्ट पर लागू बेसिक कस्टम ड्यूटी 7.5% है। इस प्रोडक्ट के लिए माप की तय इकाई मीट्रिक टन (मीट्रिक टन) है, और इस जांच के लिए भी इसी इकाई को अपनाया गया है।

11. नियमों के नियम 2(घ) में "समान वस्तु (समान वस्तु)" की परिभाषा निम्नानुसार दी गई है:

> *"'एक जैसी वस्तु' (like article) का मतलब है ऐसी वस्तु जो भारत में डंपिंग के लिए जांच की जा रही वस्तु के बिल्कुल समान या हर तरह से वैसी ही हो; या अगर ऐसी वस्तु न हो, तो कोई दूसरी वस्तु जो भले ही हर तरह से वैसी न हो, लेकिन उसकी विशेषताएं जांच की जा रही वस्तु की विशेषताओं से काफी मिलती-जुलती हों।"*

12. अथॉरिटी का मानना है कि ऊपर बताई गई परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि दो वस्तुओं को 'एक जैसा' मानने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि वे हर तरह से बिल्कुल एक जैसी हों। अगर दो वस्तुओं की विशेषताएं काफ़ी हद तक मिलती-जुलती हैं, तो इतनी समानता ही उन्हें 'एक जैसा' मानने के लिए काफ़ी है। यह तय करने के लिए कि क्या दो वस्तुओं की विशेषताएं काफ़ी हद तक मिलती-जुलती हैं, अथॉरिटी उत्पादों की तकनीकी और व्यावसायिक रूप से एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकने की क्षमता (प्रतिस्थापन) को अहम पैमाना मानती है। दो उत्पाद उत्पादन की तकनीक, डिज़ाइन, स्टाइल, क्वालिटी आदि के मामले में अलग-अलग दिख सकते हैं, फिर भी जांच के मकसद से उन्हें 'एक जैसा' माना जा सकता है, बशर्ते वे बाज़ार में एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकें और बदले जा सकें–ऐसा उनके एक जैसे अंतिम इस्तेमाल और ग्राहकों की पसंद के कारण हो सकता है।

13. अथॉरिटी का मानना है कि संबंधित देशों से एक्सपोर्ट किए गए प्रोडक्ट और घरेलू इंडस्ट्री द्वारा सप्लाई किए गए समान प्रोडक्ट के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू इंडस्ट्री द्वारा बनाए गए और संबंधित देशों से इम्पोर्ट किए गए प्रोडक्ट, फिजिकल और केमिकल विशेषताओं जैसे गुणों के मामले में एक-जैसे हैं। कंज्यूमर घरेलू और इम्पोर्टेड दोनों तरह के मटीरियल का इस्तेमाल एक-दूसरे की जगह कर रहे हैं और एक्सपोर्टर तथा घरेलू इंडस्ट्री ने एक ही तरह के कस्टमर्स को वही प्रोडक्ट बेचा है। इसलिए, अथॉरिटी का यह मानना है कि घरेलू इंडस्ट्री द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट के समान ही है।

14. अथॉरिटी ने जांच शुरू करने के नोटिस में विचाराधीन प्रोडक्ट के दायरे और पीसीएन मैथडोलॉजी के बारे में बताया। संबंधित पक्षों से कहा गया कि अगर उनके पास पीयूसी-पीसीएन मैथडोलॉजी पर कोई टिप्पणी है, तो वे जांच शुरू होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर उसे दें।

15. अथॉरिटी ने विचाराधीन प्रोडक्ट के दायरे और पीसीएन मैथडोलॉजी पर संबंधित पक्षों की टिप्पणियों पर विचार किया। हालाँकि, अथॉरिटी का मानना था कि मौजूदा जांच में किसी चीज़ को बाहर रखने या पीसीएन बनाने का कोई ठोस आधार नहीं था। इसलिए, जवाब दाखिल करने के मकसद से विचाराधीन प्रोडक्ट का दायरा और पीसीएन मैथडोलॉजी वही रखी गई, जो 25 मार्च, 2025 के शुरुआती नोटिफिकेशन में बताई गई थी।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और स्टैंडिंग

घ.1 विरोधी हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन

16. विरोधी हितबद्ध पक्षों ने घरेलू उद्योग के दायरे एवं उसकी स्थिति (खड़ा) के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं।
    i. आवेदक ने एक और घरेलू उत्पादक के होने का दावा किया है, लेकिन उसका नाम या उत्पादन से जुड़ी जानकारी नहीं बताई है, जिससे उसके 'स्टैंडिंग' दावे की सटीकता पर गंभीर संदेह पैदा होता है।

घ.2 आवेदक द्वारा प्रस्तुति

17. आवेदक ने घरेलू उद्योग के दायरे और उसकी स्थिति के संबंध में निम्नलिखित बातें कही हैं:
    i. आवेदक, विचाराधीन उत्पाद 'एथिलीन डायमाइन' (ईडीए) का भारत में एकमात्र उत्पादक है।
    ii. आवेदक के अलावा, 'डायमाइन्स एंड केमिकल्स लिमिटेड' भी इसी तरह के उत्पाद का एक और निर्माता है, जिसकी क्षमता 2500 मीट्रिक टन है। हालाँकि, आवेदक का मानना है कि यह निर्माता अभी कोई उत्पादन नहीं कर रहा है।
    iii. आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान संबंधित देशों में से किसी से भी विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।
    iv. आवेदक का संबंधित देशों के किसी निर्यातक या भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से कोई संबंध नहीं है।

गैर गोपनीय

घ.3 <u>प्राधिकरण द्वारा जांच</u>

18. नियमों का नियम 2(b) 'घरेलू उद्योग' शब्द को इस प्रकार परिभाषित करता है:

> *"(b) "घरेलू उद्योग" का मतलब है वे घरेलू उत्पादक जो कुल मिलाकर वैसी ही वस्तु के निर्माण और उससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल हैं, या जिनका उस वस्तु का सामूहिक उत्पादन, उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है; सिवाय तब, जब ऐसे उत्पादक कथित तौर पर डंप की गई वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से जुड़े हों या खुद उसके आयातक हों–ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' शब्द का अर्थ बाकी उत्पादकों से माना जा सकता है।"*

19. यह आवेदन बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड ने दायर किया है। रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी के अनुसार, भारत में संबंधित सामान का एक और उत्पादक है, जिसका नाम डायमाइन्स एंड केमिकल्स लिमिटेड है। इस जांच को शुरू करने से पहले अथॉरिटी ने डायमाइन्स एंड केमिकल्स लिमिटेड को सूचना भेजी थी। हालांकि, उस उत्पादक ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। घरेलू उद्योग का दावा है कि नुकसान की अवधि के दौरान वह उत्पादक संबंधित उत्पाद का उत्पादन नहीं कर रहा था।

20. अथॉरिटी ने डीजी सिस्टम के ट्रांज़ैक्शन-वाइज़ डेटा की जांच की है, और यह पाया गया है कि बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। यह भी देखा गया है कि बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड का संबंध संबंधित देशों से विचाराधीन उत्पाद के किसी निर्यातक या भारत में किसी आयातक से नहीं है।

21. रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी के आधार पर, अथॉरिटी ने जांच की अवधि के लिए भारतीय उत्पादन और भारतीय उत्पादन में बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड की हिस्सेदारी इस प्रकार तय की है:

क्र. सं.	**विवरण**	**उत्पादन (मीट्रिक टन)**	**हिस्सा (%)**
1	**आवेदक का उत्पादन**	*******	**100**
2	**कुल/सकल भारतीय उत्पादन**	*******	**100**

22. बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड नियम 2(ख) के अर्थ में एक पात्र घरेलू उद्योग है तथा नियम 5(3) के अनुसार स्थिति (स्थिति) की आवश्यक शर्तों को पूरा करता है। अतः

प्राधिकरण यह मानता है कि बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग का गठन करता है।

ङ. <u>गोपनीयता एवं विविध अभ्यावेदन</u>

ङ.1 <u>विरोधी हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन</u>

23. विरोधी हितबद्ध पक्षों ने निम्नलिखित विविध अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं:

i. उनके उत्तरों में की गई सभी गोपनीयता संबंधी दावे एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 7 तथा प्राधिकरण द्वारा जारी ट्रेड नोटिस संख्या 10/2018 दिनांक 27 सितंबर 2018 के अनुरूप हैं, क्योंकि ये दावे केवल ऐसी स्वामित्व वाली व्यावसायिक जानकारी (स्वामित्व वाली व्यावसायिक जानकारी) के संबंध में किए गए हैं, जिनका प्रकटीकरण होने पर कंपनी को गंभीर व्यावसायिक क्षति हो सकती है तथा उसकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

ii. उत्पादों की सूची का प्रकटीकरण ट्रेड नोटिस संख्या 10/2018 के अनुबंध-II के अंतर्गत कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। तथापि, उत्पादों की सूची कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

iii. कंपनियों ने उत्पाद जिसके संबंध में जांच की जा रही है, के उत्पादन में शामिल सभी संबंधित पक्षों (संबंधित पक्ष) के नामों का विधिवत प्रकटीकरण किया है।

iv. वित्तीय एवं लेखा प्रणाली (वित्तीय एवं लेखा प्रणाली) से संबंधित सूचना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है तथा ट्रेड नोटिस के अनुबंध-II के अनुसार इसका प्रकटीकरण आवश्यक भी नहीं है।

v. सदारा केमिकल कंपनी ने यह प्रस्तुत किया है कि उत्पाद जिसके संबंध में जांच की जा रही है, की निर्माण प्रक्रिया अत्यंत स्वामित्वाधीन (स्वामित्वाधीन) है तथा यह उत्पादक के तकनीकी ज्ञान (तकनीकी ज्ञान) और व्यापारिक गोपनीयता (व्यापारिक गोपनीय जानकारी) का एक मूलभूत घटक है। तथापि, कंपनी ने उत्पादन प्रक्रिया का गैर-गोपनीय सार (गैर-गोपनीय सारांश) प्रदान किया है।

vi. निर्यात मूल्य में किए गए समायोजनों (समायोजन) के गैर-प्रकटीकरण के संबंध में यह प्रस्तुत किया गया है कि विरोधी पक्षों द्वारा निर्यात मूल्य की गणना में दावा किए गए समायोजन प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट 3ए/3बी के गैर-गोपनीय संस्करण में पारदर्शी रूप से प्रकट किए गए हैं। ये समायोजन कंपनी-विशिष्ट वाणिज्यिक डेटा से संबंधित हैं, जिनमें वित्तीय एवं लेन-देन संबंधी विवरण शामिल हैं, जो प्रकृति में गोपनीय हैं। यद्यपि समायोजनों की पूर्ण कार्यप्रणाली (कार्यप्रणाली) एवं उनकी मात्रा

(मात्रा) को गोपनीय रखा गया है, तथापि समायोजनों के प्रकार को परिशिष्टों के गैर-गोपनीय संस्करण में पर्याप्त रूप से संक्षेपित किया गया है।

vii. आवेदक ट्रेड नोटिस 10/2018 का पालन करने में विफल रहा। एनआईपी और नेट सेल्स रियलाइज़ेशन का खुलासा करने में विफल रहा।

viii. रदर्शिता और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, अथॉरिटी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्मेट में ही इम्पोर्ट डेटा तक पहुँच का अनुरोध करने के लिए एक्सॉटिक डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के फैसले और ट्रेड नोटिस नंबर 07/2018 का हवाला दिया गया।

ङ.2 <u>आवेदक द्वारा प्रस्तुति</u>

24. आवेदक ने निम्नलिखित विविध बातें कही हैं:

i. विरोधी पक्ष उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादित उत्पादों की सूची, संबंधित कंपनियों की सूची और कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वित्तीय और अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा गोपनीयता का दावा करते हैं। ट्रेड नोटिस के अनुसार संबंधित पक्षों का खुलासा किया जाना चाहिए।

ii. एक्सपोर्ट करने वालों ने नॉर्मल वैल्यू और नेट एक्सपोर्ट प्राइस की गणना के लिए ज़रूरी एडजस्टमेंट की जानकारी नहीं दी है। नॉर्मल वैल्यू और एक्सपोर्ट प्राइस में एडजस्टमेंट की लिस्ट की जानकारी अथॉरिटी द्वारा फ़ाइनल नतीजों में बताई जाती है। इसलिए, प्रोड्यूसर/एक्सपोर्टर ने जो जानकारी दी है, उसे बाद में सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इस वजह से, इस मामले में गोपनीयता का दावा पूरी तरह से बेबुनियाद है।

iii. वितरण चैनलों को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है।

iv. संबंधित आयातकों ने सभी एग्ज़िबिट और एनेक्ज़र को गोपनीय बताया है और उनके ट्रेंड्स का भी खुलासा नहीं किया है, जिससे आवेदक के लिए सार्थक टिप्पणी करना मुश्किल हो गया है।

v. कार्डोलाइट और इंडोरामा ने विचाराधीन प्रोडक्ट की खरीद, कुल बिक्री टर्नओवर, पीयूसी के इस्तेमाल की जानकारी, लागत का ब्योरा और प्रोडक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इसके अलावा, इंडोरामा ने प्रोडक्शन प्रोसेस को भी गोपनीय बताया है।

vi. अन्य इच्छुक पक्षों ने आरोप लगाया कि घरेलू उद्योग ट्रेड नोटिस 10/2018 का पालन करने में विफल रहा; हालाँकि, घरेलू उद्योग ने आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण में एनआईपी (रेंज में) और नेट सेल्स रियलाइज़ेशन (इंडेक्स्ड/ट्रेंड के रूप में) सहित सभी संबंधित जानकारी का खुलासा किया है।

ङ.3 <u>प्राधिकरण द्वारा जांच</u>

25. अथॉरिटी ने नियम 6(7) के अनुसार, अलग-अलग पक्षों द्वारा दी गई जानकारी का वह वर्शन (संस्करण) सभी दूसरे इच्छुक पक्षों को उपलब्ध कराया जो गोपनीय नहीं था। इच्छुक पक्षों द्वारा सौंपी गई जानकारी की गोपनीयता के संबंध में, नियमों का नियम 7 इस प्रकार है:

> *"7. गोपनीय जानकारी:*
>
> *(1) नियम 6 के उप-नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप-नियम (2), नियम 15 के उप-नियम (4) और नियम 17 के उप-नियम (4) में दी गई किसी भी बात के बावजूद, नियम 5 के उप-नियम (1) के तहत मिलीं अर्जियों की कॉपी, या जांच के दौरान किसी पक्ष द्वारा तय अधिकारी को गोपनीय तौर पर दी गई कोई भी जानकारी–जब तय अधिकारी उसकी गोपनीयता के बारे में संतुष्ट हो जाए– तो उसे गोपनीय ही माना जाएगा और ऐसी जानकारी देने वाले पक्ष की खास मंज़ूरी के बिना ऐसी कोई भी जानकारी किसी दूसरे पक्ष को नहीं बताई जाएगी।*
>
> *(2) तय अधिकारी, गोपनीय आधार पर जानकारी देने वाली इच्छुक पार्टियों से उस जानकारी का गैर-गोपनीय सारांश देने के लिए कह सकता है। अगर जानकारी देने वाली पार्टी की राय में उस जानकारी का सारांश नहीं बनाया जा सकता है, तो वह पार्टी तय अधिकारी को यह बताते हुए एक बयान दे सकती है कि सारांश क्यों नहीं बनाया जा सकता।*
>
> *(3) उप-नियम (2) में दी गई किसी भी बात के बावजूद, अगर तय अधिकारी को यह लगता है कि जानकारी को गोपनीय रखने का अनुरोध सही नहीं है, या जानकारी देने वाला व्यक्ति जानकारी को सार्वजनिक करने या उसे सामान्य या संक्षिप्त रूप में बताने की अनुमति देने को तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी को नज़रअंदाज़ कर सकता है।*

26. देखा गया है कि घरेलू उद्योग और संबंधित पक्षों ने कई तरह की जानकारी को गोपनीय रखने का दावा किया है, जैसे कि उत्पादन, क्षमता, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, बाजार में हिस्सेदारी, स्टॉक, बिक्री मूल्य, लागत, लाभ, नकद लाभ, निवेश पर रिटर्न, गैर-हानिकारक मूल्य, उत्पादन लागत से जुड़ी जानकारी, सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य, डंपिंग मार्जिन, लैंडेड मूल्य, नुकसान का मार्जिन, मूल्य समायोजन, लाभ से जुड़ी जानकारी, बिक्री के चैनल, बिक्री और खरीद के दस्तावेज, ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के नाम आदि। यह भी देखा गया है कि जहां भी जानकारी नुकसान की अवधि से संबंधित है, उसे इंडेक्स के आधार पर दिया गया है। जहां जानकारी किसी एक वर्ष से संबंधित है, उसे एक रेंज में बताया गया है, बशर्ते ऐसी जानकारी देने से उसकी गोपनीयता पर कोई असर न पड़े। संबंधित पक्षों ने कई सहायक

दस्तावेजों और जानकारी को गोपनीय रखने का दावा किया है, जिन्हें उन्होंने सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं किया है। जिन मामलों में किसी संबंधित पक्ष ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण सार्वजनिक नहीं किए हैं, उन्हें गोपनीय माना गया है। जहां भी संबंधित पक्षों ने किसी दस्तावेज को गोपनीय बताया है, वहां यह देखा गया है कि उनका कहना है कि इन दस्तावेजों का सारांश नहीं बनाया जा सकता और उन्होंने इसके कारण भी बताए हैं। संबंधित पक्षों का दावा था कि घरेलू उद्योग ने गैर-हानिकारक मूल्य की रेंज का खुलासा नहीं किया। बाद में देखा गया कि वही जानकारी सार्वजनिक कर दी गई थी।

27. अथॉरिटी ने सभी जांचों में घरेलू उद्योगों, विदेशी उत्पादकों और अन्य संबंधित पक्षों द्वारा दी गई जानकारी और दस्तावेजों के मामले में संबंधित पक्षों को गोपनीयता का दावा करने की लगातार अनुमति दी है। अथॉरिटी ने देखा है कि सभी संबंधित पक्षों ने अपनी कारोबार से जुड़ी संवेदनशील जानकारी को गोपनीय बताया है। संतुष्ट होने पर, अथॉरिटी ने जहां भी जरूरी समझा, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना है तथा उसे अन्य संबंधित पक्षों के सामने उजागर नहीं किया है।

28. आवेदक या डीजीटीआर द्वारा ट्रांज़ैक्शन-वाइज़ डेटा के खुलासे के संबंध में, अथॉरिटी का मानना है कि आवेदक के लिए ज़रूरी जानकारी में आयात की मात्रा और मूल्य तथा जानकारी का स्रोत शामिल है। नियमों के तहत अथॉरिटी के लिए आयात की मात्रा और कीमत से जुड़ी जानकारी महत्वपूर्ण है। ट्रांज़ैक्शन-वाइज़ डेटा केवल आवेदक द्वारा किए गए दावों की पर्याप्तता और सटीकता के लिए सहायक जानकारी के रूप में काम आता है। इसी तरह, डीजी सिस्टम से इकट्ठा की गई जानकारी का मकसद केवल आयात की मात्रा और मूल्य का पता लगाना है, और इसे मौजूदा डिस्क्लोज़र स्टेटमेंट में सही ढंग से बताया गया है। संबंधित पक्षों को जांच और निर्णय से जुड़ी जानकारी पर अपने हितों की रक्षा करने का पर्याप्त मौका मिला है।

च. <u>डंपिंग का आकलन और सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य तथा डंपिंग मार्जिन का निर्धारण</u>

च.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन</u>

29. विरोधी हितबद्ध पक्षों ने डंपिंग के आकलन तथा सामान्य मूल्य (सामान्य मूल्य), निर्यात मूल्य (निर्यात मूल्य) और डंपिंग मार्जिन (डंपिंग अंतर) के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं।

i. सदारा केमिकल कंपनी सऊदी अरब से उत्पाद जिसके संबंध में जांच की जा रही है, की एक सहकारी उत्पादक एवं निर्यातक है, जो अपने संबंधित ट्रेडर्स के माध्यम से

भारत को निर्यात करती है। यह दावा किया गया है कि डंपिंग मार्जिन का निर्धारण सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराए गए वास्तविक अभिलेखों एवं सूचनाओं के आधार पर किया जाना चाहिए।

ii. सऊदी अरब के लिए आरोपित डंपिंग मार्जिन (75-85%) अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है और इसका कोई विश्वसनीय आधार नहीं है, क्योंकि यह एक त्रुटिपूर्ण (त्रुटिपूर्ण) सामान्य मूल्य (सामान्य मान) गणना पर आधारित है।

iii. घरेलू इंडस्ट्री द्वारा बताई गई 'नॉर्मल वैल्यू' असल में बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसे उनके अपने कम कुशल और कम प्रतिस्पर्धी कॉस्ट स्ट्रक्चर के आधार पर तय किया गया है। घरेलू इंडस्ट्री की लागत कई ढांचागत कमियों की वजह से बढ़ी हुई है: यह एक नई कंपनी है (जिसने 2019 में प्रोडक्शन शुरू किया) और इसके पास बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन का फ़ायदा (पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं) नहीं है; यह वर्टिकली इंटीग्रेटेड नहीं है और इम्पोर्ट किए गए कच्चे माल (एमईए) पर निर्भर है; और सोलापुर में प्लांट होने के कारण इसे देश के अंदर सामान लाने-ले जाने (इनलैंड लॉजिस्टिक्स) पर काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। यह कॉस्ट स्ट्रक्चर सदारा (Sadara) जैसे कुशल ग्लोबल प्रोड्यूसर के हिसाब से सही नहीं है।

iv. डंपिंग मार्जिन की गणना, उत्तरदाताओं द्वारा अपने प्रश्नावली के जवाबों में सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य के बारे में दिए गए वास्तविक और सत्यापित डेटा के आधार पर की जानी चाहिए।

च.2 <u>आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन</u>

30. आवेदक ने डंपिंग के आकलन तथा सामान्य मूल्य (सामान्य मान), निर्यात मूल्य (निर्यात मूल्य) और डंपिंग मार्जिन (डंपिंग मार्जिन) के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं:

i. चीन (पीआरसी) को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए।

ii. अगर यह तर्क दिया जाए कि चीन पीआर के एक्सेसियन प्रोटोकॉल का आर्टिकल 15(a)(ii) पहले ही खत्म हो चुका है और इसलिए इसे मौजूदा मामले में लागू नहीं किया जा सकता, तो भी आर्टिकल 15(a)(i) लागू रहता है और चीन पीआर के लिए 'नॉर्मल वैल्यू' तय करने के लिए उस पर विचार किया जाना चाहिए।

iii. चीन पीआर के एक्सेसियन प्रोटोकॉल के 15(a)(i) के तहत यह ज़रूरी है कि एक्सपोर्टर, नियमों के एनेक्शर I के पैरा 8 में बताई गई शर्तों को पूरा करे।

iv. चूँकि चीनी उत्पादक बाज़ार अर्थव्यवस्था उपचार (बाज़ार अर्थव्यवस्था उपचार) के लिए पात्र नहीं हैं, इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकरण को सामान्य मूल्य (सामान्य मूल्य) के निर्धारण हेतु नियमों के अनुबंध I के पैराग्राफ 7 का पालन करना चाहिए।

v. आवेदक वास्तविक बिक्री मूल्य या किसी तीसरे देश की बाज़ार अर्थव्यवस्था में उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं कर सका, क्योंकि वास्तविक बिक्री मूल्य का कोई भी सत्यापन योग्य प्रमाण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं था।

vi. आवेदक किसी तीसरे देश से दूसरे देश (भारत सहित) को बेचे गए सामान की कीमत के आधार पर 'सामान्य मूल्य' तय नहीं कर सका, क्योंकि भले ही संबंधित सामान के लिए भारत में एक खास कोड है, लेकिन दुनिया भर में इसके लिए कोई खास कोड नहीं है।

vii. आवेदक ने 'किसी अन्य उचित आधार' के तहत सामान्य मूल्य तय किया था। यह आधार दूसरे देशों को किए गए निर्यात की कीमत (क्योंकि ये निर्यात मात्रा में काफी हैं और इनसे मुनाफा भी होता है) और उचित मुनाफ़े को जोड़कर उत्पादन लागत (जिसमें कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमत को ध्यान में रखा गया था) पर आधारित था।

viii. अगर अथॉरिटी को लगता है कि चीन के एक्सेसियन प्रोटोकॉल के आर्टिकल 15 के सभी प्रावधान अब लागू नहीं हैं और नियमों के पैरा 1-6 के अनुसार सामान्य मूल्य तय करने की ज़रूरत है, तो भी चीनी घरेलू लागत और कीमतों को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक चीनी एक्सपोर्टर कई मानकों को पूरा न कर लें, जैसे कि (i) लागत और कीमतों को तय करने में सरकारी दखल न होना, (ii) मुख्य इनपुट की कीमतें काफी हद तक बाजार मूल्य को दर्शाती हों, (iii) एक्सपोर्टर के खातों की ऑडिटिंग चीनी आम तौर पर स्वीकृत अकाउंटिंग सिद्धांतों (जीएएपी) और अंतरराष्ट्रीय अकाउंटिंग मानकों के अनुसार की गई हो, और (iii) एक्सपोर्टर के संगठनात्मक ढांचे के कारण लागत का उचित होना।

ix. पूरी कोशिश करने के बाद भी, आवेदक को यूरोपीय संघ में उत्पादकों की वास्तविक लेन-देन कीमत के बारे में कोई सबूत नहीं मिल सका।

x. आवेदक ने सामान्य मूल्य तय करने के लिए यूरोपीय संघ के अंदर की कीमतों पर विचार किया है; यह वह कीमत है जिस पर उत्पाद का व्यापार यूरोपीय संघ में खपत के लिए किया जाता है।

xi. ताइवान में उत्पादकों की वास्तविक लेन-देन कीमत के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई सबूत उपलब्ध नहीं है। चूंकि उस देश में इस उत्पाद के लिए एक खास कोड है, इसलिए आवेदक ने ताइवान में होने वाले आयात के आधार पर सामान्य मूल्य तय किया है।

xii. सऊदी अरब के मामले में भी, देश में उत्पादकों की वास्तविक लेन-देन कीमत या उत्पादन की वास्तविक लागत के बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि देश में इस उत्पाद के लिए एक खास कोड है, लेकिन कोई प्रकाशित डेटा न

होने के कारण, आवेदक ने मार्जिन में उचित बढ़ोतरी के साथ अपनी उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य तय किया है।

xiii. जांच की अवधि के दौरान, संबंधित देशों के डंपिंग मार्जिन और इंजरी मार्जिन न केवल 'डी-मिनिमस' (न्यूनतम सीमा) से ऊपर हैं, बल्कि अभूतपूर्व रूप से महत्वपूर्ण भी हैं।

च.3 <u>प्राधिकरण द्वारा जांच</u>

31. प्राधिकरण ने विषय देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली (प्रश्नावली) भेजी, जिसमें उन्हें प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रूप एवं तरीके से सूचना प्रदान करने की सलाह दी गई। विषय देशों के निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने, उनके संबंधित निर्यातकों एवं भारत में आयातकों सहित, निर्धारित प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत किए हैं।

क्र. सं.	**हितबद्ध पक्ष का नाम**
क.	एम/एस बीएएसएफ एंटवर्पेन एनवी, बेल्जियम
ख.	एम/एस बीएएसएफ ईओओडी, बुल्गारिया
ग.	एम/एस बीएएसएफ एस्पान्योला एसएलयू, स्पेन
घ.	एम/एस बीएएसएफ फ्रांस एस.ए.एस., फ्रांस
ङ.	एम/एस बीएएसएफ हांगकांग लिमिटेड, हांगकांग
च.	एम/एस बीएएसएफ हंगारिया केएफटी., हंगरी
छ.	एम/एस बीएएसएफ-वाईपीसी कंपनी लिमिटेड, चीन पीआर
ज.	एम/एस बीएएसएफ आयरलैंड डीएसी, आयरलैंड
झ.	एम/एस बीएएसएफ इटालिया एस.पी.ए., इटली
ञ.	एम/एस बीएएसएफ नेदरलैंड बी.वी., नीदरलैंड्स
ट.	एम/एस बीएएसएफ एसई, जर्मनी
ठ.	एम/एस बीएएसएफ स्पोल एस.आर.ओ., चेक गणराज्य
ड.	एम/एस बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड, भारत
ढ.	एम/एस डॉव केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड, दुबई शाखा, यूएई
ण.	एम/एस डॉव सऊदी अरबिया प्रोडक्ट मार्केटिंग अरेबिया बी.वी., दुबई शाखा, यूएई
त.	एम/एस डॉव केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, दुबई शाख

32. विषय देशों के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य (सामान्य मान) और निर्यात मूल्य (निर्यात मूल्य) निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं,

गैर गोपनीय

च.4 <u>सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य का निर्धारण</u>

क. <u>चीन पीआर से सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य।</u>

- **सामान्य मान**

33. WTO में चीन के शामिल होने से जुड़े प्रोटोकॉल का आर्टिकल 15 इस प्रकार है:

> *गैट 1994 का आर्टिकल VI, 'टैरिफ़ और ट्रेड पर जनरल एग्रीमेंट 1994' के आर्टिकल VI को लागू करने का एग्रीमेंट ("एंटी-डंपिंग एग्रीमेंट") और एससीएम एग्रीमेंट, WTO के किसी सदस्य देश में चीन से होने वाले इंपोर्ट से जुड़ी कार्यवाही में नीचे दी गई बातों के अनुसार लागू होंगे:*
> *(क) गैट 1994 के आर्टिकल VI और एंटी-डंपिंग एग्रीमेंट के तहत कीमत की तुलना तय करते समय, आयात करने वाला विश्व व्यापार संगठन सदस्य या तो जांच के दायरे में आने वाली इंडस्ट्री के लिए चीनी कीमतों या लागतों का इस्तेमाल करेगा, या फिर ऐसी कार्यप्रणाली अपनाएगा जो चीन में घरेलू कीमतों या लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित न हो; और यह सब निम्नलिखित नियमों के आधार पर किया जाएगा:*
>
> *(i) अगर जांच के दायरे में आने वाले उत्पादक यह साफ तौर पर दिखा सकें कि उस उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के मामले में, उसी तरह का उत्पाद बनाने वाली इंडस्ट्री में मार्केट इकॉनमी की स्थितियां मौजूद हैं, तो आयात करने वाला विश्व व्यापार संगठन सदस्य देश, कीमतों की तुलना करने के लिए जांच के दायरे में आने वाली इंडस्ट्री के मामले में चीनी कीमतों या लागत का इस्तेमाल करेगा;*
>
> *(ii) अगर जांच के दायरे में आने वाले प्रोड्यूसर यह साफ़ तौर पर नहीं दिखा पाते हैं कि उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और बिक्री के मामले में, उस प्रोडक्ट को बनाने वाली इंडस्ट्री में मार्केट इकॉनमी की स्थितियां मौजूद हैं, तो इम्पोर्ट करने वाला विश्व व्यापार संगठन सदस्य ऐसी कार्यप्रणाली अपना सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों या लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित न हो।*
>
> *(ख)एससीएम समझौते (एससीएम समझौता) के भाग II, III और V के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों में, जब अनुच्छेद 14(a), 14(b), 14(c) और 14(d) में वर्णित सब्सिडी (सब्सिडी) पर विचार किया जाता है, तो एससीएम समझौते के संबंधित*

प्रावधान लागू होंगे; तथापि, यदि इन प्रावधानों के अनुप्रयोग में विशेष कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, तो आयात करने वाला विश्व व्यापार संगठन सदस्य सब्सिडी लाभ (सब्सिडी का लाभ) की पहचान और मापन के लिए ऐसी कार्यप्रणालियाँ अपना सकता है, जो इस संभावना को ध्यान में रखें कि चीन में प्रचलित शर्तें और परिस्थितियाँ हमेशा उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी कार्यप्रणालियों को लागू करते समय, जहाँ व्यावहारिक हो, आयात करने वाला विश्व व्यापार संगठन सदस्य चीन के बाहर प्रचलित शर्तों और परिस्थितियों का उपयोग करने से पहले चीन में प्रचलित शर्तों और परिस्थितियों को समायोजित (समायोजित करना) करना चाहिए।

(ग)आयात करने वाला विश्व व्यापार संगठन सदस्य, उप-पैराग्राफ (a) के अनुसार इस्तेमाल किए गए तरीकों की जानकारी 'एंटी-डंपिंग प्रैक्टिस कमेटी' को देगा और उप-पैराग्राफ (b) के अनुसार इस्तेमाल किए गए तरीकों की जानकारी 'सब्सिडी और काउंटरवेलिंग मेज़र्स कमेटी' को देगा।

(घ) जब चीन, आयात करने वाले विश्व व्यापार संगठन सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत, यह स्थापित कर लेता है कि वह एक बाज़ार अर्थव्यवस्था (बाज़ार अर्थव्यवस्था) है, तो उप-अनुच्छेद (a) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि उस आयातक सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्रवेश (परिग्रहण) की तिथि पर बाज़ार अर्थव्यवस्था के मानदंड (मानदंड) शामिल हों। किसी भी स्थिति में, उप-अनुच्छेद (a)(ii) का प्रावधान प्रवेश की तिथि के 15 वर्षों बाद समाप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि चीन, आयात करने वाले विश्व व्यापार संगठन सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसार यह स्थापित करता है कि किसी विशेष उद्योग या क्षेत्र में बाज़ार अर्थव्यवस्था की परिस्थितियाँ प्रचलित हैं, तो उप-अनुच्छेद (a) के गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था (गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था) संबंधी प्रावधान उस उद्योग या क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे।

34. आवेदक ने चीन के 'एक्सेशन प्रोटोकॉल' के आर्टिकल 15(a)(i) और 'एनेक्शर I' के पैरा 7 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि चीन पीआर में संबंधित प्रोडक्ट बनाने वाले प्रोड्यूसर्स को यह साबित करना चाहिए कि उनके उद्योग में मार्केट इकॉनमी की स्थितियां मौजूद हैं, खासकर उस प्रोडक्ट के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के मामले में जिस पर विचार किया जा रहा है। आवेदकों का कहना है कि अगर जवाब देने वाले चीनी प्रोड्यूसर्स यह साबित नहीं कर पाते हैं कि उनकी लागत और कीमत की जानकारी मार्केट-आधारित है, तो 'नॉर्मल वैल्यू' की गणना नियमों के 'एनेक्शर-I' के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।

35. यह ध्यान दिया गया है कि जहाँ अनुच्छेद 15 (a)(ii) में दिया गया प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गया है, वहीं विश्व व्यापार संगठन एंटी-डंपिंग समझौते के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान और एक्सेसियन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(a)(i) के तहत दायित्व के अनुसार, मार्केट इकोनॉमी ट्रीटमेंट का दावा करने के लिए सप्लीमेंट्री प्रश्नावली में दी जाने वाली जानकारी/डेटा के माध्यम से नियमों के एनेक्शर I के पैराग्राफ 8 में बताए गए मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। यह ध्यान दिया गया है कि चूंकि चीन PR के जवाब देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों ने सप्लीमेंट्री प्रश्नावली का जवाब नहीं दिया है, इसलिए नियमों के एनेक्शर I के पैराग्राफ 7 के प्रावधानों के अनुसार सामान्य मूल्य की गणना करना आवश्यक है, जो इस प्रकार है:

> *नॉन-मार्केट इकॉनमी वाले देशों से इंपोर्ट के मामले में, नॉर्मल वैल्यू का पता मार्केट इकॉनमी वाले किसी तीसरे देश में कीमत या अनुमानित वैल्यू के आधार पर लगाया जाएगा, या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को की गई बिक्री की कीमत के आधार पर, या जहाँ ऐसा करना संभव न हो, वहाँ किसी अन्य उचित आधार पर–जिसमें भारत में उसी तरह के प्रोडक्ट के लिए वास्तव में चुकाई गई या चुकाने योग्य कीमत शामिल हो सकती है (और ज़रूरत पड़ने पर उचित प्रॉफ़िट मार्जिन शामिल करने के लिए उसमें उचित बदलाव किया जा सकता है)–तय किया जाएगा। संबंधित देश और प्रोडक्ट के विकास के स्तर को ध्यान में रखते हुए, डेज़िग्नेटेड अथॉरिटी उचित तरीके से मार्केट इकॉनमी वाले किसी तीसरे देश का चयन करेगी और चयन के समय उपलब्ध किसी भी विश्वसनीय जानकारी को ध्यान में रखेगी। साथ ही, समय-सीमा के भीतर, यदि किसी अन्य मार्केट इकॉनमी वाले तीसरे देश के संबंध में इसी तरह के मामले में कोई जांच की गई हो, तो उसे भी उचित होने पर ध्यान में रखा जाएगा। जांच में शामिल पक्षों को मार्केट इकॉनमी वाले तीसरे देश के उक्त चयन के बारे में बिना किसी अनुचित देरी के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणी देने के लिए उचित समय दिया जाएगा।"*

36. पैरा 7 में 'सामान्य मूल्य' (सामान्य मान) तय करने के लिए एक क्रम (पदानुक्रम) बताया गया है। इसमें कहा गया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण इन आधारों पर किया जाएगा: मार्केट इकोनॉमी वाले किसी तीसरे देश में कीमत या 'कन्स्ट्रक्टेड वैल्यू' (निर्मित मूल्य); या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को की गई बिक्री की कीमत; या यदि ये संभव न हो, तो किसी भी उचित आधार पर–जिसमें भारत में उसी तरह की वस्तु के लिए वास्तव में चुकाई गई या देय कीमत शामिल हो सकती है (और यदि ज़रूरी हो, तो उचित मुनाफ़े के मार्जिन को शामिल करने के लिए उसमें उचित समायोजन/एडजस्टमेंट किया जा

सकता है)। इस प्रकार, अथॉरिटी का मानना है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण पैरा 7 में दिए गए विभिन्न क्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

37. अथॉरिटी यह भी नोट करती है कि नॉन-मार्केट इकॉनमी के मामले में 'नॉर्मल वैल्यू' तय करने से जुड़े मौजूदा कानूनी सिद्धांत कई फैसलों में दिए गए हैं। ये फैसले नियमों के एनेक्ज़र । के पैरा 7 को लागू करने के बारे में निर्देश देते हैं, जिसमें सही विकल्प चुनने और उससे जुड़ी जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है।

38. अथॉरिटी का कहना है कि किसी भी इच्छुक पक्ष ने किसी उपयुक्त मार्केट-इकोनॉमी वाले तीसरे देश में प्रोडक्ट की घरेलू कीमत या अनुमानित कीमत (निर्मित मूल्य) के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। अथॉरिटी यह भी कहती है कि उसे इच्छुक पक्षों द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई जानकारी और सबूतों के आधार पर एक उपयुक्त देश चुनना है। यह दावा किया गया है कि जिस प्रोडक्ट पर विचार किया जा रहा है, उसके लिए ज़्यादातर देशों में कोई खास कोड नहीं है। चूँकि ज़्यादातर देशों में इस प्रोडक्ट के लिए कोई खास कोड नहीं है, इसलिए अथॉरिटी ने इस आधार पर सामान्य मूल्य (सामान्य मान) तय नहीं किया है।

39. अथॉरिटी ने चीन (पीआर) के लिए 'सामान्य मूल्य' (सामान्य मान) का निर्धारण भारत में उसी तरह की वस्तु के लिए वास्तव में चुकाई गई या चुकाने योग्य कीमत के आधार पर किया है। यह सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन लागत को ध्यान में रखकर तय किया गया है; इसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों तथा उचित मुनाफ़े को जोड़कर और ज़रूरी समायोजन (समायोजन) करके इसे निकाला गया है। इस तरह तय किया गया 'निर्मित सामान्य मूल्य' (निर्मित सामान्य मूल्य) डंपिंग मार्जिन टेबल में दिया गया है।

- **निर्यात मूल्य**

<u>बीएएसएफ - वाईपीसी कंपनी लिमिटेड</u>

40. बीएएसएफ - वाईपीसी कंपनी लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद की निर्माता है और उसने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का *** MT निर्यात किया है। निर्माता ने दावा किया है कि उसने संबंधित ट्रेडर के माध्यम से संबंधित भारतीय ग्राहक को उत्पाद का अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात किया, जिसने इसे आगे गैर-संबंधित भारतीय ग्राहकों को बेच दिया। निर्माता ने समुद्री माल-भाड़े, देश के भीतर परिवहन आदि के आधार पर समायोजन का दावा किया है।

41. अथॉरिटी ने डेस्क वेरिफिकेशन किया है और प्रतिवादी द्वारा किए गए दावों की जांच की है। डेस्क वेरिफिकेशन के बाद प्रतिवादी द्वारा किए गए एडजस्टमेंट को मंज़ूरी दे दी गई है। इस तरह तय की गई नेट एक्सपोर्ट प्राइस नीचे डंपिंग मार्जिन टेबल में दी गई है।

चीन (पीआर) के सहयोग न करने वाले उत्पादक

42. अथॉरिटी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सहयोग न करने वाले उत्पादकों/निर्यातकों के लिए नेट एक्सपोर्ट प्राइस तय किया है। तय किया गया एक्स-फ़ैक्ट्री एक्सपोर्ट प्राइस नीचे दी गई डंपिंग मार्जिन टेबल में दिखाया गया है।

ख. <u>यूरोपीय संघ से सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य</u>

<u>बीएएसएफ एंटवर्पेन एनवी और उससे जुड़े ट्रेडर (जिन्हें बीएएसएफ ग्रुप कहा जाता है)</u>

- **<u>सामान्य मान</u>**

43. बीएएसएफ एंटवर्पेन एनवी यूरोपीय संघ में संबंधित सामान का उत्पादक है। उत्पादक ने अपने संबंधित निर्यातकों और आयातक के साथ मिलकर, ज़रूरी जानकारी देते हुए निर्यातक प्रश्नावली का जवाब जमा किया है। अथॉरिटी ने देखा है कि उत्पादक/निर्यातक ने जांच की अवधि के दौरान संबंधित ग्राहकों को *** मीट्रिक टन की घरेलू बिक्री की जानकारी दी है; इन ग्राहकों ने इसे या तो गैर-संबंधित ग्राहकों को फिर से बेचा या खुद इस्तेमाल किया।

44. सामान्य मूल्य तय करने के लिए, अथॉरिटी ने संबंधित सामान की उत्पादन लागत के आधार पर मुनाफ़ा कमाने वाले घरेलू बिक्री लेन-देन का पता लगाने के लिए 'सामान्य व्यापार प्रक्रिया' (ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ़ ट्रेड) का टेस्ट किया। अगर मुनाफ़ा कमाने वाले लेन-देन 80% से ज़्यादा हैं, तो अथॉरिटी ने सामान्य मूल्य तय करने के लिए घरेलू बाज़ार में हुए सभी लेन-देन को ध्यान में रखा है। जहाँ मुनाफ़े वाले लेन-देन 80% से कम हैं, वहाँ सामान्य मूल्य तय करने के लिए सिर्फ़ मुनाफ़े वाली घरेलू बिक्री को ही ध्यान में रखा जाता है। 'सामान्य व्यापार प्रक्रिया' टेस्ट के आधार पर यह देखा गया है कि संबंधित उत्पादक इस टेस्ट में सफल नहीं हो पाया है क्योंकि बिक्री का *** हिस्सा ही मुनाफ़ा कमाने वाला है, और इसलिए, अथॉरिटी ने इस मामले में मुनाफ़े वाले लेन-देन के आधार पर सामान्य मूल्य तय करना सही समझा है।

45. अथॉरिटी ने डेस्क वेरिफिकेशन किया है और प्रतिवादी द्वारा किए गए दावों की जांच की है, जिसमें इनलैंड फ्रेट, ओशन फ्रेट आदि से संबंधित एडजस्टमेंट शामिल हैं। डेस्क वेरिफिकेशन के बाद सत्यापित दावों को स्वीकार कर लिया गया है। इस तरह तय की गई सामान्य वैल्यू नीचे डंपिंग मार्जिन टेबल में दी गई है।

- **निर्यात मूल्य**

46. बीएएसएफ एंटवर्पेन एनवी, यूरोपीय संघ में विचाराधीन उत्पाद का निर्माता है। बीएएसएफ एंटवर्पेन एनवी ने इस उत्पाद का निर्यात सीधे संबंधित आयातक को और अपने संबंधित निर्यातकों - जैसे बीएएसएफ बेल्जियम कोऑर्डिनेशन सेंटर कॉमवी, बीएएसएफ ईओओडी, बीएएसएफ एस्पानोला एसएलयू, बीएएसएफ ओए, बीएएसएफ फ्रांस एस.ए.एस., बीएएसएफ हंगारिया केएफटी., बीएएसएफ आयरलैंड डीएसी, बीएएसएफ इटली एस.पी.ए., बीएएसएफ नीदरलैंड्स बी.वी.., बीएएसएफ एस.आर.एल.., बीएएसएफ स्पोल एस.आर.ओ., बीएएसएफ एस ई, बीएएसएफ हॉन्ग कॉन्ग लिमिटेड- के माध्यम से किया है। इन संबंधित निर्यातकों ने आगे यह उत्पाद अपने संबंधित आयातक, बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड को बेचा, जिसने बदले में ये सामान भारत में गैर-संबंधित ग्राहकों को बेचे।

47. बीएएसएफ एंटवर्पेन एनवी विचाराधीन उत्पाद की निर्माता है और उसने प्रश्नावली का जवाब दाखिल किया है। निर्माता ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के *** मीट्रिक टन निर्यात की सूचना दी है। निर्माता ने दावा किया है कि उसने संबंधित व्यापारियों के माध्यम से संबंधित भारतीय ग्राहकों को उत्पाद का अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात किया, जिन्होंने इसे असंबद्ध भारतीय ग्राहकों को फिर से बेच दिया। निर्माता ने समुद्री माल-भाड़े, अंतर्देशीय परिवहन आदि के आधार पर समायोजन का दावा किया है।

48. अथॉरिटी ने डेस्क वेरिफिकेशन किया है और प्रतिवादी द्वारा किए गए दावों की जांच की है। डेस्क वेरिफिकेशन के बाद प्रतिवादी द्वारा किए गए एडजस्टमेंट को मंज़ूरी दे दी गई है। इस तरह तय की गई नेट एक्सपोर्ट प्राइस नीचे डंपिंग मार्जिन टेबल में दी गई है।

<u>यूरोपीय संघ के सहयोग न करने वाले उत्पादक।</u>

49. प्राधिकरण ने गैर-सहकारी उत्पादकों/निर्यातकों (असहयोगी उत्पादक/निर्यातक) के लिए उपलब्ध तथ्यों (उपलब्ध तथ्य) के आधार पर शुद्ध निर्यात मूल्य (शुद्ध निर्यात मूल्य) निर्धारित किया

है। निर्धारित किया गया एक्स-फ़ैक्ट्री निर्यात मूल्य नीचे दिए गए डंपिंग मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ग. <u>सऊदी अरब से सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य</u>

<u>सदारा केमिकल कंपनी, डाउ केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड, दुबई ब्रांच, डाउ सऊदी अरब प्रोडक्ट मार्केटिंग अरेबिया बी.वी., डाउ केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड</u>

- **सामान्य मान**

50. सदारा केमिकल कंपनी ("सदारा") सऊदी अरब में उत्पाद जिसके संबंध में जांच की जा रही है, की उत्पादक है। सदारा ने निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली (निर्यातक प्रश्नावली) प्रारूप में अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करते हुए आवश्यक जानकारी प्रदान की है। प्राधिकरण ने नोट किया है कि जांच अवधि (पीओआई) के दौरान सदारा ने घरेलू बाजार में केवल एक घरेलू बिक्री लेन-देन (घरेलू बिक्री का लेन-देन) किया था, जो *** मीट्रिक टन (मीट्रिक टन) ऑफ-ग्रेड (बंद ग्रेड) उत्पाद का था और एक असंबंधित ग्राहक को किया गया था। चूँकि यह एकमात्र घरेलू बिक्री लेन-देन ऑफ-ग्रेड गुणवत्ता का था तथा मात्रा में पर्याप्त नहीं था, इसलिए इसे सामान्य मूल्य (सामान्य मान) के निर्धारण के लिए विचार में नहीं लिया जा सकता।

51. ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, अथॉरिटी ने जांच के दौरान उचित मुनाफ़े के मार्जिन को जोड़कर 'नॉर्मल वैल्यू' तय की है। यह वैल्यू जांच के तहत आने वाले प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट के आधार पर तय की गई है, जिसकी जानकारी सदा-रा (सदारा) ने अपेंडिक्स-8 में दी थी और जांच के दौरान जिसकी ठीक से पुष्टि की गई थी। इस तरह तय की गई 'नॉर्मल वैल्यू' का ज़िक्र डंपिंग मार्जिन टेबल में किया गया है।

- **निर्यात मूल्य**

52. सदारा केमिकल कंपनी सऊदी अरब में विचाराधीन उत्पाद की निर्माता है। पीओआई के दौरान, सदारा ने संबंधित निर्यातक, डाउ सऊदी अरब प्रोडक्ट मार्केटिंग अरबिया बी.वी. ("डाउ मार्केटिंग) को संबंधित सामान बेचा। इसके बाद, डाउ मार्केटिंग ने वह सामान एक अन्य संबंधित ट्रेडर, डाउ केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड, दुबई ब्रांच ("डाउ सिंगापुर) को बेचा। बाद में, डाउ सिंगापुर ने वह सामान भारत में संबंधित आयातक, डाउ केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ("डी.सी.आई.पी.एल इंडिया") को बेचा। अंत में, डी.सी.आई.पी.एल इंडिया ने वह सामान भारत में गैर-संबंधित ग्राहकों को बेचा।

53. डाउ मार्केटिंग ने डाउ केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, दुबई ब्रांच ("डी.सी.आई.पी.एल दुबई") को भी एक एक्सपोर्ट ट्रांज़ैक्शन किया है। इसके बाद डी.सी.आई.पी.एल दुबई ने संबंधित सामान का यह एक ट्रांज़ैक्शन भारत में एक ऐसे कस्टमर को बेचा है जिसका उनसे कोई संबंध नहीं है। सभी 5 एंटिटी - सदारा, डाउ मार्केटिंग, डाउ सिंगापुर, डी.सी.आई.पी.एल दुबई और डी.सी.आई.पी.एल इंडिया - ने इस जांच में हिस्सा लिया है और तय किए गए सवाल-जवाब के फ़ॉर्मैट में ज़रूरी जानकारी दी है।

54. अथॉरिटी ने डाउ मार्केटिंग, डाउ सिंगापुर और डी.सी.आई.पी.एल दुबई की तरफ़ से दिए गए जवाबों से यह देखा है कि पीओआई के दौरान, सदारा द्वारा बनाए और एक्सपोर्ट किए गए सामान को डाउ ग्रुप ने कुल मिलाकर मुनाफ़े पर दोबारा बेचा था।

55. सदारा ने समुद्री माल-भाड़े, बीमा, देश के भीतर परिवहन, बंदरगाह से जुड़े खर्चों, क्रेडिट लागत और मार्केटिंग शुल्क के लिए एडजस्टमेंट का दावा किया। अथॉरिटी ने उचित जांच-पड़ताल के बाद इन एडजस्टमेंट की समीक्षा की और उन्हें मंज़ूरी दी।

56. इस तरह तय की गई एक्स-फ़ैक्ट्री एक्सपोर्ट कीमत को डंपिंग मार्जिन की गणना के लिए ध्यान में रखा गया है और इसे नीचे दी गई डंपिंग मार्जिन तालिका में दिखाया गया है।

<u>सऊदी अरब के असहयोगी उत्पादक।</u>

57. अथॉरिटी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सहयोग न करने वाले उत्पादकों/निर्यातकों के लिए नेट एक्सपोर्ट प्राइस तय किया है। तय किया गया एक्स-फ़ैक्ट्री एक्सपोर्ट प्राइस नीचे दी गई डंपिंग मार्जिन टेबल में दिखाया गया है

घ. <u>ताइवान से सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य।</u>

58. चूंकि किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने इस जांच में हिस्सा नहीं लिया है, इसलिए ताइवान के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य का निर्धारण एंटी-डंपिंग नियम, 1995 के नियम 6(8) के तहत उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर किया गया है।

ङ. <u>डंपिंग मार्जिन</u>

गैर गोपनीय

59. वर्तमान जांच में निर्धारित सामान्य मूल्य (सामान्य मान), निर्यात मूल्य (निर्यात मूल्य) और डंपिंग मार्जिन (डंपिंग मार्जिन) निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	**विवरण**	**सीएनवी/एनवी (यूएसडी/एमटी)**	**एनईपी (यूएसडी/एमटी)**	**डंपिंग मार्जिन (यूएसडी/एमटी)**	**डंपिंग मार्जिन %**	**डंपिंग मार्जिन सीमा**
क.	चीन पीआर					
1	बीएएसएफ - वाईपीसी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
2	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	40-50
ख.	यूरोपीय संघ					
1	बीएएसएफ एंटवर्पेन एनवी	***	***	***	***	80-90
2	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	120-130
ग.	सऊदी अरब					
1	सदारा केमिकल कंपनी	***	***	***	***	10-20
2	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	20-30
घ.	ताइवान					
1	कोई उत्पादक	***	***	***	***	30-40

छ. <u>क्षति का आकलन और कारणात्मक संबंध</u>

छ.1 <u>अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुति</u>

60. विपक्षी हित-धारकों ने नुकसान के आकलन और कारण-संबंध के बारे में निम्नलिखित बातें कही हैं:

i. आयात केवल मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए बढ़ाए गए हैं, जबकि आवेदक के उत्पादन और बिक्री में कमी उनकी परिचालन संबंधी अक्षमताओं के कारण है।

ii. डाउनस्ट्रीम यूज़र्स मुख्य रूप से घरेलू सप्लाई में कमी के कारण इंपोर्ट पर निर्भर हैं, न कि कीमत की प्राथमिकता के कारण। जांच की अवधि के दौरान एप्लिकेंट की कम क्षमता के इस्तेमाल और बीच-बीच में प्रोडक्शन रुकने की वजह से यूज़र्स के पास दूसरे देशों से संबंधित प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

iii. ईडीए एक मानकीकृत वस्तु है जिसकी कीमतों में उतार-चढ़ाव अमोनिया और मोनोएथेनॉलमाइन (एमईए) जैसे प्रमुख कच्चे माल में होने वाले उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। आयातित और घरेलू उत्पादों के बीच आवधिक मूल्य अंतर बाजार-प्रेरित होते हैं और इन्हें मूल्यह्रास नहीं माना जा सकता।

iv. आवेदक की लागत संरचना अधिक होने का कारण उसकी अपनी अक्षमताएं और कच्चे माल के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भरता है। आयात की कम कीमतें वैश्विक उत्पादकों के 'बैकवर्ड इंटीग्रेशन' को दर्शाती हैं, न कि नुकसान पहुंचाने वाली कीमतों को।

v. 2023-24 और पीओआई के दौरान कीमतों में आई गिरावट, विचाराधीन उत्पाद की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में आई गिरावट के साथ मेल खाती है।

vi. विचाराधीन प्रोडक्ट की कीमतें ग्लोबल सप्लाई और डिमांड से तय होती हैं। चीन और यूरोपीय संघ में प्लांट बंद होने के कारण 2021-22 और 2022-23 में कीमतें बढ़ीं और प्रोडक्शन सामान्य होने पर 2023-24 में कीमतें गिर गईं। आवेदक की कीमतों में आई गिरावट इसी ग्लोबल ट्रेंड के अनुरूप है, और इस पर इम्पोर्ट का कोई असर नहीं पड़ा है।

vii. आवेदक ने माना कि 2022-23 में उत्पादन में बढ़ोतरी ज़्यादा एक्सपोर्ट की वजह से हुई थी, और उसके बाद उत्पादन में आई कमी किसी संरचनात्मक अक्षमता के बजाय एक रणनीतिक फ़ैसले का नतीजा है।

viii. आवेदक ने उचित कीमतों पर "राजस्व के नुकसान" का भी ज़िक्र किया है। यह हिसाब-किताब काल्पनिक है और इसके समर्थन में कोई विस्तृत गणना या सत्यापित डेटा नहीं दिया गया है।

ix. अलग-अलग देशों से होने वाले आयात की लैंडेड कीमत में काफी अंतर दिखता है; सबसे ज़्यादा और सबसे कम कीमत के बीच लगभग 17,000 रुपये प्रति MT का अंतर है, जिससे पता चलता है कि आयात एक जैसी कीमत पर मुकाबला नहीं करते हैं।

x. आवेदक की क्षमता का उपयोग तेज़ी से घटा, जिससे प्रति-इकाई निश्चित लागत बढ़ गई।

xi. इस अवधि के दौरान कच्चे माल की कीमतों में काफी बदलाव आया, जिससे लागत मार्जिन में भी बदलाव हुआ।

xii. 2023-24 के चेयरमैन के भाषण में जियोपॉलिटिकल तनाव, सप्लाई चेन में रुकावट और जलवायु से जुड़े जोखिमों जैसी चुनौतियों पर ज़ोर दिया गया, लेकिन डंपिंग को एक बड़ी चिंता के तौर पर नहीं बताया गया।

xiii. आवेदक पूरी तरह से आयातित मोनोएथेनॉलमाइन (एम ई ए) पर निर्भर है, जिसकी कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे होती रहती हैं। इस निर्भरता और कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण आवेदक की इनपुट और इन्वेंट्री लागत काफी बढ़ गई है। दुनिया भर के उन उत्पादकों के विपरीत जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हैं, आवेदक एक नॉन-इंटीग्रेटेड प्लांट चलाता है, जिससे उसे लागत के मामले में काफी नुकसान उठाना पड़ता है।

xiv. महाराष्ट्र के सोलापुर में आवेदक की सुविधा बंदरगाहों और पेट्रोकेमिकल हब से दूर है, जिसके कारण लॉजिस्टिक्स और इनलैंड फ्रेट (देश के भीतर माल ढुलाई) की लागत ज़्यादा आती है; इससे आयात से अलग, उत्पादन की लागत भी बढ़ जाती है।

xv. आवेदक ने जून 2019 में ही कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया। नुकसान की अवधि उसके कामकाज के शुरुआती सालों से मेल खाती है, जिसमें प्रोसेस को स्थिर करने, कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने और सप्लाई चेन बनाने जैसी शुरुआती कमियां शामिल थीं।

xvi. एथिलीन डायमाइन की ज़्यादा लागत एग्रोकेमिकल सेक्टर में निवेश और इनोवेशन पर असर डालेगी, जिससे ग्लोबल लेवल पर भारत की कॉम्पिटिटिवनेस कमज़ोर होगी।

xvii. इस मामले में, जापान, यूएसए और कोरिया आरपी जैसे देशों का अलग-अलग हिस्सा 3% से कम है, लेकिन उनका कुल हिस्सा 7.28% है, जो तय सीमा से ज़्यादा है। इसलिए, इन देशों को जांच में शामिल किया जाना चाहिए था।

xviii. इन देशों को बाहर रखना भेदभाव है, यह विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों के खिलाफ है और किसी भी एंटी-डंपिंग उपाय की प्रभावशीलता को कम करता है।

xix. आवेदक को कथित तौर पर हुए किसी भी नुकसान का मुख्य कारण चीन (पीआर) से होने वाला आयात है, न कि सऊदी अरब से।

xx. नुकसान के विश्लेषण में सभी ज़रूरी आर्थिक कारकों पर विचार किया जाना चाहिए, जिसमें आवेदक का निर्यात प्रदर्शन भी शामिल है। जांच की अवधि के दौरान आवेदक के निर्यात की मात्रा में कमी आई है। निर्यात की कीमतों में भी 35% की गिरावट आई है, जो अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में भारी दबाव का संकेत है।

xxi. जांच की अवधि के दौरान वेतन और मजदूरी 2021-22 की तुलना में 2.4 गुना से अधिक हैं।

xxii. इसी अवधि में लगाई गई पूंजी में 13% की वृद्धि हुई है, जबकि क्षमता का कोई विस्तार नहीं हुआ है।

xxiii. संबंधित देशों पर लगाए गए एंटी-डंपिंग शुल्क से केवल उन देशों को फ़ायदा होगा जिन पर ये शुल्क नहीं लगाए गए हैं, और इससे आवेदन करने वाले को कोई खास

राहत नहीं मिलेगी। घरेलू मांग और आपूर्ति के बीच काफ़ी अंतर है, इसलिए आयात करना ज़रूरी है।

xxiv. जापान, यूएसए, कोरिया आर पी, सिंगापुर और यूएई जैसे देशों से मिलने वाली कीमतें तुलना करने लायक या उनसे भी ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हैं। इसका मतलब है कि जिन देशों पर पाबंदी लगाने की बात हो रही है, उनसे होने वाले आयात पर कोई भी रोक लगाने से सिर्फ़ आयात का स्रोत बदल जाएगा, लेकिन कीमतों पर दबाव कम नहीं होगा।

xxv. काम या ज़िम्मेदारियों के बावजूद, आवेदक को वैसी ही प्रतिस्पर्धी चुनौतियों का सामना करना जारी रहेगा।

xxvi. घरेलू उद्योग का नुकसान होने का दावा बेबुनियाद है और यह नुकसान के बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए मार्जिन (सऊदी अरब के लिए 50-60% होने का दावा) पर आधारित है, जो एक गलत आधार से निकाला गया है।

xxvii. चोट या नुकसान का पूरा विश्लेषण 'नॉन-इंजुरियस प्राइस' (एन आई पी) पर आधारित है, जो अनुचित और कृत्रिम रूप से बढ़ाया गया है। दावा किया गया एन आई पी, सभी एक्सपोर्ट करने वाले देशों (जिनमें वे देश भी शामिल हैं जिन पर जांच लागू नहीं है) से होने वाले इम्पोर्ट की 'लैंडेड प्राइस' से काफी ज़्यादा है।

xxviii. इससे यह साबित होता है कि घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत असल में अव्यावहारिक है और उस पर वित्तीय दबाव आयात से मिलने वाली निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के कारण नहीं, बल्कि उसकी अपनी संरचनात्मक कमियों का नतीजा है।

xxix. इसके अलावा, जो भी नुकसान हुआ है, वह खुद की वजह से हुआ है। 2021-22 की तुलना में पी ओ आई के दौरान डी आई का सैलरी और वेज पर खर्च लगभग 2.5 गुना बढ़ गया और उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड में 13% की बढ़ोतरी हुई, जबकि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी में कोई बदलाव नहीं हुआ और प्रोडक्शन घट गया। लागत में यह बेहिसाब और संदिग्ध बढ़ोतरी उसके फाइनेंशियल दबाव का मुख्य कारण है और इसकी जांच होनी चाहिए।

xxx. सऊदी अरब से होने वाले आयात और कथित नुकसान के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। नुकसान की अवधि के दौरान सऊदी अरब से आयात की मात्रा 20% से ज़्यादा कम हुई है - यह 2021-22 में 13,587 मीट्रिक टन से घटकर पी ओ आई में 10,773 मीट्रिक टन हो गई है।

xxxi. भारत के कुल आयात में सऊदी अरब से होने वाले आयात की हिस्सेदारी भी 2021-22 के 42.01% से घटकर पी ओ आई में 25.27% रह गई है।

xxxii. नुकसान की असल वजह चीन (पी आर) से होने वाले आयात में भारी बढ़ोतरी है; नुकसान की अवधि के दौरान यह आयात सात गुना से ज़्यादा बढ़ गया और अब यह आयात का सबसे बड़ा स्रोत (36.50% हिस्सेदारी) बन गया है। संबंधित देश से आयात में हुई पूरी बढ़ोतरी के लिए सिर्फ़ चीन (पी आर) ही ज़िम्मेदार है।

xxxiii. भारत में ईडीए के लिए मांग और आपूर्ति के बीच एक बड़ा और बढ़ता हुआ अंतर है। घरेलू उद्योग की क्षमता इतनी नहीं है कि वह मांग का आधा हिस्सा भी पूरा कर सके, इसलिए डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए आयात करना ज़रूरी हो जाता है।

xxxiv. घरेलू उद्योग की अपनी निर्यात बिक्री की मात्रा और कीमतों में आई भारी गिरावट यह संकेत देती है कि कीमतों पर दबाव का कारण वैश्विक कीमतों में गिरावट है, न कि सऊदी अरब से डंप किया गया आयात।

छ.2 <u>आवेदक द्वारा प्रस्तुति</u>

61. आवेदक ने चोट के आकलन और कारण-संबंध के बारे में निम्नलिखित बातें कही हैं:

i. चीन में उत्पादकों ने अपनी घरेलू मांग से ज़्यादा क्षमता स्थापित की है। यह अतिरिक्त उत्पादन क्षमता भारतीय बाज़ार की कुल मांग से भी अधिक है, जिससे पता चलता है कि इसे निर्यात के लिए विकसित किया गया है।

ii. चीन और ताइवान से बहुत ज़्यादा और आक्रामक तरीके से हो रहे इंपोर्ट का पैटर्न साफ़ दिखाता है कि उनका बिज़नेस मॉडल अनुचित व्यापार तरीकों से दूसरे देशों के बाज़ार पर कब्ज़ा करना है, और अगर एंटी-डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाई गई, तो उनकी अतिरिक्त क्षमता भारत की ओर मोड़ दी जाएगी।

iii. इस मामले में कुल मिलाकर किए जाने वाले मूल्यांकन (संचयी मूल्यांकन) की कानूनी ज़रूरतें पूरी होती हैं। चूंकि किसी भी विरोधी पक्ष ने इस तरह के मूल्यांकन पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, इसलिए अथॉरिटी से अनुरोध है कि वह आयात के प्रभावों के कुल मूल्यांकन पर विचार करे।

iv. संबंधित देशों से विचाराधीन उत्पाद के डंप किए गए आयात की मात्रा में काफी बढ़ोतरी हुई है। नुकसान की अवधि के दौरान मांग में हुई बढ़ोतरी की तुलना में संबंधित देशों से आयात में कहीं ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है।

v. आयात की कीमत में बदलाव, उत्पादन लागत में हुए बदलाव के हिसाब से नहीं हुआ है। भारतीय बाज़ार पर कब्ज़ा करने के लिए निर्यातकों ने लागत में हुई कमी से कहीं ज़्यादा अपनी कीमतें कम की हैं।

vi. कम कीमत वाले आयात की भारी आवक के कारण, घरेलू उद्योग अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, जबकि उसके पास घरेलू मांग का 60% पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता मौजूद है।

vii. दूसरे देशों में एक्सपोर्ट की कीमत भारतीय बाज़ार की कीमतों से ज़्यादा है। संबंधित देशों के प्रोड्यूसर चुनिंदा डंपिंग करते हैं और दूसरे एक्सपोर्ट बाज़ारों की तुलना में भारतीय बाज़ार में कम कीमतें ऑफ़र करते हैं।

viii. भारतीय बाज़ार में एथिलीन डाई-अमाइन की कीमतें न तो भारत में विदेश मंत्रालय के आयात मूल्य को दर्शाती हैं और न ही वैश्विक विदेश मंत्रालय कीमतों को। घरेलू उद्योग ने यह भी स्थापित किया है कि भारतीय बाज़ार में कीमतें चुनिंदा रूप से कम हैं।

ix. घरेलू उद्योग के नुकसान पर बिक्री करने के बावजूद, कीमतों और लागत में काफी हद तक 'अंडरकटिंग' (यानी प्रतिस्पर्धियों से कम कीमत या लागत रखना) देखी जा रही है।

x. आयात की कीमत घरेलू उद्योग की वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है। डंप किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग की कीमतें कम हो रही हैं।

xi. घरेलू उद्योग के पास काफी मात्रा में अप्रयुक्त क्षमता मौजूद है।

xii. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता का उपयोग कम हो गया। नुकसान की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिक्री में लगातार गिरावट आई है।

xiii. बिक्री मूल्य में गिरावट, बिक्री की लागत में आई गिरावट से ज़्यादा थी, जिसके कारण कीमतों में भारी कमी आई और नुकसान हुआ। ऐसा डंपिंग और उससे हुए नुकसान की वजह से हुआ, न कि किसी आंतरिक नुकसान की वजह से।

xiv. संबंधित देशों से बड़े पैमाने पर डंपिंग के कारण घरेलू उद्योग अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहा है। योगदान नकारात्मक होने की वजह से, घरेलू उद्योग अपनी फिक्स्ड कॉस्ट (स्थिर लागत) भी वसूलने की स्थिति में नहीं है, और इसलिए इस उत्पाद का उत्पादन करने का कोई प्रोत्साहन नहीं है।

xv. संबंधित देशों से कम कीमत पर होने वाले आयात के कारण घरेलू उद्योग को समय-समय पर अपना उत्पादन रोकना पड़ा है।

xvi. घरेलू उद्योग का इन्वेंटरी (स्टॉक) काफी बढ़ गया।

xvii. घरेलू उद्योग को भारी नुकसान हुआ है। कैश प्रॉफ़िट और निवेश पर रिटर्न में गिरावट आई है।

xviii. संबंधित देशों से डंप किए गए आयात में वृद्धि के साथ घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई।

xix. संबंधित देशों से डंप किए गए आयात का कुल विकास पर नकारात्मक असर पड़ता है, जिससे घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता प्रभावित होती है।

xx. घरेलू उद्योग की निर्यात कीमत घरेलू कीमत से अधिक है और निर्यात से होने वाला लाभ घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को स्थापित करता है।

xxi. घरेलू उद्योग का लागत ढांचा भारत में मौजूदा बाज़ार की स्थितियों और इनपुट की कीमतों को पूरी तरह से दर्शाता है। हालांकि नुकसान की अवधि के दौरान कच्चे माल

की आयात कीमतों में गिरावट आई, लेकिन एथिलीन डाई अमीन की आयात कीमत में आई गिरावट, इनपुट की लागत में आई गिरावट से दोगुनी से भी ज़्यादा थी।

xxii. जब आयात की कीमत ज़्यादा थी, तब घरेलू उद्योग मुनाफ़े में था। आयात की कीमतों में लागत से भी कहीं ज़्यादा असामान्य गिरावट साफ़ तौर पर दिखाती है कि यह विदेशी उत्पादकों की नुकसान पहुँचाने वाली कीमत तय करने की नीति का नतीजा है, न कि घरेलू उद्योग की किसी अंदरूनी अक्षमता का।

xxiii. इस बात पर कि जापान, यूएसए और कोरिया आर पी का अलग-अलग हिस्सा 3% से कम है, लेकिन उनका कुल हिस्सा तय सीमा से ज़्यादा है। जापान और कोरिया आर पी से होने वाले इंपोर्ट की कीमत ज़्यादा है और वे कुल मांग का सिर्फ़ [4.5%] हिस्सा हैं, जबकि सऊदी अरब का हिस्सा [21%] है; इससे पता चलता है कि नुकसान इन देशों की वजह से हो रहा है, न कि उन देशों की वजह से जो इस दायरे में नहीं आते।

xxiv. हालांकि डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज़ का कहना है कि सप्लाई की कमी के कारण वे इम्पोर्ट पर निर्भर हैं, लेकिन घरेलू इंडस्ट्री के पास मांग का एक बड़ा हिस्सा पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। यूज़र्स ने माना है कि इम्पोर्ट मुख्य रूप से विदेशी उत्पादकों द्वारा दी जाने वाली बहुत कम कीमतों के कारण किया गया था। ग्राहक अक्सर इन कम कीमत वाले इम्पोर्ट का इस्तेमाल बातचीत के एक टूल के तौर पर करते थे, ताकि घरेलू इंडस्ट्री पर कीमतें टिकाऊ स्तर से नीचे लाने का दबाव बनाया जा सके।

xxv. इस बात पर कि घरेलू इंडस्ट्री की कीमतों में बदलाव ग्लोबल ट्रेंड्स के हिसाब से नहीं हैं, यह कहा गया है कि नुकसान वाली अवधि के दौरान इम्पोर्ट की लैंडेड कीमत में प्रति मीट्रिक टन 1,46,778 रुपये की भारी गिरावट आई, जबकि विदेश मंत्रालय इम्पोर्ट की कीमतों में प्रति मीट्रिक टन केवल 25,338 रुपये की कमी हुई, जिससे घरेलू इंडस्ट्री को अपनी कीमतें कम करने और नुकसान उठाने पर मजबूर होना पड़ा।

xxvi. यह आरोप लगाया जाता है कि घरेलू उद्योग की लागत संरचना (लागत संरचना) के ऊंचे होने का कारण अक्षमताएं और बैकवर्ड इंटीग्रेशन की कमी है। हालांकि, यह लागत संरचना भारत में मौजूदा बाजार की स्थितियों और इनपुट की कीमतों को दर्शाती है। यदि उच्च लागत संरचना नुकसान का कारण होती, तो घरेलू उद्योग को जांच की अवधि से पहले ही नुकसान उठाना पड़ता।

xxvii. इस तर्क पर कि "रेवेन्यू का नुकसान" काल्पनिक है, एंटी-डंपिंग नियमों के तहत, डंप किए गए इम्पोर्ट के बुरे असर का आकलन असल और संभावित बिक्री में गिरावट के आधार पर किया जाना चाहिए, और कानून बिक्री की मात्रा और मूल्य के बीच कोई अंतर नहीं करता है।

xxviii. जांच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग को रुपये [***] करोड़ का वास्तविक नुकसान हुआ, क्योंकि उचित कीमतों पर रुपये [***] करोड़ की संभावित बिक्री के मुकाबले वास्तविक बिक्री रुपये [***] करोड़ तक ही सीमित रही।

xxix. इस तर्क के जवाब में कि घरेलू उद्योग को नुकसान ज़्यादा लॉजिस्टिक्स और स्टार्ट-अप लागत की वजह से हुआ है, यह कहा जाता है कि ये हालात नुकसान वाली अवधि के दौरान भी बने रहे। ये कारक पहले के सालों में भी मौजूद थे, जब घरेलू उद्योग स्थिर और मुनाफ़े वाला बना रहा।

xxx. इस दावे के जवाब में कि सालाना रिपोर्ट घरेलू उद्योग पर असर डालने वाली दूसरी चुनौतियों को उजागर करती है, यह कहा जाता है कि 2024-25 की सालाना रिपोर्ट में साफ़ तौर पर बताया गया है कि डंप किए गए इंपोर्ट की वजह से घरेलू उद्योग के कामकाज पर असर पड़ा। इसलिए, इस नुकसान की वजह कोई और कारक नहीं हो सकता।

xxxi. इस तर्क पर कि सैलरी और मज़दूरी बढ़ गई हैं और यही नुकसान का कारण हैं: जांच की अवधि के दौरान सैलरी और मज़दूरी 2023-24 की तुलना में कम थीं (जब घरेलू इंडस्ट्री ने मुनाफ़ा कमाया था), इसलिए नुकसान के लिए सिर्फ़ सैलरी और मज़दूरी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

xxxii. यह कहना गलत है कि बिना किसी विस्तार के भी इस्तेमाल की गई क्षमता बढ़ गई, क्योंकि वर्किंग कैपिटल सिर्फ़ उस प्रोडक्ट पर निर्भर नहीं करती जिस पर विचार किया जा रहा है। नेट फिक्स्ड एसेट्स में बढ़ोतरी का मतलब हमेशा ज़्यादा क्षमता नहीं होता, क्योंकि इसका संबंध दूसरे ज़रूरी हिस्सों से भी हो सकता है जिनसे क्षमता नहीं बढ़ती। जांच की अवधि के दौरान, जिस प्रोडक्ट पर विचार किया जा रहा है, उसके लिए नेट फिक्स्ड एसेट्स और वर्किंग कैपिटल दोनों में कुल मिलाकर कमी आई। घरेलू और एक्सपोर्ट ऑपरेशन्स के बीच बंटवारा सेल्स वैल्यू के आधार पर किया जाता है।

छ.3 <u>प्राधिकरण द्वारा जांच</u>

62. एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 11 और उसके साथ एनेक्शर II के अनुसार, नुकसान का पता लगाने के लिए उन कारकों की जांच की जानी चाहिए जिनसे घरेलू उद्योग को नुकसान का संकेत मिल सकता है। इसमें "...सभी संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा, जैसे डंप किए गए आयात की मात्रा, घरेलू बाजार में वैसी ही वस्तुओं की कीमतों पर उनका असर, और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयात का नतीजा..."। कीमतों पर डंप किए गए आयात के असर पर विचार करते समय, यह जांचना ज़रूरी है कि क्या भारत में वैसी ही वस्तु की कीमत की तुलना में डंप किए गए आयात के कारण कीमतों में भारी कमी (प्राइस अंडरकटिंग) आई है, या क्या ऐसे आयात का असर कीमतों को काफी हद तक कम करने या

कीमतों में होने वाली संभावित बढ़ोतरी को काफी हद तक रोकने वाला रहा है। भारत में घरेलू उद्योग पर डंप किए गए आयात के असर की जांच के लिए, नियमों के एनेक्शर II के अनुसार उद्योग की स्थिति से जुड़े संकेतकों पर विचार किया गया है, जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, इन्वेंट्री, लाभप्रदता, शुद्ध बिक्री से प्राप्ति, डंपिंग का स्तर और मार्जिन आदि।

63. यह दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग 'बैकवर्ड इंटीग्रेटेड' नहीं है, जिससे लागत बढ़ रही है और घरेलू उद्योग को हो रहे नुकसान की वजह बैकवर्ड इंटीग्रेशन का न होना है। अथॉरिटी का कहना है कि घरेलू उद्योग ने 2020-21 और 2021-22 में मुनाफ़ा कमाया था। अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन का न होना घरेलू उद्योग के प्रदर्शन पर असर डालने वाला कोई कारण होता, तो घरेलू उद्योग को पहले भी नुकसान हुआ होता। अथॉरिटी ने 'यूरोपियन यूनियन - बायोडीज़ल (अर्जेंटीना)' मामले में अपीलेट बॉडी के फ़ैसले पर ध्यान दिया है, जिसमें यह कहा गया था कि अथॉरिटी को उन विशेषताओं के संबंध में 'नॉन-एट्रिब्यूशन एनालिसिस' (कारणों का विश्लेषण) करने की ज़रूरत नहीं है जो किसी उद्योग का स्वाभाविक हिस्सा हैं और नुकसान की अवधि के दौरान उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। हिस्सा लेने वाले उत्पादकों द्वारा दिए गए जवाबों से पता चला है कि उत्पाद को 'डंप की गई कीमतों' पर भारत में निर्यात किया गया है। इसी तरह, यह तथ्य कि सोलापुर, महाराष्ट्र में आवेदक की फ़ैसिलिटी बंदरगाहों और पेट्रोकेमिकल हब से दूर है - जिससे लॉजिस्टिक्स और इनलैंड फ्रेट (देश के भीतर ढुलाई) की लागत बढ़ जाती है और उत्पादन लागत भी ज़्यादा हो जाती है - जांच की अवधि में हुए नुकसान और पहले हुए मुनाफ़े को सही नहीं ठहराता है। इसलिए, अथॉरिटी का यह मानना नहीं है कि बताया गया नुकसान इस वजह से हुआ है कि घरेलू उद्योग 'बैकवर्ड इंटीग्रेटेड' नहीं है या इसकी लोकेशन (जगह) की वजह से ऐसा हुआ है।

64. इस बात पर कि घरेलू इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कम हुआ है, जिससे प्रोडक्शन की लागत बढ़ी है और नतीजतन नुकसान हुआ है, अथॉरिटी का मानना है कि प्रोडक्शन में कमी खुद घरेलू मार्केट में संबंधित सामान की डंपिंग का सीधा नतीजा है। जब घरेलू इंडस्ट्री को डंप किए गए इम्पोर्ट की वजह से वॉल्यूम पर बुरा असर पड़ रहा हो, तो इससे होने वाले नुकसान या बढ़ी हुई लागत को सिर्फ़ अंदरूनी कमियों या कम प्रोडक्शन से जोड़ना सही नहीं होगा। वॉल्यूम पर ऐसे बुरे असर डंप किए गए इम्पोर्ट की मौजूदगी से सीधे तौर पर जुड़े हैं, जिन्होंने घरेलू प्रोडक्शन को कम किया है और कैपेसिटी के इस्तेमाल को दबाया है। अथॉरिटी ने यह भी गौर किया कि संबंधित सामान की इम्पोर्ट कीमतें घरेलू इंडस्ट्री की प्रोडक्शन लागत से कम थीं, जिससे नुकसान और बढ़ गया। इन बातों को देखते हुए, अथॉरिटी का मानना है कि प्रोडक्शन में कमी और उसके कारण लागत में बढ़ोतरी को डंप किए गए इम्पोर्ट के असर से अलग नहीं किया जा सकता।

65. यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग ने अपनी सालाना रिपोर्ट में हुए नुकसान का मुख्य कारण भू-राजनीतिक तनाव, सप्लाई चेन में रुकावट और जलवायु से जुड़े जोखिमों को बताया है, और डंप किए गए इंपोर्ट को नुकसान का एक अहम कारण नहीं माना है। अथॉरिटी का मानना है कि संबंधित पक्षों ने सालाना रिपोर्ट का चुनिंदा हवाला दिया है; घरेलू उद्योग की 2024-25 की सालाना रिपोर्ट की जांच करने पर यह साफ है कि घरेलू उद्योग ने यह भी कहा है कि डंप किए गए इंपोर्ट की वजह से उसके कामकाज पर बुरा असर पड़ा है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, अथॉरिटी का मानना है कि संबंधित पक्षों का तर्क सही साबित नहीं होता है और इसलिए, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

66. इस बात पर कि जापान, कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका से होने वाला आयात कुल आयात का 7% है, आयात के आंकड़ों की जांच की गई है और यह पाया गया है कि इन आयातों का कुल हिस्सा कुल आयात के 6% से भी कम है।

67. इस बात पर कि दी जाने वाली सैलरी और वेज (मज़दूरी) में बढ़ोतरी हुई है, जिससे घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता था, अथॉरिटी ने पाया है कि घरेलू इंडस्ट्री में वेज 2023-24 तक तो बढ़े, लेकिन जांच की अवधि में इनमें कमी आई है। जांच की अवधि में सैलरी और वेज 2023-24 की तुलना में कम हैं और घरेलू इंडस्ट्री को जांच की अवधि में ज़्यादा नुकसान हुआ है। घरेलू इंडस्ट्री को हुए वित्तीय नुकसान की वजह सिर्फ़ वेज और सैलरी को नहीं माना जा सकता।

68. नियमों के अनुलग्नक II का पैरा (iii) आयात के सामूहिक विश्लेषण से संबंधित है। यह इस प्रकार है:

> *(iii) ऐसे मामलों में जहां एक से अधिक देशों से किसी उत्पाद के आयात पर एक साथ एंटीडंपिंग जांच चल रही हो, नामित प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन तभी करेगा, जब वह यह निर्धारित करे कि, -*
>
> *(क) प्रत्येक देश से आयात के संबंध में स्थापित डंपिंग मार्जिन निर्यात मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाने पर दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत है या जहां व्यक्तिगत*

देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, वहां आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात का सात प्रतिशत से अधिक है; और

(ख) आयातित उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों और आयातित उत्पादों तथा उसी तरह के घरेलू उत्पाद के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए, आयात के प्रभावों का सामूहिक मूल्यांकन करना उचित है।

69. यह पता लगाने के लिए कि क्या आयातित वस्तु और वैसी ही घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए आयात के असर का सामूहिक मूल्यांकन उचित है, निम्नलिखित पैमानों की जांच की गई है: -

क. अलग-अलग पार्टियों द्वारा सप्लाई किए गए उत्पाद एक जैसी वस्तुएं हैं और गुणों में उनकी तुलना की जा सकती है।

ख. देश में बने उत्पाद और आयातित उत्पाद एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

ग. घरेलू उत्पाद और आयातित उत्पाद के बीच सीधा मुकाबला है, और आयातित उत्पादों के आपस में भी मुकाबला है।

घ. उपभोक्ता घरेलू और आयातित सामग्री का एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं और निर्यातक तथा घरेलू उद्योग ने एक ही तरह के ग्राहकों को वही उत्पाद बेचा है।

ङ. संबंधित देशों से आयात की कीमतें एक साथ बदली हैं।

70. ऊपर दी गई बातों को ध्यान में रखते हुए, अथॉरिटी यह उचित समझती है कि संबंधित देशों से विचार-धीन उत्पाद के डंप किए गए आयात का घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले प्रभावों का सामूहिक रूप से आकलन किया जाए।

छ.3.1 <u>मांग/प्रतीत खपत का आकलन</u>

71. इस जांच के मकसद से, भारत में वैसी ही वस्तु की मांग या स्पष्ट खपत को इस तरह परिभाषित किया गया है: घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, भारत के दूसरे उत्पादक की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से विचाराधीन उत्पाद के आयात का कुल योग। इस तरह आंकी गई मांग नीचे दी गई तालिका में बताई गई है।

क्र. सं.	**विवरण**	**इकाई**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**POI**
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	एम टी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूची	100	95	90	66

3	अन्य भारतीय उत्पादक की बिक्री	एम टी	-	-	-	-
4	प्रवृत्ति	सूची	-	-	-	-
5	विषय देशों से आयात	एम टी	24,304	19,729	27,583	36,207
6	प्रवृत्ति	सूची	100	81	113	149
7	अन्य देशों से आयात	एम टी	1,545	952	1,682	2,302
8	प्रवृत्ति	सूची	100	62	109	149
9	मांग/उपभोग	एम टी	***	***	***	***
10	प्रवृत्ति	सूची	100	85	106	124

72. देखा गया है कि 2021-22 की तुलना में 2022-23 में मांग में कमी आई। 2023-24 में मांग बढ़ी और जांच की अवधि के दौरान इसमें और वृद्धि हुई। नुकसान की अवधि के दौरान मांग में बढ़ोतरी हुई है।

छ.3.2 <u>डंप किए गए आयात का मात्रात्मक प्रभाव</u>

73. आयात की मात्रा के संबंध में, अथॉरिटी को यह विचार करना होगा कि क्या संबंधित देश से डंप किए गए आयात में कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है - चाहे वह कुल मात्रा के संदर्भ में हो या भारत में उत्पादन या खपत के अनुपात में। इसका विश्लेषण नीचे दी गई तालिका में किया गया है।

क्र. सं.	**विवरण**	**इकाई**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**POI**
1	विषय देशों से आयात	एम टी	24,304	19,729	27,583	36,207
2	अन्य देशों से आयात	एम टी	1,545	952	1,682	2,302
3	विषय देश से आयात निम्न के संबंध में					
क	भारत उत्पादन	%	***	***	***	***
ख	प्रवृत्ति	सूची	100	63	152	236
ग	भारतीय मांग	%	***	***	***	***
घ	प्रवृत्ति	सूची	100	96	107	120
ङ	कुल आयात	%	94%	95%	94%	94%

74. भारतीय उत्पादन के मुकाबले आयात 2022-23 में घटा, लेकिन 2023-24 में बढ़ गया। जांच की अवधि में आयात और भी बढ़ा। इसी तरह, भारतीय मांग के मुकाबले आयात 2022-23

में घटा, लेकिन 2023-24 में बढ़ा और उसके बाद जांच की अवधि में और भी बढ़ गया। यह देखा गया है कि नुकसान की अवधि के दौरान उत्पादन और मांग के मुकाबले आयात में बढ़ोतरी हुई है। इसलिए अथॉरिटी का मानना है कि भारत में मांग में हुई बढ़ोतरी की तुलना में आयात में बढ़ोतरी ज़्यादा थी।

75. नुकसान की अवधि के दौरान, कुल आयात के मुकाबले संबंधित देशों से आयात का स्तर लगभग एक जैसा ही बना रहा है।

छ.3.3 <u>डंप किए गए आयात का कीमत पर असर</u>

76. एसोसिएटेड इंपोर्ट के ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज़ पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे समझने के लिए संबंधित देश से जुड़े इंपोर्ट की वजह से फ़्लोरिडा अंडरकटिंग, पीएआरएम सप्रेशन और वैल्युएशन न्यूट्रिशन (यदि कोई हो) की जांच की गई है। इस एनालिसिस के लिए, घरेलू उद्योग के प्रोडक्शन कास्ट, नेट सेल रियलाइजेशन (एनएसआर) और नॉन-इंजुरियस प्रॉपर्टीज (एनआईपी) की तुलना संबंधित देश से आने वाले संबंधित सामान के इंपोर्ट की लैंड्रेड प्रॉजेक्ट से की गई है।

क. आयात मूल्य में बदलाव

77. नीचे दी गई तालिका में आयात मूल्य और कच्चे माल की कीमत में बदलाव को दिखाया गया है। विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए मुख्य कच्चा माल 'मोनोएथेनॉल एमाइन्स' है और घरेलू उद्योग ने भारत में इन उत्पादों के आयात मूल्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है।

क्र. सं.	**विवरण**	**इकाई**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**POI**
1	मोनोएथेनॉल अमाइन्स	रुपये/ एम टी	1,23,463	1,48,801	1,00,006	1,02,139
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	121	81	83
3	आयात मूल्य	रुपये/ एम टी	2,22,039	3,49,881	1,69,299	1,30,886
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	158	76	59

78. देखा गया है कि 2022-23 में कच्चे माल की कीमतें बढ़ीं और इस दौरान आयात की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई। 2023-24 में कच्चे माल की कीमतें घटीं और जांच की अवधि के दौरान स्थिर रहीं। हालांकि, 2023-24 में आयात की कीमत में गिरावट आई और उसके बाद जांच की अवधि में इसमें और कमी आई है।

79. नुकसान वाली अवधि में कच्चे माल की कीमतों में 17% की गिरावट आई, जबकि जांच की अवधि में आयात की कीमतों में 41% की गिरावट आई है। अथॉरिटी का मानना है कि आयात की कीमतें कच्चे माल की कीमतों के हिसाब से नहीं बदली हैं, और उनमें कच्चे माल की कीमतों में आई गिरावट की तुलना में कहीं ज़्यादा गिरावट आई है। इसलिए, यह तर्क सही नहीं है कि विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में बदलाव, अमोनिया और मोनोएथेनॉलमाइन (विदेश मंत्रालय) जैसे मुख्य कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के अनुरूप है।

ख. कीमत कम करना

80. प्राइस अंडरकटिंग (कीमत कम करने) के विश्लेषण के लिए, घरेलू उद्योग की शुद्ध बिक्री कीमत की तुलना संबंधित देशों से होने वाले आयात की लैंडेड कीमत से की गई है। इसके अनुसार, संबंधित देशों से डंप किए गए आयात की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	**विवरण**	**इकाई**	**चीन पी आर**	**यूरोपीय संघ**	**सऊदी अरब**	**ताइवान**	**भारित औसत**
1	आयात मात्रा	MT	12,414	11,615	10,691	1,486	36,207
2	शुद्ध बिक्री	रुपये/ एम टी	***	***	***	***	***
3	लैंडेड मूल्य	रुपये/ एम टी	1,43,206	1,45,544	1,34,946	1,47,265	1,41,684
4	मूल्य अंडरकटिंग	रुपये/ एम टी	***	***	***	***	***
5	मूल्य अंडरकटिंग	%	10%	8%	16%	7%	11%

81. प्राधिकरणका मानना है कि जिन सामानों का आयात किया जा रहा है, वे घरेलू इंडस्ट्री की कीमतों से कम कीमत पर बेचे जा रहे हैं और यह कीमत का अंतर (प्राइस अंडरकटिंग) पॉजिटिव और काफी ज़्यादा है। यह कीमत का अंतर तब भी पॉजिटिव है, जब घरेलू इंडस्ट्री इस प्रोडक्ट को नुकसान उठाकर बेच रही है।

ग. कीमतों को दबाना/कम करना

82. यह पता लगाने के लिए कि क्या डंप किए गए आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं और क्या ऐसे आयात का असर कीमतों को काफी हद तक दबाने या उन कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने का है जो सामान्य तौर पर होतीं, नुकसान की अवधि के दौरान लागत और कीमतों में हुए बदलावों की तुलना नीचे दिए गए तरीके से की जाती है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	विक्रय मूल्य	रुपये/ एम टी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	125	68	59
3	परिवर्तन	रुपये/ एम टी	***	***	***	***
4	बिक्री लागत	रुपये/ एम टी	***	***	***	***
5	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	121	90	89
6	परिवर्तन	रुपये/ एम टी	***	***	***	***
7	लैंडेड मूल्य	रुपये/ एम टी	2,40,358	3,78,746	1,83,266	1,41,684
8	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	158	76	59
9	परिवर्तन	रुपये/ एम टी				

83. यह देखा गया है कि,

क. 2022-23 में, बिक्री की लागत 21 इंडेक्स पॉइंट बढ़ी, जबकि बिक्री मूल्य भी 25 इंडेक्स पॉइंट बढ़ा।

ख. 2023-24 में, बिक्री की लागत में 31 इंडेक्स पॉइंट की कमी आई, जबकि बिक्री मूल्य में 57 इंडेक्स पॉइंट की गिरावट हुई। इस साल घरेलू उद्योग को मामूली नुकसान उठाना पड़ा।

ग. जांच की अवधि में, जहां बिक्री की लागत में 1 इंडेक्स पॉइंट की कमी आई है, वहीं बिक्री मूल्य में 9 इंडेक्स पॉइंट की कमी आई है।

घ. हालांकि 2022-23 और 2023-24 के दौरान इंपोर्ट की 'लैंडेड कीमत' (देश में पहुँचने पर कुल लागत) घरेलू इंडस्ट्री की लागत और बिक्री कीमत से ज़्यादा बनी रही, लेकिन 'जांच की अवधि' (पीओआई) के दौरान इसमें भारी गिरावट आई। खास तौर पर, लैंडेड कीमत 2023-24 की पहली छमाही में ₹2,22,342 प्रति मीट्रिक टन से गिरकर उसी साल की दूसरी छमाही में ₹1,37,460 प्रति मीट्रिक टन हो गई (जो पीओआई की पहली छमाही

भी है, जिससे एक ओवरलैपिंग अवधि बनती है)। इसके उलट, पीओआई की दूसरी छमाही के दौरान लैंडेड कीमत में थोड़ी रिकवरी हुई और यह बढ़कर ₹1,43,965 प्रति मीट्रिक टन हो गई।

ङ. ठीक पिछले साल की तुलना में, जांच की अवधि के दौरान बिक्री मूल्य में गिरावट आई, लेकिन लैंडेड प्राइस (आयातित माल की लागत) में गिरावट की दर ज़्यादा थी। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतें कम बनी हुई हैं।

84. प्राधिकरणका का मानना है कि जांच की अवधि के दौरान, आयातित सामान की 'लैंडेड कीमत' (आयात लागत) के कारण घरेलू उद्योग उचित और लाभकारी कीमतें नहीं वसूल पाया। इसलिए, आयातित सामान की लैंडेड कीमत ने घरेलू उद्योग की कीमतों को दबाया और कम किया है। 2023-24 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में लैंडेड कीमत, 2023-24 की दूसरी छमाही (अक्टूबर-मार्च) की तुलना में काफी ज़्यादा है; ये दोनों ही जांच की अवधि (POI) का हिस्सा हैं। इस अवधि के दौरान बिक्री की कीमत लैंडेड कीमत से कम रही है, जिससे नुकसान और बढ़ गया है।

छ.3.4 <u>घरेलू उद्योग के आर्थिक पैरामीटर</u>

85. नियमों के अनुलग्नक II के अनुसार, नुकसान का पता लगाने के लिए ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर डंप किए गए आयात के असर की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर डंप किए गए आयात के असर के संबंध में, नियम यह भी कहते हैं कि घरेलू उद्योग पर डंप किए गए आयात के असर की जांच में उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले सभी संबंधित आर्थिक कारकों और सूचकांकों का निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। इसमें बिक्री, मुनाफ़े, उत्पादन, बाज़ार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर रिटर्न या क्षमता के इस्तेमाल में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों पर असर डालने वाले कारक; डंपिंग मार्जिन का स्तर; और कैश फ़्लो, इन्वेंट्री, रोज़गार, वेतन, विकास और पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक असर शामिल हैं। घरेलू उद्योग से जुड़े नुकसान के विभिन्न पैमानों पर नीचे चर्चा की गई है।

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता का उपयोग और बिक्री की मात्रा।

86. नुकसान की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता के उपयोग का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	क्षमता	एम टी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	100	100
3	उत्पादन	एम टी	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	130	75	63
5	क्षमता उपयोग - संयंत्र	%	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	129	75	64
7	घरेलू बिक्री	एम टी	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	96	90	66
9	निर्यात बिक्री	एम टी	***	***	***	***
10	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	244	12	8

87. यह देखा गया है कि:

क. नुकसान की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता एक जैसी बनी रही। यह देखा गया है कि क्षमता केवल विचाराधीन उत्पाद के लिए ही समर्पित नहीं है।

ख. जब प्लांट पूरी क्षमता से काम करता है, तो आवेदक का प्लांट इतना प्रोडक्ट बना सकता है कि घरेलू बाज़ार की 60% मांग पूरी हो सके। घरेलू इंडस्ट्री ने सबूत दिए हैं कि नया प्लांट लगाने के लिए उन्हें पर्यावरण मंज़ूरी तो मिल गई थी, लेकिन नुकसान होने की वजह से इस प्लान को रोक दिया गया है।

ग. 2021-22 की तुलना में 2022-23 में घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता के इस्तेमाल में बढ़ोतरी हुई। 2023-24 में, संबंधित देश से आयात की मात्रा बढ़ने के साथ घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता के इस्तेमाल में गिरावट आई। जांच की अवधि के दौरान, 2023-24 की तुलना में उत्पादन और क्षमता के इस्तेमाल में और गिरावट आई है।

घ. 2021-22 की तुलना में 2022-23 में घरेलू इंडस्ट्री की घरेलू बिक्री में गिरावट आई। 2023-24 और जांच की अवधि के दौरान घरेलू बिक्री में और गिरावट आई। जहां मांग बढ़ी है, वहीं घरेलू बिक्री में कमी आई है। यह देखा गया है कि घरेलू इंडस्ट्री की घरेलू बिक्री में गिरावट आई है, जबकि वे अपनी काफी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे (यानी काफी क्षमता खाली पड़ी थी) ।

ङ. नुकसान की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिक्री में गिरावट आई है।

च. घरेलू उद्योग की एक्सपोर्ट बिक्री में भी गिरावट आई है, लेकिन यह अब भी मुनाफ़े वाली बनी हुई है। अथॉरिटी ने घरेलू उद्योग के इस तर्क पर ध्यान दिया है कि वह एक्सपोर्ट

बिक्री पर निर्भर नहीं है और ऐसा केवल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वे घरेलू बाज़ार में बिक्री करने में असमर्थ हैं।

ख. सभी सप्लायर्स की मार्केट हिस्सेदारी

88. घरेलू उद्योग, भारत में अन्य उत्पादकों और भारत में उत्पादों के आयात का बाज़ार हिस्सा नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	113	85	53
3	अन्य घरेलू उत्पादक	%	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	-	-	-	-
5	विषय देशों से आयात	%	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	96	107	120
7	अन्य देशों से आयात	%	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	73	102	120

89. ऊपर दी गई बातों के आधार पर, अथॉरिटी यह नोट करती है कि:

क. घरेलू उद्योग की बाज़ार हिस्सेदारी 2022-23 में बढ़ी, 2023-24 में घटी और उसके बाद जांच की अवधि में फिर से घट गई।

ख. 2022-23 में संबंधित आयात का बाज़ार हिस्सा मामूली रूप से घटा, उसके बाद 2023-24 में बढ़ा और जांच की अवधि में और भी बढ़ गया।

ग. मांग का [***] हिस्सा पूरा करने की क्षमता होने के बावजूद, घरेलू उद्योग घरेलू बाज़ार का केवल [***] % ही पूरा कर पा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग ने कहा है कि हालांकि उसने क्षमता बढ़ाने के लिए ज़रूरी मंज़ूरी ले ली है, लेकिन ऐसा विस्तार नहीं किया गया है, क्योंकि मौजूदा क्षमता का बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है।

ग. इन्वेंटरी

90. इन्वेंटरी से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	POI
1	प्रारंभिक स्टॉक	एम टी	***	***	***	***

2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	92	228	109
3	समापन स्टॉक	एम टी	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	248	254	509
5	औसत स्टॉक	एम टी	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	167	240	301

91. यह देखा गया है कि नुकसान की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत इन्वेंट्री में बढ़ोतरी हुई है। जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत इन्वेंट्री तब भी बढ़ी, जब संबंधित उत्पाद की मांग में बढ़ोतरी हुई थी। घरेलू उद्योग ने बताया है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान उनके पास मौजूद इन्वेंट्री में 200% की बढ़ोतरी हुई है।

घ. मुनाफ़ा कमाने की क्षमता, नकद मुनाफ़ा और लगाई गई पूँजी पर रिटर्न।

92. नुकसान की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, लगाई गई पूंजी पर रिटर्न और नकद लाभ नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं: -

क्र. सं.	**विवरण**	**इकाई**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**POI**
1	लाभ/(हानि)	रुपये/ एम टी	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	137	-1	-30
3	लाभ/(हानि)	रुपये लाख	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	132	-0	-20
5	PBIT (ब्याज एवं कर पूर्व लाभ)	रुपये लाख	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	123	3	-15
7	नकद लाभ	रुपये लाख	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	128	11	-7
9	निवेश पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
10	प्रवृत्ति (Trend)	सूचकांक	100	116	2	-14

93. यह देखा गया है कि,

क. 2022-23 में जब इंपोर्ट कम हुआ, तो घरेलू इंडस्ट्री का प्रति यूनिट प्रॉफ़िट बढ़ गया। 2023-24 में प्रॉफ़िट में भारी गिरावट आई और यह नुकसान में बदल गया, और जांच की अवधि में यह नुकसान और भी बढ़ गया है।

ख. 2022-23 में मुनाफ़ा बढ़ा और उसके बाद जांच की अवधि तक इसमें गिरावट आई, जिसके चलते भारी नुकसान हुआ।

ग. घरेलू उद्योग का ब्याज और टैक्स से पहले का मुनाफ़ा और कैश मुनाफ़ा 2022-23 में बढ़ा, लेकिन उसके बाद जांच की अवधि तक इसमें गिरावट आई; जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को कैश नुकसान और ब्याज से पहले नुकसान उठाना पड़ा।

घ. घरेलू उद्योग के निवेश पर रिटर्न 2022-23 में बढ़ा, 2023-24 में इसमें भारी गिरावट आई और यह नेगेटिव हो गया, और उसके बाद जांच की अवधि में इसमें और गिरावट आई।

ङ. घरेलू उद्योग की मौजूदा कीमतें उत्पादन लागत से कम हैं, जिसके कारण नुकसान हो रहा है।

ङ. रोज़गार, उत्पादकता और वेतन

94. नीचे दी गई तालिका में नुकसान की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग में रोज़गार, उत्पादकता और मज़दूरी का विवरण दिया गया है।

क्र. सं.	**विवरण**	**इकाई**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**POI**
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
2	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	131	142	144
3	प्रति दिन उत्पादकता	एम टी /दिन	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	113	113	111
5	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एम टी /संख्या	***	***	***	***
6	प्रवृत्ति	संख्या	100	99	42	44
7	मजदूरी	रुपये लाख	***	***	***	***
8	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	158	312	241

95. यह देखा गया है कि:

क. नुकसान की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई।

ख. 2022-23 में प्रति दिन उत्पादकता बढ़ी, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट आई है।

ग. चोट लगने की अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी उत्पादकता में लगातार गिरावट आई है।

घ. घरेलू उद्योग द्वारा दी जाने वाली मजदूरी में 2021-22 की तुलना में POI के दौरान बढ़ोतरी हुई है।

च. विकास

96. नीचे दी गई तालिका नुकसान की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के विकास के पैरामीटर दिखाती है।

क्र. सं.	**विवरण**	**इकाई**	**2022-23**	**2023-24**	**POI**
1	उत्पादन	%	30%	-42%	-16%
2	क्षमता उपयोग	%	29%	-42%	-14%
3	घरेलू बिक्री	%	-4%	-6%	-28%
4	प्रति इकाई PBT	%	37%	-100%	-5718%
5	प्रति इकाई नकद लाभ	%	33%	-91%	-186%
6	प्रति इकाई PBIT	%	28%	-98%	-876%
7	निवेश पर प्रतिफल	%	16%	-98%	-844%
8	स्टॉक	%	67%	44%	25%

97. जांच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग के वॉल्यूम पैरामीटर और सभी प्राइस पैरामीटर (जैसे मुनाफ़ा, कैश मुनाफ़ा, ब्याज और टैक्स से पहले का मुनाफ़ा और लगाई गई पूंजी पर रिटर्न) में काफ़ी नकारात्मक वृद्धि देखी गई है। ये पैरामीटर उस स्तर के आस-पास भी नहीं रहे, जिस पर उन्हें होना चाहिए था। घरेलू उद्योग ने सबसे पहले 2023-24 में वॉल्यूम और प्राइस पैरामीटर दोनों में नकारात्मक वृद्धि का अनुभव किया, जो जांच की अवधि के दौरान भी जारी रही।

छ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

98. अथॉरिटी ने देखा है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ है। यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा लगाई गई पूंजी पर रिटर्न नेगेटिव है, जिससे पूंजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता पर असर पड़ेगा।

99. प्रोडक्ट की बढ़ती मांग को देखते हुए, घरेलू इंडस्ट्री ने अपनी कुल क्षमता को [***] मीट्रिक टन (जिसमें विचाराधीन प्रोडक्ट के अलावा अन्य प्रोडक्ट भी शामिल हैं) तक बढ़ाने की मंज़ूरी ले ली थी। घरेलू इंडस्ट्री भारी निवेश करके अपनी क्षमता बढ़ाना चाहती है। इतने बड़े वित्तीय

नुकसान के कारण, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतों के लिए पूंजी जुटाने की क्षमता पर भी असर पड़ा है।

ज. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

100. अथॉरिटी ने पाया कि जांच की अवधि के दौरान, संबंधित आयात की 'लैंडेड कीमत' (आयातित माल की देश में पहुंचने पर कुल लागत) घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री मूल्य से कम थी। संबंधित आयात की इस लैंडेड कीमत ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर दिया है, जिससे घरेलू उद्योग को मात्रा और कीमत, दोनों ही पैमानों पर काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए, डंप किए गए आयात ही घरेलू उद्योग की कीमतों पर असर डालने वाले मुख्य कारक हैं। घरेलू उद्योग ने ग्राहकों के साथ हुई बातचीत के ऐसे सबूत पेश किए हैं जिनसे पता चलता है कि ग्राहकों ने घरेलू उद्योग के साथ मोल-भाव करने के लिए आयातित माल की कीमत का हवाला दिया और उन पर आयातित माल की कीमतों के बराबर अपनी कीमतें कम करने का दबाव डाला।

झ. डंपिंग का पैमाना

101. डंपिंग की मात्रा इस बात का संकेत है कि भारत में किस हद तक आयात की डंपिंग हो रही है। जांच से पता चला है कि जांच की अवधि के दौरान डंपिंग मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

छ.3.5 चोट के संबंध में अवलोकन

102. विचाराधीन उत्पाद के आयात और घरेलू उद्योग के प्रदर्शन की जांच से पता चलता है कि:

क. संबंधित देशों से आयात आधार वर्ष के 24,304 MT से बढ़कर 36,207 MT हो गया है। आयात में वास्तविक मात्रा के हिसाब से वृद्धि हुई है।

ख. प्रोडक्शन के मुकाबले इंपोर्ट, बेस ईयर में ***% से बढ़कर जांच की अवधि में ***% हो गया। खपत के मुकाबले इंपोर्ट, बेस ईयर में ***% से बढ़कर जांच की अवधि में ***% हो गया। रिलेटिव टर्म्स में इंपोर्ट बढ़ा है।

ग. लैंडेड कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, जिसके परिणामस्वरूप पॉजिटिव प्राइस अंडरकटिंग होती है।

घ. जांच की अवधि के दौरान, लैंडेड कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रही है। नतीजतन, घरेलू उद्योग लागत में आए बदलावों के हिसाब से अपनी कीमतें समायोजित नहीं कर पाया है। जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतें कम बनी रहीं।

ङ. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता के उपयोग में गिरावट आई।

च. नुकसान की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाज़ार हिस्सेदारी में गिरावट आई है।

छ. इंजरी की अवधि के दौरान औसत इन्वेंट्री में वृद्धि हुई।

ज. 2022-23 में घरेलू उद्योग का मुनाफ़ा कम हुआ है और जांच की अवधि में यह नुकसान में बदल गया है। प्रति यूनिट मुनाफ़ा *** रुपये प्रति मीट्रिक टन से घटकर *** रुपये प्रति MT का नुकसान हो गया है।

झ. इसी तरह, 2022-23 में घरेलू उद्योग के कैश प्रॉफ़िट और लगाई गई पूंजी पर रिटर्न में गिरावट आई और उसके बाद जांच की अवधि में ये नेगेटिव हो गए।

ञ. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को वॉल्यूम और कीमत, दोनों पैमानों पर बढ़ोतरी के मामले में नुकसान उठाना पड़ा।

ट. घरेलू उद्योग की पूंजी जुटाने की क्षमता पर बुरा असर पड़ा है।

ठ. डंप किए गए आयात ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित किया है।

ड. जांच की अवधि के दौरान डंपिंग मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

ज. <u>श्रेय न देना और कारण-संबंध</u>

103. नियमों के अनुसार, डंप किए गए आयात के अलावा अन्य ज्ञात कारकों की भी जांच करना ज़रूरी है जो घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा रहे हों, ताकि इन अन्य कारकों से होने वाले नुकसान को डंप किए गए आयात के कारण हुआ नुकसान न माना जाए। नीचे इस बात की जांच की गई है कि क्या डंप किए गए आयात के अलावा अन्य कारकों ने भी घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाने में भूमिका निभाई है। अथॉरिटी शुरू में यह नोट करती है कि एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने के लिए न तो एक्ट और न ही नियमों में यह ज़रूरी है कि डंपिंग ही घरेलू उद्योग को नुकसान का एकमात्र कारण हो।

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

104. अथॉरिटी का कहना है कि संबंधित देशों के अलावा, जापान, कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका से होने वाला कुल आयात, कुल आयात का 6% से भी कम है।

ख. मांग में संकुचन

105. प्राधिकरण का मानना है कि नुकसान की अवधि के दौरान मांग बढ़ी है, इसलिए घरेलू उद्योग को हुए नुकसान का कारण मांग में कमी नहीं है।

ग. उपभोग के पैटर्न में बदलाव

106. प्राधिकरण का मानना है कि विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई ऐसा महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है, जिससे घरेलू उद्योग को नुकसान पहुँचा हो।

घ. व्यापार को सीमित करने वाले तौर-तरीके

107. प्राधिकरण का मानना है कि विचाराधीन उत्पाद की बिक्री पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है और प्राधिकरण के ध्यान में ऐसी कोई प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया नहीं लाई गई है।

ङ. टेक्नोलॉजी में विकास

108. प्राधिकरण यह नोट करता है कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन हेतु प्रयुक्त प्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।"

च. उत्पादकता

109. उत्पादन में कमी के साथ-साथ, प्रति कर्मचारी उत्पादन में भी कमी आई है।

छ. निर्यात प्रदर्शन

110. प्राधिकरण का मानना है कि ऊपर बताई गई नुकसान की जानकारी सिर्फ़ घरेलू बाज़ार में घरेलू इंडस्ट्री के परफ़ॉर्मेंस से जुड़ी है। इसलिए, घरेलू इंडस्ट्री को हुए नुकसान का कारण उसके एक्सपोर्ट परफ़ॉर्मेंस को नहीं माना जा सकता। अथॉरिटी ने देखा है कि पिछले साल की तुलना में जांच की अवधि में एक्सपोर्ट बिक्री में कमी आई है। हालांकि, एक्सपोर्ट से अभी भी मुनाफ़ा हो रहा है। इसलिए, घरेलू बाज़ार में बताए गए नुकसान का कारण एक्सपोर्ट परफ़ॉर्मेंस नहीं हो सकता।

ज. अन्य उत्पादों का प्रदर्शन

111. प्राधिकरण ने केवल संबंधित सामान के परफ़ॉर्मेंस से जुड़े डेटा पर विचार किया है। इसलिए, घरेलू इंडस्ट्री को हुए नुकसान का कारण अन्य उत्पादित और बेचे गए उत्पादों का परफ़ॉर्मेंस नहीं हो सकता है।

झ. <u>चोट की गंभीरता का स्तर</u>

112. प्राधिकरण ने नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के साथ एनेक्ज़र III में बताए गए सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए 'नॉन-इंजुरियस प्राइस' (ऐसा मूल्य जिससे नुकसान न हो) तय किया है। संबंधित सामान का नॉन-इंजुरियस प्राइस, जांच की अवधि के दौरान उत्पादन लागत से जुड़ी वेरिफाइड जानकारी/डेटा का इस्तेमाल करके तय किया गया है। 'इंजुरी मार्जिन' (नुकसान का अंतर) की गणना करने के लिए संबंधित देशों से आने वाले सामान की 'लैंडेड प्राइस' (आयातित सामान की लागत) से तुलना करने के लिए नॉन-इंजुरियस प्राइस को आधार माना गया है। नॉन-इंजुरियस प्राइस तय करने के लिए, नुकसान वाली अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल के सबसे अच्छे इस्तेमाल को ध्यान

में रखा गया है। यूटिलिटीज़ (जैसे बिजली, पानी आदि) के मामले में भी यही तरीका अपनाया गया है। नुकसान वाली अवधि के दौरान प्रोडक्शन कैपेसिटी (उत्पादन क्षमता) के सबसे अच्छे इस्तेमाल को भी ध्यान में रखा गया है। यह पक्का किया गया है कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण या बार-बार न होने वाला खर्च शामिल न किया जाए। नियमों के एनेक्ज़र III में बताए अनुसार, नॉन-इंजुरियस प्राइस तक पहुंचने के लिए संबंधित सामान पर इस्तेमाल की गई औसत पूंजी (यानी औसत नेट फिक्स्ड एसेट्स और औसत वर्किंग कैपिटल) पर 22% का उचित रिटर्न (ब्याज, टैक्स और मुनाफे के लिए) माना गया है।

113. सहयोग करने वाले निर्यातकों के लिए 'लैंडेड प्राइस' (आयातित माल की लागत) का निर्धारण उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर किया गया है। आयात की लैंडेड प्राइस तय करने के लिए लागू कस्टम ड्यूटी को इसमें जोड़ा गया है। संबंधित देशों के उन उत्पादकों/निर्यातकों के लिए जो सहयोग नहीं कर रहे हैं, अथॉरिटी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर लैंडेड प्राइस तय की है।

114. ऊपर तय की गई लैंडेड कीमत और नॉन-इंजुरियस कीमत के आधार पर, अथॉरिटी ने संबंधित देशों के प्रोड्यूसर्स/एक्सपोर्टर्स के लिए इंजुरी मार्जिन तय किया है और इसे नीचे दी गई टेबल में बताया गया है:

क्र.सं.	**उत्पादक/निर्यातक**	**अहानिकर मूल्य**	**अवतरित मूल्य**	**क्षति मार्जिन**	**%**	**सीमा**
क	**चीन**					
1	बीएएसएफ-वाईपीसी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
2	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	30-40
ख	**यूरोपीय संघ**					
1	बीएएसएफ एंटवर्पेन एनवी	***	***	***	***	20-30
2	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	50-60
ग	**सऊदी अरब**					
1	सदारा केमिकल कंपनी	***	***	***	***	10-20
2	कोई अन्य उत्पादक	***	***	***	***	20-30
घ	**ताइवान**					
1	कोई भी उत्पादक	***	***	***	***	10-20

ञ. भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे

ञ.1 विरोधी हितधारक पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन

115. विरोधी पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित बातें कही हैं:

क. डाउनस्ट्रीम यूज़र्स मुख्य रूप से घरेलू सप्लाई में कमी के कारण इंपोर्ट पर निर्भर हैं। जांच की अवधि के दौरान एप्लिकेंट की कम क्षमता के इस्तेमाल और बीच-बीच में प्रोडक्शन रुकने की वजह से यूज़र्स के पास विदेश से सामान मंगाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा।

ख. ईडीए की ज़्यादा लागत एग्रोकेमिकल सेक्टर में निवेश और इनोवेशन पर असर डालेगी, जिससे ग्लोबल लेवल पर भारत की कॉम्पिटिटिवनेस कमज़ोर होगी।

ग. ईडीए कई उद्योगों के लिए एक ज़रूरी इनपुट है, जिनमें फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, वॉटर ट्रीटमेंट, टेक्सटाइल्स और एडहेसिव्स शामिल हैं। ईडीए पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने से मैनकोज़ेब बनाने वालों सहित आगे के मैन्युफ़ैक्चरर्स के लिए इनपुट लागत बढ़ जाएगी; ये मैन्युफ़ैक्चरर्स बढ़ी हुई लागत का बोझ किसानों पर नहीं डाल सकते, जिससे उनकी कॉम्पिटिटिवनेस पर असर पड़ेगा।

घ. मात्रात्मक सबूत बताते हैं कि 20-30% का एडीडी डाउनस्ट्रीम यूज़र्स को काफ़ी नुकसान पहुँचाएगा, जिससे मुनाफ़े, उत्पादन और एक्सपोर्ट मार्केट शेयर में कमी आएगी।

ङ. एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने से व्यापार का रुख बदल जाएगा। जिन देशों पर ये ड्यूटी लगाई गई है, उनसे होने वाले आयात की जगह जापान, यूएसए और कोरिया आरपी जैसे देशों से आयात होगा, जो पहले से ही प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सामान सप्लाई कर रहे हैं।

च. इससे घरेलू उद्योग को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उसे वैसे ही प्रतिस्पर्धी दबावों का सामना करना पड़ेगा, जिससे यह ड्यूटी बेअसर हो जाएगी।

छ. विरोधी पक्षों का मानना है कि यह जांच कानूनी रूप से दोषपूर्ण और भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसमें जापान, यूएसए और कोरिया आरपी को संबंधित देशों के तौर पर शामिल नहीं किया गया है। हालांकि अलग-अलग तौर पर इनका आयात हिस्सा 3% की सीमा से कम है, लेकिन सामूहिक रूप से ये देश कुल आयात का 7.28% हिस्सा रखते हैं, जो एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 14(डी) के तहत शामिल किए जाने के लिए तय 7% की सीमा से अधिक है।

ज. इन 'नॉन-सब्जेक्ट' देशों से आयात की कीमतें 'सब्जेक्ट' देशों के बराबर हैं और घरेलू उद्योग के एनआईपी से काफी कम हैं, जिससे पता चलता है कि ये भी डंप किए गए और नुकसान पहुंचाने वाले आयात का स्रोत हैं। इन्हें बाहर रखना विश्व व्यापार संगठन के एंटी-डंपिंग समझौते के भेदभाव न करने के सिद्धांत का उल्लंघन है।

ञ.2 <u>आवेदक द्वारा प्रस्तुति</u>

116. आवेदक ने भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित बातें कही हैं:

क. इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल एग्रोकेमिकल और फार्मास्युटिकल कामों में किया जाता है, जैसे कि मैनकोज़ेब और सिटाग्लिप्टिन। मैनकोज़ेब के प्रोडक्शन में ईडीए का इस्तेमाल बहुत कम होता है, और मैनकोज़ेब के कुल प्रोडक्शन का 80% से ज़्यादा हिस्सा एक्सपोर्ट किया जाता है, जिस पर कोई ड्यूटी नहीं लगती है।

ख. सिटाग्लिप्टिन का इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ों के इलाज के लिए किया जाता है। डॉक्टर सिटाग्लिप्टिन की लगभग 25-50 एमजी की डोज़ लिखते हैं। चूँकि सिटाग्लिप्टिन पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी सिर्फ़ 0.002% है, इसलिए अंतिम उपभोक्ता पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी का कोई असर नहीं पड़ेगा।

ग. प्रस्तावित उपायों का डाउनस्ट्रीम उद्योगों पर असर न के बराबर है।

घ. पहले कीमतें ज़्यादा थीं। प्रस्तावित एंटी-डंपिंग ड्यूटी को जोड़ने के बाद भी, आयात की कीमत इन पुराने स्तरों से कम ही रहेगी। इसलिए, एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने से यूज़र्स पर कोई खास असर पड़ने की संभावना नहीं है।

ङ. 2022-23 में आयात की कीमत बढ़ने के बावजूद, घरेलू उद्योग ने जनहित को ध्यान में रखते हुए कीमतें बढ़ाने से परहेज किया।

च. 2022-23 में अमोनिया और विदेश मंत्रालय की लागत बढ़ने के कारण आयात की कीमतें तेज़ी से बढ़ीं, जिससे कीमतों में 13% की नेगेटिव अंडरकटिंग (कीमतों में अंतर) हुई; फिर भी, जनहित को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग ने उसी अनुपात में अपनी कीमतें नहीं बढ़ाईं।

छ. इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल मुख्य रूप से एग्रोकेमिकल और फार्मास्युटिकल सेक्टर में होता है, जो 'पास-थ्रू' इंडस्ट्री की तरह काम करते हैं। एंटी-डंपिंग ड्यूटी की वजह से लागत में होने वाली किसी भी बढ़ोतरी का बोझ आखिर में ग्राहकों पर डाले जाने की संभावना है, और इससे मांग पर बहुत कम असर पड़ेगा।

ज. संबंधित देशों के एक्सपोर्टर्स की भारतीय बाज़ार के प्रति कोई लंबी अवधि की प्रतिबद्धता नहीं होगी और वे सप्लाई को ज़्यादा मुनाफ़े वाले बाज़ारों की ओर मोड़ सकते हैं। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग स्थिर सप्लाई और उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखता है, साथ ही इससे इन्वेंट्री और वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतें भी कम रहती हैं।

झ. एकमात्र भारतीय उत्पादक होने के नाते, घरेलू उद्योग को स्थिरता से जुड़ी गंभीर चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसने पहले ही काफी समय से उत्पादन कम कर दिया है। एंटी-डंपिंग ड्यूटी न होने पर प्लांट बंद होने का वास्तविक खतरा है, जिससे रोजगार और आजीविका पर बुरा असर पड़ेगा।

ञ. घरेलू इंडस्ट्री का मौजूदा प्रदर्शन देश में नए निवेश को सही नहीं ठहराता है और दूसरे भारतीय उत्पादकों के लिए इस बिज़नेस में आना आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं है।

ट. घरेलू उद्योग ने 2023-24 में जनहित से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां चलाकर समाज को लाभ पहुंचाने के लिए सीएसआर के तहत 2.88 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

ञ.3 <u>प्राधिकरण द्वारा जांच</u>

117. प्राधिकरण ने यह परीक्षण किया कि क्या प्रस्तावित एंटी-डंपिंग शुल्क का आरोपण सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा। यह निर्धारण अभिलेख पर उपलब्ध सूचनाओं तथा विभिन्न पक्षों, जिनमें घरेलू उद्योग, विदेशी उत्पादक एवं उपभोक्ता शामिल हैं, के हितों पर विचार के आधार पर किया गया है।

118. प्राधिकरण ने एक गैज़ेट नोटिफ़िकेशन जारी करके इम्पोर्टर्स, कंज्यूमर्स और अन्य इच्छुक पार्टियों से उनकी राय मांगी। अथॉरिटी ने यूज़र्स के लिए एक प्रश्नावली भी तय की ताकि वे मौजूदा जांच से जुड़ी ज़रूरी जानकारी दे सकें, जिसमें एंटी-डंपिंग ड्यूटी का उनके कामकाज पर संभावित असर भी शामिल है। अथॉरिटी ने कई बातों पर जानकारी मांगी, जैसे कि अलग-अलग देशों के सप्लायर्स से मिलने वाले प्रोडक्ट की अदला-बदली की क्षमता, सोर्स बदलने की क्षमता, कंज्यूमर्स पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी का असर, और वे कारक जो एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगने से बनी नई स्थिति के अनुसार ढलने की प्रक्रिया को तेज़ या धीमा कर सकते हैं।

119. प्राधिकरण का मानना है कि एंटी-डंपिंग ड्यूटी का मकसद आम तौर पर डंपिंग जैसे अनुचित व्यापार तरीकों से घरेलू उद्योग को होने वाले नुकसान को खत्म करना है, ताकि भारतीय बाज़ार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से कायम की जा सके।

120. प्राधिकरण ने आर्थिक हित से जुड़ा एक सवालनामा तैयार किया था, जिसे इस जांच में शामिल सभी इच्छुक पक्षों को भेजा गया था। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, इंडोरामा इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, कार्डोलाइट स्पेशलिटी केमिकल्स इंडिया एलएलपी और घरेलू उद्योग ने आर्थिक हित से जुड़ा सवालनामा जमा किया है। यूज़र्स का दावा है कि एंटी-डंपिंग ड्यूटी का उनके कामकाज पर बुरा असर पड़ेगा। यूज़र्स ने एंटी-डंपिंग ड्यूटी के असर का हिसाब नीचे दिए अनुसार लगाया है।

उपयोगकर्ता	**कार्डोलाइट**	**कोरोमंडल**	**इंडोरामा**

गैर गोपनीय

उत्पाद	**एपॉक्सी क्योरिंग एजेंट**	**मैन्कोजेब**	**इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न**
एफजी में पीयूसी की लागत	रुपये/किग्रा	***	***
एफजी की कुल लागत	रुपये/किग्रा	***	***
एफजी का विक्रय मूल्य	रुपये/किग्रा	***	***
लाभप्रदता	रुपये/किग्रा	***	***
एफजी की कीमत में पीयूसी का हिस्सा	%	***	***
पीयूसी में काल्पनिक मूल्य वृद्धि	%	***	***
पीयूसी की लागत में वृद्धि	रुपये/किग्रा	***	***
एफजी की कीमत पर वृद्धि का प्रभाव	%	5.96%	2.91%

121. घरेलू उद्योग ने एंटी-डंपिंग ड्यूटी के असर का आकलन नीचे दिए गए तरीके से किया है।

क्र.सं.	**विवरण**	**इकाई**	**मैन्कोजेब**
1	मैन्कोजेब तकनीकी 85% न्यूनतम	रुपये/किग्रा	250
2	डाउनस्ट्रीम उत्पाद के लिए ईडीए (अनुमान)	किग्रा	0.20
3	1 किग्रा के लिए ईडीए मूल्य	रुपये/किग्रा	134
4	ईडीए पर एडीडी (काल्पनिक 20%)	रुपये/किग्रा	26.80
5	डाउनस्ट्रीम उद्योग (एपीआई उत्पादक) के लिए लागत वृद्धि	रुपये/किग्रा	5.36
6	तकनीकी उत्पादक पर एडीडी का प्रभाव	%	2.14%
7	मैन्कोजेब फॉर्मुलेशन मूल्य प्रति 1 किग्रा	रुपये	571
8	मैन्कोजेब की सांद्रता	%	75%
9	फॉर्मुलेशन उत्पादक के लिए लागत वृद्धि	रुपये	4.02
10	फॉर्मुलेशन उत्पादक पर एडीडी का प्रभाव	%	0.70%
11	1 किग्रा मैन्कोजेब द्वारा आवृत क्षेत्र	एकड़	1.25
12	प्रति एकड़ प्रभाव	रुपये	5

क्र.सं.	**विवरण**	**इकाई**	**सिटाग्लिप्टिन**
1	1 किग्रा उत्पाद की औसत कीमत	रुपये/किग्रा	7,500
2	डाउनस्ट्रीम उत्पाद के लिए ईडीए (अनुमान)	किग्रा	0.15

3	1 किग्रा के लिए ईडीए मूल्य	रुपये/किग्रा	134
4	ईडीए पर एंटी-डंपिंग शुल्क (काल्पनिक 20%)	रुपये/किग्रा	26.80
5	डाउनस्ट्रीम उद्योग (एपीआई उत्पादक) के लिए लागत वृद्धि	रुपये/किग्रा	4.02
6	टैबलेट निर्माता पर एंटी-डंपिंग शुल्क का प्रभाव	%	0.05%
7	1 स्ट्रिप की कीमत	रुपये	85
8	1 टैबलेट की कीमत	रुपये/स्ट्रिप	8.50
9	सिटाग्लिप्टिन की प्रति टैबलेट खुराक	मि.ग्रा.	50
10	1 मि.ग्रा. की कीमत	रुपये/मि.ग्रा.	0.17
11	1 किग्रा की कीमत	रुपये/किग्रा	1,70,000
12	टैबलेट निर्माता के लिए लागत वृद्धि (मानते हुए कि पूरी लागत पास की जाती है)	रुपये/किग्रा	4.02
13	टैबलेट निर्माता पर एंटी-डंपिंग शुल्क का प्रभाव	%	0.002%
14	प्रति स्ट्रिप प्रभाव	रुपये	0.002

122. घरेलू उद्योग और यूज़र इंडस्ट्री द्वारा जमा किए गए डेटा की जांच करने पर यह पाया गया है कि ईडीए, डाउनस्ट्रीम उत्पादों की लागत का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, और इसलिए अंतिम उत्पादों की कीमत पर इसका असर भी सीमित है।

123. नीचे दी गई तालिका आयात की लैंडेड कीमत दिखाती है।

क्र.सं.	**विवरण**	**इकाई**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**जांच अवधि (पीओ आई)**
1	अवतरित मूल्य	रुपये/मीट्रिक टन	2,40,358	3,78,746	1,83,266	1,41,684

124. देखा गया है कि पहले लैंडेड कीमत ज़्यादा थी और जांच की अवधि में इसमें कमी आई है। घरेलू इंडस्ट्री ने कहा है कि प्रस्तावित एंटी-डंपिंग ड्यूटी सहित इंपोर्ट की लैंडेड कीमत पहले की कीमतों से कम होगी। इसलिए, जब इन ज़्यादा कीमतों का यूज़र पर कोई असर नहीं पड़ा, तो एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने से भी कोई खास असर पड़ने की संभावना नहीं है। अथॉरिटी का मानना है कि भले ही एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने से भारत में प्रोडक्ट की कीमत के स्तर पर असर पड़ सकता है, लेकिन ऐसे एंटी-डंपिंग उपायों से भारतीय बाज़ार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, एंटी-डंपिंग उपाय डंपिंग प्रैक्टिस से मिलने वाले अनुचित फ़ायदे को कम कर सकते हैं, जिससे घरेलू इंडस्ट्री को होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा और संबंधित सामान के उपभोक्ताओं के लिए ज़्यादा विकल्प उपलब्ध रहेंगे।

इसके अलावा, जांच में यह बात सामने नहीं आई है कि डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री लागत में बढ़ोतरी के हिसाब से अपनी कीमतें तय करने में असमर्थ रही है।

125. मांग और आपूर्ति के अंतर के कारण ज़रूरी इंपोर्ट के मामले में, रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी से पता चलता है कि घरेलू इंडस्ट्री अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रही है (काफी क्षमता खाली पड़ी है) और उसने क्षमता बढ़ाने के लिए ज़रूरी मंज़ूरी ले ली है। हालांकि मांग और आपूर्ति में अभी भी अंतर है, लेकिन अथॉरिटी का मानना है कि भारी नुकसान उठाने के बावजूद किसी प्रोड्यूसर से बड़े निवेश की उम्मीद नहीं की जा सकती। अथॉरिटी यह भी मानती है कि एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने से भारत में संबंधित सामान की कमी नहीं होगी। यह ध्यान दिया गया है कि एंटी-डंपिंग ड्यूटी देश में इंपोर्ट पर रोक नहीं लगाती, बल्कि यह पक्का करती है कि इंपोर्ट उचित कीमतों पर उपलब्ध हों। इसलिए, ड्यूटी लगाने से प्रोडक्ट की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अथॉरिटी का मानना है कि घरेलू बाज़ार में निवेश उचित बाज़ार सिद्धांतों के आधार पर किया गया था। जब बड़े पैमाने पर डंपिंग हो रही हो, तो घरेलू इंडस्ट्री का विस्तार नहीं हो सकता; साथ ही, यूज़र इंडस्ट्री ने डंप किए गए इंपोर्ट मिलने की उम्मीद में अपना कामकाज शुरू नहीं किया था।

ट. <u>प्रकटीकरण-पश्चात् टिप्पणियाँ</u>

ट.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुतियाँ</u>

126. अन्य हितबद्ध पक्षों ने प्रकटीकरण विवरण पर निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:

i. यह प्रस्तुत किया गया है कि प्राधिकरण ने संबंधित रेखा मंत्रालयों से जानकारी मांगकर घरेलू उद्योग की पात्रता (स्थिति) का स्वतंत्र रूप से सत्यापन नहीं किया है, जो कि पिछली जांचों में अपनाई जाने वाली सुसंगत प्रथा है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि घरेलू उद्योग की पात्रता के संबंध में जानकारी सही हो और प्राधिकरण द्वारा विकृत आंकड़ों पर विचार किए जाने के किसी भी भौतिक जोखिम को रोका जा सके। विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय निकाय के निर्णय ईसी-फास्टनर्स (चीन) का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सक्षम प्राधिकरण पर यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि जिस तरह से वह घरेलू उद्योग को परिभाषित करता है, वह आर्थिक आंकड़ों को विकृत करने और परिणामस्वरूप, उद्योग की स्थिति के अपने विश्लेषण को विकृत करने का कोई भौतिक जोखिम पेश न करे।

ii. यह प्रस्तुत किया गया है कि 'प्रमुख अनुपात' (प्रमुख अनुपात) परीक्षण पूरी तरह से गणितीय परीक्षण नहीं है और इसके मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों अर्थ हैं। एक परीक्षण जो पूरी तरह से मात्रात्मक होगा, यह आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित नहीं

करेगा कि उस आधार पर परिभाषित घरेलू उद्योग कुल घरेलू उत्पादन को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित करता है। आवेदन 'प्रमुख अनुपात' परीक्षण के गुणात्मक पहलू को संतुष्ट करने में विफल रहता है क्योंकि बाजार में मौजूद स्थापित उत्पादक को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा गया है। विश्व व्यापार संगठन पैनल ने चीन - संयुक्त राज्य अमेरिका से ब्रॉयलर उत्पादों पर एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग ड्यूटी उपायों के मामले में कहा था कि एक जांच प्राधिकरण को अपने नुकसान के निर्धारण में अन्य घरेलू उत्पादकों की स्थिति को नजरअंदाज करने की अनुमति नहीं है।

iii. यह प्रस्तुत किया गया है कि जापान, यूएसए और कोरिया आरपी से होने वाले आयात, जबकि व्यक्तिगत रूप से 3% की सीमा से कम हैं, सामूहिक रूप से आवेदन में दिए गए आंकड़ों के अनुसार कुल आयात के 7.28% से अधिक हैं। विश्व व्यापार संगठन एंटी-डंपिंग समझौते के अनुच्छेद 5.8 और प्रतिप्रतिषेध नियमों के नियम 14(डी) के तहत, ऐसे आयातों का सामूहिक रूप से आकलन किया जाना चाहिए था और इस जांच के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए था। इन देशों को जांच के दायरे से बाहर रखना अनिवार्य कानूनी सीमाओं की अवहेलना करता है, नुकसान के विश्लेषण को भौतिक रूप से अधूरा और त्रुटिपूर्ण बनाता है, तथा सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र उपचार खंड में निहित गैर-भेदभाव के सिद्धांत के विपरीत है।

iv. जापान और यूएसए जैसे गैर-विषय देशों से आयात प्रतिस्पर्धी कीमतों पर किया जाता है, जो अक्सर निर्मित गैर-हानिकारक मूल्य से भी कम होता है। इन आयातों को छोड़कर, नुकसान का विश्लेषण पूरे नुकसान का भार अनुचित रूप से विषय देशों पर डालता है, जिससे एक बढ़ा हुआ क्षति मार्जिन और एक त्रुटिपूर्ण कारणात्मक संबंध बनता है। केवल विषय देशों पर प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाने से अनिवार्य रूप से व्यापार का रुख उन बाहर किए गए देशों की ओर मुड़ जाएगा, जिससे शुल्क के सुरक्षात्मक उद्देश्य को नकार दिया जाएगा।

v. यह प्रस्तुत किया गया है कि घरेलू उद्योग को कथित रूप से कोई भी नुकसान विषय आयातों के अलावा अन्य कारकों के कारण है। घरेलू उद्योग महत्वपूर्ण संरचनात्मक नुकसानों के साथ काम करता है, जिसमें अपने मुख्य कच्चे माल के रूप में आयातित मोनोएथेनॉलमाइन (एमईए) पर निर्भरता, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का अभाव, महाराष्ट्र के सोलापुर में अपने स्थान के कारण उच्च लॉजिस्टिक्स लागत, और अपेक्षाकृत छोटी उत्पादन क्षमता के कारण पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का अभाव शामिल है। इसके अलावा, जून 2019 में ही व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने के कारण, घरेलू उद्योग को नुकसान की अवधि के दौरान अभी भी प्रारंभिक परिचालन अक्षमताओं, प्रक्रिया स्थिरीकरण के मुद्दों और उच्च उत्पादन लागतों का सामना करना पड़ रहा था। इन कारकों ने, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से, घरेलू उद्योग के

प्रदर्शन को भौतिक रूप से प्रभावित किया है और इसे विषय देशों से आयात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

vi. यह प्रस्तुत किया गया है कि चीन पीआर से आयात में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान सात गुना से अधिक की तीव्र वृद्धि हुई है, और चीन पीआर भारत को विचाराधीन उत्पाद का सबसे बड़ा एकल निर्यातक बनकर उभरा है। चीन पीआर से आयात में उछाल के बिना, विषय देशों से कुल आयात में वास्तव में कमी आई होती। इसके विपरीत, नुकसान की अवधि के दौरान सऊदी अरब से आयात की मात्रा में कमी आई है। तदनुसार, नुकसान के विश्लेषण को विषय देशों के व्यक्तिगत योगदानों के बीच सावधानीपूर्वक अंतर करना चाहिए, और सऊदी अरब से आयात को चीन पीआर के साथ एकत्रित करने से नुकसान का गलत आरोपण होगा।

vii. यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रकटीकरण विवरण में गैर-विषय देशों से ईडीए के आयात आंकड़ों को विषय देशों के आयात आंकड़ों में संशोधन की तुलना में काफी अधिक सीमा तक नीचे की ओर संशोधित किया गया है। इस असममित नीचे की ओर संशोधन के परिणामस्वरूप, गैर-विषय देशों से आयात का कुल आयात में हिस्सा जांच की अवधि में 7% से अधिक से घटकर 7% से कम हो गया है। इस विषम संशोधन के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्राधिकरण से अनुरोध है कि वह गैर-विषय देशों से आयात आंकड़ों की फिर से जांच करे क्योंकि यह मुद्दा सीधे इस निर्धारण को प्रभावित करता है कि क्या उन देशों को जांच के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए था।

viii. यह प्रस्तुत किया गया है कि एचएस कोड 29212100 के तहत ईडीए के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क को सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 12/2026 दिनांक 1 अप्रैल 2026 के माध्यम से वापस ले लिया गया है, जाहिर तौर पर मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति और उसके परिणामी मूल्य दबावों को देखते हुए। ऐसी स्थिति में, ईडीए पर प्रतिप्रतिषेध शुल्क की सिफारिश करना सीधे तौर पर इन सरकारी उपायों के अंतर्निहित नीति उद्देश्य का प्रतिकार करेगा। प्राधिकरण को ऐसे उपाय की सिफारिश नहीं करनी चाहिए जो सरकार के स्वयं के सार्वजनिक हित में किए गए टैरिफ उदारीकरण कदमों के प्रभाव को निष्क्रिय कर दे।

ix. यह प्रस्तुत किया गया है कि भारत में ईडीए के लिए एक महत्वपूर्ण और बढ़ता हुआ मांग-आपूर्ति अंतर मौजूद है। घरेलू उद्योग की क्षमता स्पष्ट रूप से भारत की कुल मांग का आधा हिस्सा भी पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। जापान, यूएसए, कोरिया आरपी, सिंगापुर और यूएई जैसे गैर-विषय देशों से आयात पहले से ही भारतीय बाजार में विषय देशों के बराबर या उससे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर प्रवेश कर रहा है। विषय देशों से आयात पर कोई भी प्रतिबंध केवल आयात के स्रोत में बदलाव को ट्रिगर करेगा, जिससे घरेलू उद्योग को कोई स्पष्ट लाभ नहीं होगा।

x. घरेलू उद्योग के लिए सही और स्थायी उपाय व्यापार संरक्षण में नहीं है, बल्कि मौलिक संरचनात्मक सुधार करने में है, जिसमें ऊर्ध्वाधर एकीकरण, क्षमता विस्तार और अपनी लागत संरचना को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्तर पर लाने के लिए पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं प्राप्त करना शामिल है।

xi. यह प्रस्तुत किया गया है कि ईडीए कई आवश्यक कृषि रासायनिक उत्पादों जिनमें मैन्कोजेब शामिल है, के लिए एक महत्वपूर्ण मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। ईडीए आयातों पर प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाने से अनिवार्य रूप से कच्चे माल की लागत में वृद्धि होगी, जो मूल्य श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ेगी, जिससे डाउनस्ट्रीम कृषि रासायनिक सूत्रीकरणों की कीमतें बढ़ जाएंगी। इस तरह की बढ़ी हुई लागत महत्वपूर्ण फसल सुरक्षा रसायनों की कीमतों को बढ़ाकर किसानों पर सीधा बोझ डालेगी, संभावित रूप से कृषि पैदावार और किसानों की आय को कम करेगी, तथा देश के व्यापक आर्थिक और सार्वजनिक हित के उद्देश्यों के विपरीत होगी।

xii. यह भी अनुरोध किया गया है कि आयात डेटा उसी प्रारूप और तरीके में प्रदान किया जाए, जिसमें इसे जांच के उद्देश्य के लिए रिकॉर्ड पर लिया गया था, जो माननीय सीईएसटीएटी के निर्णय एक्सोटिक डेकोर प्रा. लि. बनाम नामित प्राधिकरण (प्रतिप्रतिषेध अपील संख्या 52233/2018) दिनांक 12 जून 2020 के अनुरूप है।

xiii. यदि प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाना उचित है, तो यह प्रस्तुत किया गया है कि ऐसा शुल्क केवल दो (2) वर्षों की सीमित अवधि के लिए अनुशंसित किया जाना चाहिए, ताकि एक अनुचित उपाय अनावश्यक रूप से लंबी अवधि के लिए लागू न रहे।

xiv. यह प्रस्तुत किया गया है कि प्राधिकरण ने 'ऑफ-ग्रेड गुणवत्ता' और 'पर्याप्त मात्रा में नहीं' के आधार पर एक उत्पादक के एकमात्र घरेलू बिक्री लेनदेन को अनुचित रूप से खारिज कर दिया, बिना एंटी-डंपिंग समझौते के अनुच्छेद 2.2 और नियमों के नियम 10 के तहत आवश्यक विश्लेषण किए। किसी उत्पाद को 'ऑफ-ग्रेड' के रूप में वर्गीकृत करना, बिना आगे की जांच के, उसे व्यापार के सामान्य क्रम के बाहर नहीं रखता है।

xv. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सऊदी अरब से आयात जांच की अवधि के दौरान 20% से अधिक घट गया, और जब सऊदी आयात की मात्रा अधिक थी, तब घरेलू उद्योग लाभदायक था, जो किसी भी कारणात्मक संबंध को नकारता है। डीजीटीआर ने निम्नलिखित के संबंध में एंटी-डंपिंग समझौते के अनुच्छेद 3.5 के तहत उचित गैर-आरोपण विश्लेषण करने में विफलता दिखाई है: (क) घरेलू उद्योग के निर्यात प्रदर्शन में 92% की गिरावट; (ख) एमईए की कीमतों में उतार-चढ़ाव; तथा (ग) 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट में स्वीकार किए गए भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और जलवायु परिवर्तन। तदनुसार, जांच को जहां तक यह सऊदी अरब से संबंधित है, समाप्त किया जाना चाहिए।

xvi. कुछ डाउनस्ट्रीम आयातकों/उपयोगकर्ताओं द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि सामूहिक मूल्यांकन अनुपयुक्त है क्योंकि विभिन्न विषय देशों से आयात विभिन्न शर्तों के तहत, विभिन्न मूल्य स्तरों पर, विभिन्न व्यापार चैनलों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा करते हैं।

xvii. लगभग 10-11% का भारित औसत मूल्य अंडरकटिंग नाममात्र है और यह महत्वपूर्ण मूल्य क्षति का प्रमाण नहीं है। मूल्य में गिरावट कोविड-19 के बाद वैश्विक ईडीए कीमतों में व्यापक सुधार के साथ मेल खाती है।

xviii. xviii. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने रोजगार (44% की वृद्धि), प्रति दिन उत्पादकता (11% की वृद्धि), और कुल मजदूरी (141% की वृद्धि) में सकारात्मक रुझान दिखाया, जो भौतिक क्षति के निष्कर्ष के अनुरूप नहीं हैं।

xix. मैन्कोजेब पर प्रतिप्रतिषेध शुल्क का प्रभाव विश्लेषण गलत उपभोग मान्यताओं पर आधारित है। सत्यापित उत्पादन अभिलेख विभिन्न वास्तविक उपभोग अनुपात दिखाते हैं। 20-30% का प्रतिप्रतिषेध शुल्क कम मार्जिन वाले उद्योगों में लाभप्रदता को नष्ट कर देगा।

xx. प्रतिप्रतिषेध शुल्क के आरोपण से आपूर्ति की कमी पैदा होगी और एकमात्र घरेलू उत्पादक को अनुचित मूल्य निर्धारण शक्ति प्रदान होगी, जिससे एक एकाधिकारी परिणाम का जोखिम होगा, मुद्रास्फीति संबंधी प्रभाव होंगे तथा भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर होगी।

ट.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ</u>

127. घरेलू उद्योग ने प्रकटीकरण विवरण पर निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:

i. कि प्राधिकरण ने प्रकटीकरण विवरण में स्पैन्डेक्स यार्न के उत्पादन में प्रयुक्त एथिलीन डायमीन को बाहर नहीं करने का प्रस्ताव सही रूप से दिया है। अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा भरोसा किए गए विनिर्देश 2020-21 में उन्हें दिए गए नमूने पर आधारित थे। 2020-21 के बाद, घरेलू उद्योग ने तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पाद को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण अनुसंधान और विकास प्रयास किए हैं, और उत्पाद अब स्पैन्डेक्स के अन्य उत्पादकों को आपूर्ति किया जा रहा है। घरेलू उद्योग का उत्पाद दिखावट, रंग, जल सामग्री, शुद्धता और कार्बनिक अशुद्धता सहित सभी निर्दिष्ट मानकों को पूरा करता है, और बिना किसी नई मशीनरी के ग्राहक की आवश्यकताओं के आधार पर विनिर्देशों को संशोधित किया जा सकता है। उन्होंने प्राधिकरण से प्रकटीकरण विवरण में प्रस्तावित अनुसार विचाराधीन उत्पाद के दायरे की पुष्टि करने का भी अनुरोध किया है।

ii. कि प्राधिकरण को अंतिम निष्कर्षों में पुष्टि करनी चाहिए कि विषय देशों से डंपित आयातों ने घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति पहुंचाई है।

iii. कि ग्राहकों ने अपनी खरीदारी को तेजी से विषय देशों से उत्पन्न आयातित वस्तुओं की ओर स्थानांतरित कर दिया है, क्योंकि उनकी कीमतें कम हैं। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य आगे यह प्रदर्शित करते हैं कि वाणिज्यिक बातचीत के दौरान ग्राहकों द्वारा आयात कीमतों को नियमित रूप से बेंचमार्क के रूप में उपयोग किया जाता है, जो बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए घरेलू उद्योग की कीमतों पर महत्वपूर्ण नीचे की ओर दबाव डालता है।

iv. कि प्राधिकरण ने सही रूप से नोट किया है कि जापान, कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात सामूहिक रूप से कुल आयात का 6% से भी कम है और इसलिए, इसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान देने वाला कारक नहीं माना जा सकता है। प्राधिकरण ने आगे पाया है कि किसी अन्य ज्ञात कारक ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है। इन परिस्थितियों में, घरेलू उद्योग ने दोहराया कि हुई क्षति पूरी तरह से विषय देशों से डंपित आयातों के कारण है, और कम कीमत वाले डंपित आयातों में उछाल और घरेलू उद्योग के मात्रा, मूल्य और वित्तीय प्रदर्शन मानकों में गिरावट के बीच एक स्पष्ट और प्रत्यक्ष कारणात्मक संबंध मौजूद है।

v. कि उपयोगकर्ता पिछले वर्षों में काफी अधिक कीमतों पर आयातित उत्पाद खरीद रहे थे। चूंकि जांच की अवधि में कीमतों में तेजी से गिरावट आई है, इसलिए समान प्रतिस्पर्धी स्तर बहाल करने वाले प्रतिप्रतिषेध शुल्क के आरोपण का डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं पर कोई भौतिक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि ईडीए डाउनस्ट्रीम उत्पादों की लागत का केवल एक छोटा सा हिस्सा बनाता है - एपॉक्सी क्योरिंग एजेंटों के लिए लगभग 30%, मैन्कोजेब के लिए 15%, और इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न के लिए 1% से भी कम - जिसका अंतिम उत्पादों की कीमत पर तदनुरूप सीमित प्रभाव पड़ता है। 20% की काल्पनिक शुल्क का अंतिम उत्पाद की कीमत पर प्रभाव 0.18% से 5.96% तक है, जो नगण्य है।

vi. प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाने से विषय देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होगा, बल्कि यह सुनिश्चित होगा कि आयात उचित कीमतों पर उपलब्ध हों। इससे भारत में विषय वस्तुओं की कमी नहीं होगी। घरेलू उद्योग से महत्वपूर्ण डंपिंग के सामने अपनी क्षमता बढ़ाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, और उपयोगकर्ता उद्योग ने डंपित आयातों तक निरंतर पहुंच की उम्मीद में अपने परिचालन स्थापित नहीं किए थे।

vii. घरेलू उद्योग भारत में ईडीए का एकमात्र उत्पादक है और उत्पाद की डंपिंग ने अन्य संभावित उत्पादकों को क्षमताएं स्थापित करने से हतोत्साहित किया है। यदि प्रतिप्रतिषेध शुल्क नहीं लगाया जाता है, तो संयंत्र बंद होने का वास्तविक जोखिम है, जो रोजगार, आजीविका और सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के उद्देश्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।

viii. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षमता बढ़ाकर 37,350 मीट्रिक टन करने की मंजूरी प्राप्त कर ली है। पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग को अपने नुकसान से उबरने, क्षमता विस्तार करने और आगे और निवेश करने के लिए आवश्यक स्थिरता और वित्तीय सहायता मिलेगी।

ix. घरेलू उद्योग प्राधिकरण से अनुरोध करता है कि वह पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाने की सिफारिश करे। जब तक शुल्क पांच वर्षों के लिए नहीं लगाया जाता, तब तक घरेलू उद्योग डंपित आयातों के परिणामस्वरूप हुई महत्वपूर्ण क्षति से पर्याप्त रूप से उबर नहीं पाएगा। घरेलू उद्योग के निदेशक मंडल ने डंपित आयातों के कारण हुए नुकसान के कारण प्रस्तावित क्षमता विस्तार निवेश को मंजूरी देने में अनिच्छा दिखाई है, और पांच वर्षों के लिए प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाने से ऐसे निवेश के लिए आवश्यक स्थिरता मिलेगी।

ट.3 <u>प्राधिकरण द्वारा परीक्षण</u>

128. प्राधिकरण ने हितबद्ध पक्षों द्वारा की गई प्रकटीकरण-पश्चात् प्रस्तुतियों का परीक्षण किया है। यह देखा गया है कि इनमें से अधिकांश प्रस्तुतियाँ पहले से ही परीक्षण किए गए तर्कों और दावों की पुनरावृत्ति हैं और इसलिए इन्हें इन अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक पैराग्राफों में आवश्यक समझे जाने तक संबोधित किया गया है। संक्षिप्तता के लिए, प्राधिकरण ने इस प्रकटीकरण-पश्चात् परीक्षण में ऐसे मुद्दों पर प्रतिक्रियाओं को दोहराने से परहेज किया है। हालाँकि, प्रकटीकरण-पश्चात् प्रस्तुतियों में पहली बार उठाए गए किसी भी नए मुद्दे, साथ ही पहले संबोधित किए गए लेकिन आगे परीक्षण करना आवश्यक समझे गए मुद्दों को यहाँ संबोधित किया गया है।

129. प्राधिकरण प्रकटीकरण विवरण में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद के दायरे और घरेलू उद्योग के रूप में आवेदक की पात्रता की पुष्टि करता है।

130. प्राधिकरण ने सामान्य मूल्य, शुद्ध निर्यात मूल्य, लैंडेड मूल्य और गैर-हानिकारक मूल्य के प्रस्तावित निर्धारणों के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षों को प्रकटीकरण की गोपनीय प्रति जारी की। प्रकटीकरण विवरण जारी करने के बाद किसी भी हितबद्ध पक्ष से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है; इसलिए, प्राधिकरण विषय देशों के विभिन्न उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्धारित डंपिंग मार्जिन की पुष्टि करता है।

131. जापान, यूएसए और कोरिया आरपी से आयात के संबंध में प्रस्तुति पर, प्राधिकरण ने डीजी सिस्टम से सत्यापित लेन-देन-वार आयात आंकड़ों की जांच की है और नोट किया है कि

जांच की अवधि के दौरान इन देशों से आयात सामूहिक रूप से कुल आयात का 6% से भी कम है। कम मात्रा वाले स्रोत देशों को शामिल करने के लिए नियमों के नियम 14(डी) के तहत निर्धारित 7% की सीमा पूरी नहीं हुई है। वर्तमान जांच के दायरे में इन देशों को शामिल करने का कोई कानूनी आधार नहीं है।

132. इस दावे पर कि प्रकटीकरण विवरण में गैर-विषय देशों के आयात आंकड़ों में नीचे की ओर संशोधन असममित था, प्राधिकरण स्पष्ट करता है कि संशोधन सभी स्रोत देशों के आंकड़ों पर समान रूप से लागू होता है और यह सत्यापन अभ्यास का परिणाम है जो दोहराव, गलत-कोडित लेनदेन और गैर-ईडीए प्रविष्टियों को हटा देता है। यह आरोप किसी भी विशिष्ट लेन-देन-स्तरीय साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

133. कारणात्मक संबंध पर प्रस्तुतियों के संबंध में, प्राधिकरण ने देखा है कि जिन स्थितियों को अब डंपित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को तोड़ने वाला बताया गया है, जैसे आयातित कच्चे माल पर निर्भरता, कैप्टिव उत्पादन या बैकवर्ड इंटीग्रेशन का अभाव, स्थान संबंधी नुकसान, और अन्य संरचनात्मक विशेषताएं, पूरी क्षति अवधि के दौरान मौजूद थीं और उन वर्षों के बीच अपरिवर्तित रहीं जब घरेलू उद्योग लाभ कमा रहा था और जांच की अवधि जब उसे नुकसान हुआ। इन्हीं स्थितियों के बावजूद घरेलू उद्योग 2021-22 और 2022-23 में लाभदायक था। तदनुसार, ऐसे कारकों को घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में गिरावट का कारण नहीं माना जा सकता है। जांच की अवधि के दौरान एकमात्र भौतिक परिवर्तन हानिकारक कीमतों पर डंपित आयातों में पर्याप्त वृद्धि थी, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण मूल्य दमन और अवसाद हुआ। इसलिए, घरेलू उद्योग को हुई क्षति स्पष्ट रूप से विषय देशों से डंपित आयातों के कारण है, न कि हितबद्ध पक्षों द्वारा उद्धृत संरचनात्मक विशेषताओं के कारण।

134. प्राधिकरण ने विषय देशों से आयातों का सामूहिक मूल्यांकन किया है, क्योंकि नियमों के अनुलग्नक II के तहत निर्धारित सभी शर्तें पूरी होती हैं। प्रत्येक विषय देश से डंपिंग मार्जिन और आयात मात्रा निर्धारित सीमाओं से अधिक हैं, और प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ सामूहिक मूल्यांकन को उचित ठहराती हैं। किसी विशेष विषय देश से आयात में मात्र गिरावट उसे सामूहिक क्षति विश्लेषण में शामिल करने में बाधा नहीं डालती है।

135. प्राधिकरण देखता है कि अधिसूचना संख्या 12/2026-सीमा शुल्क के तहत बुनियादी सीमा शुल्क की वापसी और प्रतिप्रतिषेध शुल्क का आरोपण विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत काम करते हैं। इसलिए, बुनियादी सीमा शुल्क की

वापसी प्राधिकरण को प्रतिप्रतिषेध शुल्क की सिफारिश करने से नहीं रोकती है, जहाँ डंपित आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं।

136. व्यापारिक मोड़ (ट्रेड डायवर्जन) के संबंध में प्रस्तुति के संबंध में, प्राधिकरण देखता है कि प्रतिप्रतिषेध शुल्क आयात को प्रतिबंधित या निषेधित नहीं करता है, यह केवल भारतीय बाजार में समान प्रतिस्पर्धी स्तर सुनिश्चित करता है। व्यापारिक मोड़ की संभावना अनुमानित है और सिद्ध डंपिंग और क्षति को संबोधित करने से इनकार करने का आधार नहीं है।

137. डाउनस्ट्रीम उद्योग पर प्रभाव के संबंध में, प्राधिकरण ने देखा है कि ईडीए डाउनस्ट्रीम उत्पादों की लागत का केवल एक छोटा सा अनुपात बनाता है, और 20% की काल्पनिक प्रतिप्रतिषेध शुल्क पर भी, तैयार उत्पादों की कीमतों पर प्रभाव न्यूनतम होगा। प्राधिकरण ने आगे कहा कि किसी भी डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ता ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि इस तरह की वृद्धि उसके परिचालन को अव्यवहारिक बना देगी। इसके अलावा, 2022-23 के दौरान डाउनस्ट्रीम उद्योग लाभदायक बना रहा, जब ईडीए आयात की कीमतें वर्तमान स्तरों से काफी अधिक थीं। तदनुसार, प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाने का डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कोई भौतिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

138. मांग-आपूर्ति अंतर के संबंध में, यह नोट किया गया है कि प्रतिप्रतिषेध शुल्क आयात को प्रतिबंधित नहीं करता है, बल्कि केवल घरेलू उत्पादकों और आयातित उत्पादों के बीच समान प्रतिस्पर्धी स्तर सुनिश्चित करता है। चूंकि घरेलू उद्योग वर्तमान में अपनी स्थापित क्षमता के केवल 36% पर काम कर रहा है और उसके पास आगे विस्तार के लिए आवश्यक मंजूरी है, इसलिए मांग-आपूर्ति अंतर विषय देशों से निरंतर डंपित आयातों का आधार नहीं हो सकता है। क्षमता का कम उपयोग मुख्य रूप से कम कीमत वाले डंपित आयातों की उपस्थिति के कारण है, और इसलिए, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बहाल करने और घरेलू उद्योग को उत्पादन बढ़ाने और क्षमता विस्तार करने में सक्षम बनाने के लिए प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाना आवश्यक है।

139. प्राधिकरण हितबद्ध पक्षों द्वारा आयात आंकड़ों के प्रकटीकरण और माननीय सीईएसटीएटी के निर्णय एक्सोटिक डेकोर पर निर्भरता के संबंध में की गई प्रस्तुतियों को नोट करता है। हालाँकि, प्राधिकरण नोट करता है कि डीजी सिस्टम से प्राप्त आयात जानकारी को नियमों के नियम 7 में निहित गोपनीयता प्रावधानों के अनुसार माना जाता है। हालाँकि, प्राधिकरण ने वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए अपनाई गई आयात मात्रा, लैंडेड मूल्यों, रुझानों और कार्यप्रणाली सहित विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों का खुलासा किया है। हितबद्ध पक्षों को सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण करने और प्राधिकरण द्वारा भरोसा की गई जानकारी पर टिप्पणी करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। प्राधिकरण इसलिए संतुष्ट है कि

प्राकृतिक न्याय की आवश्यकताओं और नियमों के प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया गया है।

140. प्रतिप्रतिषेध शुल्क की अवधि के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9ए(5) पाँच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाने का प्रावधान करती है, जो कि प्रतिप्रतिषेध जांचों में अपनाई जाने वाली मानक अवधि है। प्राधिकरण आगे नोट करता है कि किसी भी हितबद्ध पक्ष ने मानक पाँच-वर्षीय अवधि से विचलित होने और उपाय को दो वर्षों तक सीमित करने के लिए कोई ठोस कारण या असाधारण परिस्थितियाँ प्रदान नहीं की हैं। घरेलू उद्योग द्वारा सहन की जा रही निरंतर भौतिक क्षति और छोटी अवधि के लिए किसी औचित्य की अनुपस्थिति को देखते हुए, प्राधिकरण को दो-वर्षीय शुल्क अवधि की मांग करने वाली प्रस्तुतियों में कोई दम नहीं दिखता है और वह पाँच वर्षों की अवधि के लिए प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।

141. निर्यात प्रदर्शन पर, प्राधिकरण ने इस प्रस्तुति की जांच की है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री में 92% की गिरावट स्वयं वैश्विक रूप से दबी हुई मूल्य वातावरण का परिणाम है जिसमें डंपित आयातों ने केंद्रीय भूमिका निभाई है। जब घरेलू उद्योग हानिकारक कीमत वाले आयातों के कारण घरेलू बाजार में लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में असमर्थ होता है, तो निर्यात बाजारों में उसकी प्रतिस्पर्धी स्थिति एक साथ कमजोर हो जाती है। तदनुसार, निर्यात प्रदर्शन में गिरावट क्षति का एक स्वतंत्र कारण नहीं है - यह डंपित आयातों के कारण हुई उसी क्षति का एक लक्षण है। इस कारक को क्षति के गैर-डंपिंग कारण के रूप में आरोपित नहीं किया जा सकता है।

142. इसके अलावा, 15 मीट्रिक टन का एकल घरेलू लेनदेन, सदारा के उत्पादन और भारत को उसके निर्यात के पैमाने के मुकाबले विचार करने पर, एक प्रतिनिधि घरेलू बाजार मूल्य स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीमा को पूरा नहीं करता है। अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास और अनुच्छेद 2.2 का पाठ दोनों ही मान्यता देते हैं कि घरेलू बिक्री को अनदेखा किया जा सकता है जहाँ मात्रा उचित तुलना की अनुमति देने के लिए अपर्याप्त है। दोनों स्वतंत्र आधार - ऑफ-ग्रेड गुणवत्ता और अपर्याप्त मात्रा - अलग-अलग सामान्य मूल्य के निर्माण को उचित ठहराते हैं। प्रकटीकरण विवरण में निष्कर्ष की पुष्टि की जाती है।

143. मूल्य अंडरकटिंग और मूल्य प्रभावों पर, प्राधिकरण अंतिम निष्कर्ष में निर्धारित मूल्य प्रभावों पर अपने निष्कर्षों की पुष्टि करता है। आयात की कीमतों में क्षति अवधि के दौरान लगभग

41% की गिरावट आई, जबकि कच्चे माल की कीमतों में केवल 17% की गिरावट आई। यह असमानुपातिक गिरावट स्थापित करती है कि आयात की कीमतों ने केवल फीडस्टॉक लागत आंदोलनों का अनुसरण नहीं किया है। विषय देशों में मूल्य अंडरकटिंग 7% से 16% तक है, जिसका भारित औसत 11% है। एक पतले मार्जिन वाले उद्योग के संदर्भ में, जहां जांच की अवधि के दौरान आयात की कीमतें घरेलू उद्योग की परिवर्तनीय उत्पादन लागत से भी नीचे गिर गईं, अंडरकटिंग का यह स्तर हानिकारक है। यह प्रस्तुति कि 10-11% अंडरकटिंग 'नाममात्र' है, स्वीकार नहीं की जाती है।

144. प्राधिकरण स्वीकार करता है कि जांच की अवधि के दौरान रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी ने सकारात्मक रुझान दिखाया है। हालाँकि, नियम 11 के साथ नियमों के अनुलग्नक II के तहत क्षति निर्धारण के लिए सभी प्रासंगिक आर्थिक संकेतकों की समग्र जांच की आवश्यकता होती है। रोजगार और मजदूरी में सकारात्मक गतिविधि उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग, लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में तीव्र गिरावट से कहीं अधिक है - ये सभी प्रमुख संकेतक हैं। घरेलू उद्योग ने गंभीर वित्तीय नुकसान को अवशोषित करते हुए अपने कार्यबल का विस्तार किया है, जो क्षति की अनुपस्थिति के बजाय क्षति के बावजूद लचीलापन प्रदर्शित करता है।

145. डाउनस्ट्रीम उद्योग पर प्रभाव के संबंध में, प्राधिकरण ने देखा है कि ईडीए डाउनस्ट्रीम उत्पादों की लागत का केवल एक छोटा सा अनुपात बनाता है, और 20% की काल्पनिक प्रतिप्रतिषेध शुल्क पर भी, तैयार उत्पादों की कीमतों पर प्रभाव न्यूनतम होगा। प्राधिकरण ने आगे कहा कि किसी भी डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ता ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि इस तरह की वृद्धि उसके परिचालन को अव्यवहारिक बना देगी। इसके अलावा, 2022-23 के दौरान डाउनस्ट्रीम उद्योग लाभदायक बना रहा, जब ईडीए आयात की कीमतें वर्तमान स्तरों से काफी अधिक थीं। तदनुसार, प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाने का डाउनस्ट्रीम उद्योग पर कोई भौतिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।
146. प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग का प्रति 1,000 किग्रा मैन्कोजेब में 250 किग्रा ईडीए का अनुमान असत्यापित है, और उसने उपयोगकर्ताओं के उपभोग डेटा को सत्यापन योग्य सीमा तक ध्यान में रखा है। उपयोगकर्ताओं द्वारा दावा किए गए उच्च ईडीए अनुपात पर भी, ईडीए मैन्कोजेब की उत्पादन लागत का केवल एक सीमित अनुपात बनाता है, और अनुशंसित स्तर पर प्रतिप्रतिषेध शुल्क का प्रभाव भौतिक नहीं है। 2022-23 के दौरान डाउनस्ट्रीम उद्योग लाभदायक बना रहा, जब आयातित ईडीए की लैंडेड कीमतें काफी अधिक थीं, प्राधिकरण का मानना है कि यह शुल्क के कारण उचित मूल्य सुधार को अवशोषित कर सकता है, और प्रतिकूल डाउनस्ट्रीम प्रभाव की आशंका सिद्ध नहीं है।

147. एकाधिकार जोखिम और आपूर्ति उपलब्धता पर, प्रतिप्रतिषेध शुल्क आयात को प्रतिबंधित या निषेधित नहीं करता है - यह केवल यह सुनिश्चित करता है कि आयात भारतीय बाजार में उचित, गैर-हानिकारक कीमतों पर प्रवेश करें। घरेलू उद्योग वर्तमान में अपनी स्थापित क्षमता के केवल 36% पर काम कर रहा है और उसके पास 37,350 मीट्रिक टन तक आगे क्षमता विस्तार के लिए आवश्यक मंजूरी है। प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग के लिए उत्पादन बढ़ाने, क्षमता विस्तार करने और घरेलू मांग के एक बड़े हिस्से की पूर्ति करने की स्थितियाँ पैदा होंगी। इस दावे का कोई आधार नहीं है कि प्रतिप्रतिषेध शुल्क से आपूर्ति की कमी या एकाधिकारी मूल्य निर्धारण होगा।

ठ. <u>निष्कर्ष</u>

148. हितबद्ध पक्षों द्वारा उठाए गए दावों, प्रदान की गई जानकारी और की गई प्रस्तुतियों तथा प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि उपरोक्त निष्कर्षों में दर्ज है, और डंपिंग, क्षति और घरेलू उद्योग से कारणात्मक संबंध के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण निम्नलिखित निष्कर्ष निकालता है:

क. विचाराधीन उत्पाद एवं समरूप वस्तु के दायरे पर

i. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 'एथिलीन डायमाइन' है, जिसे संक्षेप में "ईडीए" कहा जाता है।

ii. घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तु तथा विषय देशों से निर्यातित विषय वस्तुएं, नियमों के नियम 2(घ) के अर्थ में एक-दूसरे की समरूप वस्तुएं हैं।

ख. घरेलू उद्योग एवं पात्रता पर

i. आवेदक एकमात्र उत्पादक है जिसने जांच की अवधि के दौरान उत्पाद का उत्पादन किया है।

ii. बालाजी स्पेशियलिटी केमिकल्स लिमिटेड, नियम 2(ख) के अर्थ में एक पात्र घरेलू उद्योग है तथा नियमों के नियम 5(3) के संदर्भ में पात्रता की कसौटी को पूरा करता है।

ग. सामान्य मूल्य एवं निर्यात मूल्य पर

i. चीन पीआर, यूरोपीय संघ और सऊदी अरब के उत्पादकों ने वर्तमान जांच में भाग लिया है। ताइवान से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

ii. चीन पीआर को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाता है, क्योंकि चीन पीआर के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने नियमों के अनुबंध-I के पैरा 8 में उल्लिखित इस धारणा का खंडन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रदान नहीं किए हैं।

iii. चीन पीआर, यूरोपीय संघ और सऊदी अरब के उत्पादकों द्वारा दाखिल प्रतिक्रिया से पता चलता है कि उत्पाद का निर्यात भारत को डंपित कीमतों पर किया गया है।

iv. प्रत्येक विषय देश से विचाराधीन उत्पाद के लिए डंपिंग मार्जिन डी-मिनिमस से अधिक पाया गया है।

घ. क्षति एवं कारणात्मक संबंध पर

i. विषय देशों से आयात में निरपेक्ष एवं सापेक्ष दोनों रूपों में वृद्धि हुई है।

ii. जबकि आधार वर्ष की तुलना में कच्चे माल की कीमतों में 17 सूचकांक अंकों की गिरावट आई है, आयात मूल्य में 38 सूचकांक अंकों की गिरावट आई है।

iii. विषय आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को अंडरकट कर रहे हैं, और मूल्य अंडरकटिंग सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण है।

iv. जांच की अवधि में आयातों की लैंडेड कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतें अवसादित रहीं।

v. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग का उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग घटा। घरेलू उद्योग ने अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए नुकसान पर बिक्री की है।

vi. प्रति इकाई लाभ ₹66,592 प्रति मीट्रिक टन से घटकर ₹19,943 प्रति मीट्रिक टन का नुकसान हो गया है। घरेलू उद्योग का नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल इसी प्रकार 2022-23 में घटा और उसके बाद जांच की अवधि में ऋणात्मक हो गया।

vii. डंपित आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित किया है।

viii. जांच से विषय देशों से डंपिंग के अलावा कोई अन्य कारक सामने नहीं आया, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची हो।

ङ. भारतीय उद्योग के हित पर

i. घरेलू उद्योग भौतिक क्षति सहन कर रहा है, तथा प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाना घरेलू उत्पादक के हित में होगा।

ii. शुल्क लगाना सार्वजनिक हित के विरुद्ध नहीं होगा।

ड. <u>सिफारिशें</u>

149. प्राधिकरण नोट करता है कि जांच प्रारंभ की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षों को सूचित किया गया था तथा डंपिंग, क्षति, कारणात्मक संबंध और अनुशंसित उपायों के प्रभाव के पहलू पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने का घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षों को पर्याप्त अवसर दिया गया था। प्रतिप्रतिषेध नियमों के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार डंपिंग, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच प्रारंभ और संचालित करने के बाद, प्राधिकरण की राय है कि डंपिंग और क्षति की भरपाई के लिए प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाना आवश्यक है। प्राधिकरण इसे आवश्यक मानता है तथा विषय देशों से विषय वस्तुओं के आयात पर प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।

150. अनुसरण किए गए अल्पतर शुल्क नियम (लेसर ड्यूटी रूल) को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण विषय देशों में उत्पन्न या वहाँ से निर्यातित विषय वस्तुओं के आयात पर, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए, डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कम के बराबर अंतिम प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाने की सिफारिश करता है। तदनुसार, प्राधिकरण इसे आवश्यक मानता है तथा केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए, विषय देशों में उत्पन्न या वहाँ से निर्यातित विषय वस्तुओं के आयात पर, नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर प्रतिप्रतिषेध शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।

<u>शुल्क तालिका</u>

क्र. सं.	शीर्षक (HS Code)	विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई (मापन इकाई)	मुद्रा
1	29212100	एथिलीन डायमाइन	चीन	चीन सहित कोई भी देश	बीएएसएफ-वाईपीसी कंपनी लिमिटेड	350	मीट्रिक टन (एमटी)	अमेरिकी डॉलर ($)
2	-do-	-do-	चीन	चीन सहित कोई भी देश	क्र. सं. 1 में उल्लिखित उत्पादक के अतिरिक्त कोई भी उत्पादक	575	मीट्रिक टन (एमटी)	अमेरिकी डॉलर ($)

3	-do-	-do-	चीन, यूरोपीय संघ, सऊदी अरब और ताइवान के अतिरिक्त कोई भी देश	चीन	कोई भी उत्पादक	575	मीट्रिक टन (एम टी)	अमेरिकी डॉलर ($)
4	-do-	-do-	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ सहित कोई भी देश	बीएएसएफ एंटवर्पेन एनवी	464	मीट्रिक टन (एम टी)	अमेरिकी डॉलर ($)
5	-do-	-do-	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ सहित कोई भी देश	क्र. सं. 4 में उल्लिखित उत्पादक के अतिरिक्त कोई भी उत्पादक	739	मीट्रिक टन (एम टी)	अमेरिकी डॉलर ($)
6	-do-	-do-	चीन, यूरोपीय संघ, सऊदी अरब और ताइवान के अतिरिक्त कोई भी देश	यूरोपीय संघ	कोई भी उत्पादक	739	मीट्रिक टन (एम टी)	अमेरिकी डॉलर ($)

7	-do-	-do-	सऊदी अरब	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	सदारा केमिकल कंपनी	230	मीट्रिक टन (एम टी)	अमेरिकी डॉलर ($)
8	-do-	-do-	सऊदी अरब	सऊदी अरब सहित कोई भी देश	क्र. सं. 7 में उल्लिखित उत्पादक के अतिरिक्त कोई भी उत्पादक	375	मीट्रिक टन (एम टी)	अमेरिकी डॉलर ($)
9	-do-	-do-	चीन, यूरोपीय संघ, सऊदी अरब और ताइवान के अतिरिक्त कोई भी देश	सऊदी अरब	कोई भी उत्पादक	375	मीट्रिक टन (एम टी)	अमेरिकी डॉलर ($)
10	-do-	-do-	ताइवान	ताइवान सहित कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	301	मीट्रिक टन (एम टी)	अमेरिकी डॉलर ($)
11	-do-	-do-	चीन, यूरोपीय संघ, सऊदी अरब और ताइवान के	ताइवान	कोई भी उत्पादक	301	मीट्रिक टन (एम टी)	अमेरिकी डॉलर ($)

			अतिरिक्त कोई भी देश					

नोट 1 - ऊपर उल्लिखित सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है।

नोट 2 - उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित उत्पादकों के लिए निर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का आवेदन सीमा शुल्क प्राधिकारियों को एक वैध वाणिज्यिक चालान प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन होगा। उक्त चालान पर चालान जारी करने वाली इकाई के किसी अधिकारी द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित एक घोषणा अंकित होनी चाहिए, जिसमें अधिकारी का नाम और पदनाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो। घोषणा निम्नानुसार होगी:

"मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस चालान के अंतर्गत भारत को निर्यात हेतु बेची गई एथिलीन डायमाइन, जिसे संक्षेप में 'EDA' कहा जाता है, की (मात्रा) का निर्माण (उत्पादक का नाम और पता) द्वारा [संबंधित देश] में किया गया है। मैं घोषित करता/करती हूँ कि इस चालान में दी गई जानकारी पूर्ण एवं सही है।"

यदि ऐसा कोई चालान प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी उत्पादकों पर लागू शुल्क दर लागू होगी। यह आवश्यकता लागू सीमा शुल्क कानूनों और विनियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं को प्रभावित नहीं करेगी।

ढ. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

151. इस अंतिम निष्कर्ष से उत्पन्न प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अमिताभ कुमार
(निर्दिष्ट प्राधिकारी)

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 23-06-2026
18:06:50